फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी 12:22 उपरांत एकादशी विक्रम संवत 2082

एक सम्पूर्ण दैनिक अखबार

अमृत विचार

बरेली

www.amritvichar.com

2 राज्य | 6 संस्करण

लखनऊ बरेली कानपुर मुरादाबाद अयोध्या हल्द्वानी

गुरुवार, 12 फरवरी 2026, वर्ष 7, अंक 79, पृष्ठ 16 ■ मूल्य 6 रुपये

यूपी बजट 2026-27

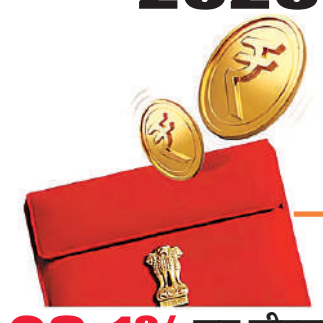

9.12 लाख करोड़ कुल बजट

19.5% पूंजीगत व्यय

12.4% शिक्षा आवंटन

6% स्वास्थ्य आवंटन

9% कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

23.1% ऋण-जीएसडीपी अनुपात लक्ष्य

योगी का बाहुबली बजट

नव निर्माण के **9** वर्ष

सुरेश कुमार खन्ना
वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश

अहम बातें

₹18,290 करोड़ से सिंचाई परियोजना

2100 नए राजकीय नलकूप

₹3,04,321 करोड़ से अधिक का गन्ना भुगतान

₹14,997 करोड़ चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए

₹37,956 करोड़ चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं। (आयुष्मान टॉप-अप 500 करोड़)

₹5,000 करोड़ से औद्योगिक विस्तार

₹3,822 करोड़ एमएसएमई के लिए

₹27,103 करोड़ अवसंरचना मद में

₹22,676 करोड़ नमामि गंगे/ग्रामीण जल मिशन

200 करोड़ एमओयू रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर के लिए

65,926 करोड़ ऊर्जा क्षेत्र को

बजटीय सौगात

49.86 लाख टैबलेट/स्मार्टफोन

₹400 करोड़ से मेधावी बेटियों को स्कूटी

10,000 युवाओं को नौकरी

₹1374 करोड़ से पुलिस भवन निर्माण

₹200 करोड़ फायर स्टेशन के लिए

₹25 करोड़ से महिला बीट कर्मियों के लिए वाहन

₹34,468 करोड़ सड़क-सेतु के लिए

₹225 करोड़ से एआई मिशन की शुरुआत

यूपी अब अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ बना राजस्व सरप्लस राज्य

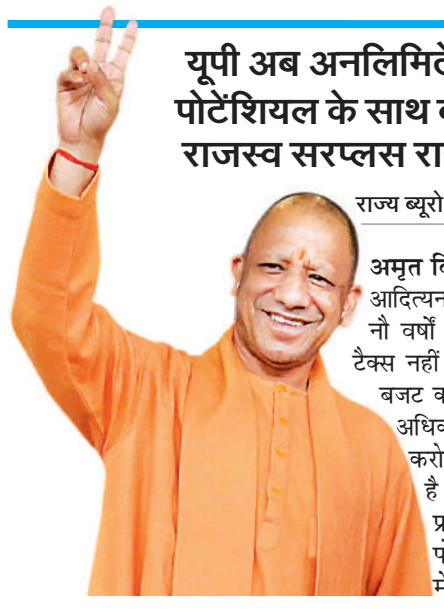

9 साल में कोई नया टैक्स नहीं, तीन गुना बढ़ा बजट : मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, फिर भी बजट का आकार तीन गुना से अधिक बढ़कर 9.12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब "अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट" के रूप में उभरा है और यह बजट उसी आत्मविश्वास का दस्तावेज है।

विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत होने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री योगी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह उनके नेतृत्व में सरकार का दसवां बजट है। उन्होंने बताया कि 43,565 करोड़ रुपये नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि दो लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) के लिए रखी गई है। उनका कहना था कि परिसंपत्तियों के निर्माण और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास से ही रोजगार सृजन को गति मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में प्रदेश में ऋण-जीएसडीपी अनुपात 30 प्रतिशत से अधिक था, जिसे घटाकर 27 प्रतिशत तक लाया गया। इस वित्तीय वर्ष में इसे 23 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की 30 प्रतिशत सीमा के भीतर रहते हुए उत्तर प्रदेश ने वित्तीय अनुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया है और आज प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है।

स्टेट डेटा अथॉरिटी का होगा गठन

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है। एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत एआई मिशन और डेटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना का प्रावधान किया गया है। स्टेट डेटा अथॉरिटी गठित की जाएगी, जो रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग के जरिए नीति निर्माण में मदद करेगी।

निवेश और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्रदेश में आए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी दूसरे स्थान पर पहुंचकर 'चीफ अचीवर स्टेट' बना है। डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना को आगे बढ़ाया जाएगा और सिटी इकॉनमिक जोन विकसित किए जाएंगे।

कृषि और ग्रामीण फोकस

बजट में 23 लाख डीजल ट्यूबवेल को सोलर से जोड़ने की घोषणा की गई है। एससी-एसटी, महिला और लघु सीमांत किसानों को 90 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। दो लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य। गन्ना, दलहन-तिलहन, मत्स्य और पशुपालन क्षेत्र में विशेष प्रावधान किए गए हैं। पशुधन बीमा योजना में 85 प्रतिशत तक प्रीमियम सरकार वहन करेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल हब

गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार, पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे और नए औद्योगिक क्लस्टर के लिए बजट में प्रावधान। हर जिले में स्किल डेवलपमेंट हब स्थापित किए जाएंगे। सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम इस बजट की मूल भावना है, जो उत्तर प्रदेश को देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।

यूपी बजट 2026-27 विधानसभा में पेश करने जाते मुख्यमंत्री योगी तथा वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना।

मेगा बजट

स्वच्छताकर्मियों को सीधे अकाउंट में मिलेंगे 16 से 20 हजार रुपये बजट में किया गया प्रावधान

बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय, शिक्षा-स्वास्थ्य और कृषि पर योगी सरकार का विशेष फोकस

नव निर्माण के नौ वर्ष की थीम पर 43,565 करोड़ की नई योजनाएं

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अमृत विचार : विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए "नव निर्माण के नौ वर्ष" थीम के तहत 43,565 .33 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का एलान किया। कुल बजट आकार 9,12,696 .35 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष से लगभग 12 .9 % अधिक। सरकार का कहना है कि यह बजट विकास, वित्तीय अनुशासन और भविष्य की तैयारी का संतुलित खाका है। एलान किया कि स्वच्छताकर्मियों को सीधे अकाउंट में 16 से 20 हजार रुपये मिलेंगे, इसका बजट में प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को बताया कि यह बजट राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता, निवेश के अनुकूल माहौल और सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन का परिणाम है। यह बजट न केवल राज्य की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है, बल्कि दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सतत विकास की स्पष्ट रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। बजट 2026-27 सरकार की उस सोच को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें विकास, वित्तीय अनुशासन और भविष्य की तैयारी तीनों को समान महत्व दिया गया है। इस बजट में अन्नदाता किसान, युवा, महिला, छात्र-छात्राओं समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को प्राथमिकता

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में 19 .5 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जो आधारभूत ढांचे, औद्योगिक विकास, सड़क, ऊर्जा और शहरी-ग्रामीण अधोसंरचना को नई गति देगा। पूंजीगत निवेश से रोजगार सृजन होगा और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। योगी सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों को बजट में प्रमुख स्थान दिया है। इसके अंतर्गत शिक्षा के लिए कुल बजट का 12 .4 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए 6 प्रतिशत और कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए 9 प्रतिशत का आवंटन किया गया है। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार मानव संसाधन विकास और किसानों की आय बढ़ाने को विकास की धुरी मानकर चल रही है।

19.5

प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान

राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की सीमा में

उन्होंने बताया कि 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह राजकोषीय अनुशासन से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा 1,18,480 .59 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2 .98 प्रतिशत है। यह 3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर है और वित्तीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। समग्र परिप्रेक्ष्य में, बजट 2026-27 में एक ओर जहां विकासोन्मुख नई योजनाओं का विस्तार है, वहीं दूसरी ओर राजस्व बचत और नियंत्रित राजकोषीय घाटे के माध्यम से वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का स्पष्ट प्रयास किया गया है।

शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कार्मिकों तथा पीएम पोषण योजना की रसोइयों एवं उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए 357 .84 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 89 .25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को निशुल्क सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्कूल उपस्थिति में सुधार की उम्मीद है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एआई प्रमाणन शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों के शिक्षा ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी के लिए 30 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना

वाराणसी रीजन चयनित

केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना में 7 रीजन की पहचान की गई है, जिनमें वाराणसी रीजन भी शामिल है। नीति आयोग की जनवरी 2026 की रिपोर्ट में काशी-विन्ध्य क्षेत्र को 'इकोनॉमिक हब' के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसमें 34 प्राथमिकता परियोजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, पर्यटन, विनिर्माण, ऊर्जा और आवास क्षेत्रों में समेकित विकास किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और एफपीओ को मजबूती

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किए जाने के मद्देनजर सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए रिवॉल्विंग फंड योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये का कोष नाबार्ड की सहभागी संस्था 'नैब किसान' के साथ मिलकर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें सरकार 75 करोड़ रुपये का अंशदान देगी। प्रत्येक पात्र एफपीओ को अधिकतम 50 लाख रुपये तक की ऋण सीमा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, यूपी एग्रीज के अंतर्गत प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ना है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत 38 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रदेश में 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बजट में स्वच्छताकर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके अकाउंट में सीधे 16 से 20 हजार रुपये भेजने का भी प्राविधान किया गया है। इसके लिए सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही स्कीम का फायदा स्वच्छताकर्मियों को मिलेगा।

ऋण प्रबंधन में योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि

वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2016-17 में राज्य को 29 .3 प्रतिशत ऋण-जीएसडीपी की अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे 2019-20 तक घटाकर 27 .9 प्रतिशत कर दिया गया। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण यह अनुपात वर्ष 2021-22 में बढ़कर 33 .4 प्रतिशत हो गया था, लेकिन सुनियोजित राजकोषीय प्रबंधन के चलते वर्ष 2024-25 में इसे पुन: 27 प्रतिशत से नीचे लाया गया है। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात को 23 .1 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य तय किया है। इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में इसे चरणबद्ध रूप से 20 प्रतिशत से नीचे लाने का संकल्प भी दोहराया गया है। इसका उद्देश्य राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित करना है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर

यूपी बजट में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं को आसान, ब्याज-मुक्त एवं चरणबद्ध पूंजी उपलब्ध कराकर 'लखपति दीदी' लक्ष्य को गति दी जाएगी। वहीं महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित सामान की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और बड़े बाजारों में महिलाओं द्वारा संचालित शोरूम व दुकानों की व्यवस्था की जाएगी, जिनका किराया शुरुआती तीन वर्षों तक राज्य सरकार वहन करेगी।

नई योजनाओं और सुदृढ़ वित्तीय संरचना की दिशा में बड़ा कदम

प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 43,565 .33 करोड़ रुपये की नई योजनाओं को शामिल किया है, जिनका उद्देश्य अधोसंरचना विकास, सामाजिक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और उत्पादक निवेश को गति देना है। यह प्रावधान राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य की कुल प्राप्तियां 8,48,233 .18 करोड़ रुपये अनुमानित की गई हैं। इसमें से राजस्व प्राप्तियां 7,28,928 .12 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत प्राप्तियां 1,19,305 .06 करोड़ रुपये निर्धारित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का बड़ा हिस्सा 6,03,401 .76 करोड़ रुपये है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 3,34,491 करोड़ रुपये तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,68,910 .76 करोड़ रुपये शामिल है। यह वित्तीय संरचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राज्य की आय में स्वयं के संसाधनों की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है, जिससे राज्य आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनता जा रहा है।

विधान सभा में यूपी बजट 2026-27 की प्रस्तुति का दृश्य।

श्रमजीवी महिला छात्रावास के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट

मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद और लखनऊ में निर्माण कार्य चल रहा है। अन्य जनपदों (अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर एवं मुरादाबाद) में विस्तार के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। जनमानस के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एसजीपीजीआई में क्वाटर्नरी हेल्थ केयर सुविधा प्रारंभ करने के लिए 359 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कैंसर मिशन के अंतर्गत हब एवं स्पोक मॉडल पर राज्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों तथा निजी क्षेत्र के समन्वय से कैंसर उपचार व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

यूपी एआई मिशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के तहत 'उत्तर प्रदेश एआई मिशन' (यूपीएआई मिशन) शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अगले तीन वर्षों में लगभग 2000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से लागू किए जाएंगे। इसके लिए 225 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। स्टेट डाटा सेंटर 2 .0 के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ नियोजन विभाग के अंतर्गत स्टेट डाटा अथॉरिटी की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 53 विभागों में 'जन विश्वास सिद्धांत' लागू किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

एमएसएमई और रोजगार को बढ़ावा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के तहत सरदार वल्लभभाई पटेल इंप्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना के लिए 575 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे स्थानीय खाद्य उत्पादों को पहचान और बाजार मिलेगा। इसके साथ ही, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश में फिल्म उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

बजट में पूंजीगत निवेश को विशेष प्राथमिकता

राज्य सरकार ने कुल 9,12,696 .35 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा है, जिसमें पूंजीगत निवेश को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसमें से 6,64,470 .55 करोड़ रुपये राजस्व लेखा व्यय तथा 2,48,225 .81 करोड़ रुपये पूंजी लेखा व्यय के रूप में निर्धारित किए गए हैं। पूंजीगत व्यय का यह उच्च स्तर राज्य में दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण, आधारभूत संरचना के विस्तार और आर्थिक गतिविधियों को गति देने की स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने बताया कि समेकित निधि की प्राप्तियों में से कुल व्यय घटाने पर 64,463 .17 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है। वहीं लोक लेखे से 9,500 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित की गई हैं। इन दोनों को समायोजित करने पर समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 54,963 .17 करोड़ रुपये ऋणात्मक आंका गया है, जो वित्तीय प्रबंधन के संतुलन की आवश्यकता को इंगित करता है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक शेष 96 .41 करोड़ रुपये ऋणात्मक को जोड़ने पर अंतिम शेष 55,059 .58 करोड़ रुपये ऋणात्मक अनुमानित है। एक सकारात्मक संकेत यह भी है कि राजस्व बचत 64,457 .57 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है, जो दर्शाता है कि राज्य की नियमित आय उसके नियमित व्यय से अधिक है और राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने में सहायता कर रही है।

डीजल से सोलर की ओर बड़ा कदम

बजट में विशेष रूप से कृषि विभाग के अंतर्गत डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की महत्वाकांक्षी योजना के लिए 637 .84 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों की डीजल पर निर्भरता कम होगी, लागत घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम कृषि क्षेत्र में हरित ऊर्जा संक्रमण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यूपी बजट 2026-27 : चुनावी वर्ष में विकास का संतुलित संदेश

विशेष टिप्पणी

● राजेश श्रीनेत

उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह चुनावी माहौल में भी विकास के एजेंडे को केंद्र में रखना चाहती है। विधान सभा में पेश यह बजट आकार में पिछले साल से लगभग 12.2 प्रतिशत बड़ा है और पूंजीगत व्यय को 19.5 प्रतिशत तक बनाए रखते हुए दीर्घकालिक आधारभूत संरचना निर्माण पर जोर देता है। राजनीति के नजरिये से देखें तो यह केवल आय व्यय का ब्यौरा नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं और चुनावी रणनीति का संकेत भी है।

चुनावी वर्ष के बजट अक्सर तात्कालिक राहत और लोकलुभावन घोषणाओं के लिए जाने जाते हैं, किंतु इस बजट में राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत की सीमा में रखने की प्रतिबद्धता वित्तीय अनुशासन का संदेश देती है। इससे लगता है कि सरकार विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहती है। निवेशकों के लिए यह संकेत महत्वपूर्ण है कि राज्य की वित्तीय सेहत नियंत्रित दायरे में है और बड़े बुनियादी प्रकल्पों के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में किए गए प्रावधान भी चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चिकित्सा शिक्षा के लिए उल्लेखनीय आवंटन, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्वास्थ्य बजट में वृद्धि ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास है। यह उन मतदाताओं के लिए संदेश है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में सुधार की अपेक्षा रखते हैं। युवा मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई मिशन के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। डिजिटल कौशल, स्टार्टअप संस्कृति और तकनीकी निवेश को बढ़ावा देना यह दर्शाता है कि सरकार नई पीढ़ी को अवसरों से जोड़ना चाहती है। टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण जैसी योजनाएं राजनीतिक दृष्टि से भी संवाद का माध्यम बनती हैं। हालांकि, युवाओं की अपेक्षाएं अब केवल उपकरणों से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण और स्थायी रोजगार के अवसरों पर केंद्रित हैं। इस दिशा में घोषित निवेश और संभावित रोजगार के आंकड़ों का धरातल पर क्रियान्वयन ही वास्तविक कसौटी होगा।

औद्योगिक विकास के क्षेत्र में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एमएसएमई प्रोत्साहन और निवेश नीति के लिए प्रावधान यह संकेत देते हैं कि सरकार राज्य को विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहती है। बड़े निवेश के समझौते और संभावित रोजगार सृजन के अनुमान चुनावी विमर्श में विकास आधारित राजनीति को बल देते हैं। फिर भी यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन परियोजनाओं का लाभ स्थानीय युवाओं और छोटे उद्यमियों तक कितनी तेजी से पहुंचता है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई विस्तार, फसल सघनता में वृद्धि और उत्पादन में बढ़ोतरी के आंकड़े ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती को रेखांकित करते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता में वृद्धि और सौर परियोजनाओं का विस्तार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संकेत है।

हालांकि आलोचनात्मक दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष में घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन की गति और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देना होगा। बड़े बजट का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा जब योजनाएं समयबद्ध ढंग से पूरी हों और लाभ लक्षित वर्गों तक पहुंचे। समग्र रूप से देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट विकास, निवेश और वित्तीय अनुशासन के संतुलन का प्रयास है। इसमें चुनावी संदर्भ की झलक अवश्य है, परंतु अत्यधिक लोकलुभावन रुख से बचते हुए दीर्घकालिक दृष्टि को सामने रखा गया है। मतदाता इस बात का मूल्यांकन करेंगे कि घोषित योजनाएं जमीन पर कितनी प्रभावी सिद्ध होती हैं। फिलहाल यह बजट विकास और विश्वास के संदेश के साथ चुनावी वर्ष की राजनीतिक पृष्ठभूमि को आकार देता हुआ दिखाई देता है।

केंद्रीय करों के हिस्सेदारी में से किसी राज्य का हिस्सा नहीं घटाया : सीतारमण-12

भारत-अमेरिका समझौते में संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरह संरक्षित : वाणिज्य सचिव-12

चीन ने कहा- आपसी मतभेदों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखे भारत-13

दक्षिण अफ्रीका की अफगानिस्तान पर दूसरे सुपर ओवर में रोमांचक जीत-14

आज का मौसम

24.0° अधिकतम तापमान

11.0° न्यूनतम तापमान

सूर्योदय 06.54

सूर्यास्त 05.59

एक सम्पूर्ण दैनिक अखबार

अमृत विचार

बरेली

www.amritvichar.com

2 राज्य | 6 संस्करण

लखनऊ बरेली कानपुर मुरादाबाद अयोध्या हल्द्वानी

फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी 12:22 उपरांत एकादशी विक्रम संवत 2082

गुरुवार, 12 फरवरी 2026, वर्ष 7, अंक 79, पृष्ठ 16 ■ मूल्य 6 रुपये

न्यूज ब्रीफ

उज्ज्वल निकम को नामित किए जाने पर याचिका दायर की

नई दिल्ली। कई हत्याओं के आरोपी गैंगस्टर विजय पलांडे ने बुधवार को अपने मामले में वकील उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नामित किए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। अपनी याचिका में पलांडे ने दलील दी कि राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित होने के कारण निकम इस मामले में एसपीपी नहीं रह सकते, क्योंकि यह लाभ के पद पर आसीन होने के बराबर होगा। निकम ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उन्हें कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से 16,000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा था।

भारतीय सेना से मिजोरम की साझेदारी, स्थानीय स्तर पर बढ़ेगी भर्ती

आइजोल। मिजोरम युवा आयोग (एमवाईसी) ने भारतीय सशस्त्र बलों में राज्य के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार को सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। एक अधिकारी ने बताया कि यहां एआरओ मुख्यालय में 'यंग मिजो एसोसिएशन' के अध्यक्ष मालसॉमजुआला राल्ते और एआरओ निदेशक कर्नल प्रकाश कुमार सिंह के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद इस सहयोग को अंतिम रूप दिया गया।

नरवणे की किताब पर जांच में शामिल होने के लिए पेंगुइन को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस जारी कर पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक को सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। यह नोटिस ऐसे समय में जारी किया गया जब पुस्तक की स्थिति और अनधिकृत संस्करणों के कथित अवैध प्रसार के विरोध में दावे किए जा रहे हैं जिससे प्रकाशक, पूर्व सेना प्रमुख और वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियां एक व्यापक सार्वजनिक विवाद में शामिल हो गई हैं।

योगी ने 10वीं बार बजट पेश कर इकलौते मुख्यमंत्री होने का रिकार्ड अपने नाम किया

प्रदेश का बजट-2026 पेश करने जाते मुख्यमंत्री योगी, साथ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना।

महाबजट @9.12 लाख करोड़

- विकास और वित्तीय अनुशासन का संतुलन निवेश, रोजगार और कल्याण पर फोकस
- उच्च शिक्षा की मेधावी बेटियों को मिलेगी स्कूटी सिंचाई, बीमा एवं मुफ्त बिजली पर भी जोर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : लोकलुभावन घोषणाओं के महाबजट के साथ बुधवार को मुख्यमंत्री योगी ने लगातार 10वीं बार बजट पेश कर इकलौते मुख्यमंत्री होने का रिकार्ड भी अपने नाम कर लिए। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का कुल आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है। इसमें विकास और वित्तीय अनुशासन का संतुलन दिखा। 10 लाख युवाओं को रोजगार, लड़कियों की शादी के लिए एक लाख रुपये समेत मेधावी बेटियों को स्कूटी के एलान से युवा मतदाताओं और सिंचाई, बीमा व मुफ्त बिजली से किसानों को साधने की कोशिश हुई है।

योगी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक का सबसे बड़ा 912696 करोड़ का बजट पेश किया। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में करीब 13 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय 19.5 प्रतिशत रखा गया है, जिससे साफ है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और दीर्घकालिक विकास पर बड़ा दांव खेल रही है। राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की सीमा में रखने और ऋण-जीएसडीपी अनुपात 23.1 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य वित्तीय अनुशासन का संकेत देता है। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, कौशल विकास और महिला सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश भाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, लड़कियों की शादी के लिए एक लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा भी की गई है। बजट में नौकरीपेशा, कामगार, व्यापारी-उद्यमी समेत सबके लिए राहत और तरक्की का पिटारा है। यह बजट चुनावी वर्ष से पहले सरकार का विकास और रोजगार केंद्रित रोडमैप माना जा रहा है, जिसमें निवेश और सामाजिक योजनाओं के संतुलन के जरिए व्यापक मतदाता वर्ग को साधने की कोशिश दिखती है। फोकस सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, मेडिकल शिक्षा, एमएसएमई, ऊर्जा, डिजिटल एवं एआई मिशन है। इसका विकसित यूपी @-2047 से तालमेल है।

महिलाओं के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र

बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए मिशन मोड में कौशल संवर्धन अभियान चलाने की घोषणा की है। पीपीपी मोड में कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और नए केंद्र खोले जाएंगे। निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास कौशल है, वह कभी बेरोजगार नहीं रह सकता। इसलिए युवाओं को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

एग्री-एक्सपोर्ट हब किए जाएंगे स्थापित

बजट में डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना लागू करने की घोषणा की गई है। खन्ना कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण में जनविश्वास सिद्धांत के आधार पर पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाएगा। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्री-एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 29वें स्थान से सुधरकर 18वें स्थान पर पहुंच चुकी है। फरवरी 2024 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हुए, जिनसे 10 लाख रोजगार सृजन की संभावना है। इनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ी 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हो चुके हैं।

लूटपाट और हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

कार्यालय संवाददाता, बदायूं

- 14 अक्टूबर 2018 की शाम नौकर ने अपने साथियों की मदद से की थी हत्या

अमृत विचार: शहर के उमेश जनरल स्टोर के मालिक की पत्नी की उनके ही नौकर और दो सहयोगियों ने लूट करके हत्या की थी। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र रिंकू ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 80-80 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा उमेश चंद्र रस्तोगी पुत्र स्व. कृष्ण कांति स्वरूप ने कोतवाली सिविल लाइन पुलिस को 14 अक्टूबर 2018 को तहरीर दी। जिसमें बताया कि उनकी पत्नी अरुणा रस्तोगी घर पर अकेली थी। बेटा नितिन और बहू पूजा एक समारोह में शामिल होने के लिए कासगंज के आगे मारहरा गए थे। उमेश चंद्र नौकरों के साथ दुकान पर थे। शाम लगभग छह बजे उनके घर पर काम करने वाली महिला प्रिया घर पर पहुंची। पत्नी को घर के फर्श पर घायल अवस्था में तपड़ते देखा तो बेटे और पुत्रवधू को फोन करके सूचना दी। उमेश चंद्र तुरंत घर पहुंचे तो उनकी पत्नी रसोइघर में खून से लथपथ पड़ी थीं। उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। इस दौरान घर के नौकर शिवम मौर्य और उसके साथ सोनू मौर्य व दिलीप मौर्य के नाम सामने आए। पुलिस ने 15 अक्टूबर को शिवम मौर्य और उसके साथियों की निशानदेही पर सोनू के मकान के कमरे के संदूक से एक काले रंग का बैग बरामद किया। जिसमें 20 लाख रुपये बरामद हुए। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू और जले हुए कपड़े बरामद किए।

न्यायालय में सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ा बुजुर्ग निवासी शिवम मौर्य पुत्र राधेश्याम मौर्या, दिलीप मौर्य पुत्र राम किशोर, सोनू मौर्य पुत्र सुरेश मौर्य पर लूटपाट और हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश बाबू शर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

समुद्र में क्रैश लैंडिंग

सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में समुद्र में एक यात्री विमान की क्रैश लैंडिंग होने से हड़कंप मच गया है। एडेन अब्दुले हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण पायलट को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी।

रामपुर सीआरपीएफ शिविर पर आतंकी हमला मामले में सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी

- उत्तर प्रदेश सरकार की हाईकोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को हुई सहमत
- 2007 के आतंकी हमले में चार आरोपियों को दी गई मौत की सजा कर दी गई थी निरस्त

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें 2007 के रामपुर सीआरपीएफ शिविर आतंकी हमले के मामले में चार आरोपियों को दी गई मौत की सजा और एक अन्य को दी गई आजीवन कारावास की सजा निरस्त कर दी गई थी। रामपुर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के शिविर पर 31 दिसंबर 2007 की रात को हुए हमले में सीआरपीएफ के आठ जवान मारे गए थे और पांच घायल हो गए थे।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर आरोपियों को नोटिस जारी किये और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की। पांचों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता एम एस खान पेश हुए। राज्य सरकार ने पिछले साल 29 अक्टूबर को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें इस मामले में चार लोगों को मृत्युदंड और एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय ने मोहम्मद शरीफ, सबाउद्दीन, इमरान शहजाद, मोहम्मद फारूक और जंग बहादुर खान को हत्या एवं अन्य गंभीर आरोपों से यह कहकर बरी कर दिया था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मुख्य अपराध के मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। हालांकि, इसने जंग बहादुर खान समेत पांचों को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-ए) के तहत दोषी पाया और उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जंग बहादुर खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा था, मामले का निस्तारण करने से पहले, हम निश्चित रूप से यह उल्लेख करना चाहेंगे कि यदि जांच और अभियोजन अधिक प्रशिक्षित पुलिस द्वारा किया गया होता तो इस मामले का परिणाम अलग होता।

राहुल के खिलाफ लाएंगे विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव

नई दिल्ली, एजेंसी

- संसदीय कार्य मंत्री रीजीजू बोले- राहुल गांधी के झूठे बयानों को सदन की कार्यवाही से हटाने का करेंगे अनुरोध

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में एक मंत्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए हैं इसलिए सरकार ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। रीजीजू ने बुधवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी का भाषण झूठ से भरा था और सत्तारूढ़ गठबंधन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा किये गए झूठे दावों को सदन की कार्यवाही से हटाए जाने का अनुरोध करेगा।

केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान राहुल के भाषण के तुरंत बाद, रीजीजू ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य आसन को एक नोटिस देंगे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष द्वारा बोले गए किसी भी कथन के प्रमाणीकरण की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने जो भी झूठ बोला है, हम उसे रिकॉर्ड से हटाए जाने की मांग करेंगे। हालांकि, राहुल गांधी ने अपने बयानों को प्रमाणित करने का वादा किया है, लेकिन मंत्री ने कहा, मुझे पता है कि वह उन्हें प्रमाणित नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सदन में झूठ बोला है। रीजीजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अक्सर जानबूझकर झूठ बोलते हैं और फिर संबंधित मंत्री का जवाब सुनने के बजाय सदन छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी का रुख यह है कि हम राहुल गांधी के झूठ का जवाब सदन के बाहर देंगे, लेकिन सदन के अंदर नोटिस जारी किया जाएगा। रीजीजू ने कहा कि राहुल ने बिना नोटिस दिए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर एक गंभीर आरोप लगाया है, जो विशेषाधिकार हनन है। उन्होंने कहा, हम आसन को आवश्यक सूचना देंगे।

पत्नी के सामने अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या

कार्यालय संवाददाता, रामपुर

- जिला पंचायत कार्यालय में हेड क्लर्क ने कहासुनी के बाद मारी गोली

अमृत विचार : जिला पंचायत के हेड क्लर्क ने लाइसेंसी पिस्टल से बुधवार को एक अधिवक्ता को उसकी पत्नी के सामने ही जिला पंचायत परिसर में गोली मार दी। घायल अधिवक्ता ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। पत्नी के वेतन कटौती को लेकर अधिवक्ता का बाबू से विवाद हुआ था।

नगर कोतवाली नालापार निवासी वकील फारुख अहमद खान (45) की पत्नी गौसिया जिला पंचायत कार्यालय में क्लर्क हैं। यहीं पर थाना पटवाई क्षेत्र के मिलक तहव्वुर गांव का रहने वाला असगर अली हेड क्लर्क है। बताया जाता है कि अधिवक्ता की पत्नी का कार्यालय में लेट आने के कारण वेतन काट लिया गया था। इसी संबंध में बुधवार को गौसिया के साथ उनके पति अधिवक्ता फारुख अहमद जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे। उन्होंने हेड क्लर्क असगर अली से इस विषय पर बात की।

इसी बीच दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। अचानक हेड क्लर्क ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अधिवक्ता पर तीन फायर झोंक दिए। अहमद तड़पकर गिर गए। गौसिया शोर मचाते हुए बाहर की ओर भागी। लोग अधिवक्ता को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

कनाडा में स्कूल में गोलीबारी, 10 लोगों की गई जान

वैंकूवर। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में टंबलर रिज सेकेंडरी स्कूल और एक मकान में हुई गोलीबारी की घटना में हमलावर सहित 10 लोगों की मौत हो गई। कनाडाई प्राधिकारियों ने बताया कि 25 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। लगभग 2,400 लोगों की आबादी वाला टंबलर रिज शहर वैंकूवर से 1,000 किलोमीटर उत्तर में अल्बर्टा की सीमा के पास स्थित है। टंबलर रिज सेकेंडरी स्कूल में सातवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के 175 छात्र पढ़ते हैं। अधीक्षक केन फ्लॉयड ने बताया कि जांचकर्ताओं ने हमलावर की पहचान कर ली है।

निर्देश

गृह मंत्रालय ने पहली बार राष्ट्रगीत गायन को लेकर प्रोटोकॉल तय किए

राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत के सभी छह छंद गाना जरूरी

नई दिल्ली, एजेंसी

- जब भी राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान गाया या बजाया जाएं तो राष्ट्रगीत पहले हो

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि जब भी राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' और राष्ट्रगान 'जन गण मन' एक साथ गाए या बजाए जाएं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए राष्ट्रगीत के सभी छह छंद पहले गाए जाएं। आदेश में मंत्रालय ने पहली बार राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के गायन को लेकर प्रोटोकॉल तय किए हैं।

जिसके तहत राष्ट्रपति के आगमन, तिरंगा फहराए जाने और राज्यपालों के भाषण जैसे आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के सभी छह छंद (कुल अवधि तीन मिनट 10 सेकंड) गाए जाएंगे। यह आदेश 28 जनवरी को जारी किया गया। आदेश में कहा गया, जब भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाए या बजाए जाएं, तो राष्ट्रगीत पहले गाया या बजाया जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जहां राष्ट्रगीत गाया जाएगा, वहां उपस्थित सभी लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा। इसमें कहा गया, जब भी राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण गाया या बजाया जाए, तो वहां मौजूद सभी लोगों को सावधान मुद्रा में खड़ा होना होगा लेकिन अगर किसी समाचार रील या वृत्तचित्र के दौरान राष्ट्रगीत फिल्म के हिस्से के रूप में बजाया जाए, तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं है क्योंकि इससे फिल्म दिखाने में रुकावट आएगी और सम्मान के बजाय अव्यवस्था एवं भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। मंत्रालय ने कहा कि विद्यालयों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन से की जानी चाहिए। केंद्र सरकार 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

छात्रों में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने के निर्देश

आदेश के अनुसार, राष्ट्रध्वज फहराने, सांस्कृतिक एवं औपचारिक कार्यक्रमों (परेड को छोड़कर), तथा किसी सरकारी या सार्वजनिक समारोह में राष्ट्रपति के आगमन जैसे अवसरों पर राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण सामूहिक गायन के साथ गाया या बजाया जाएगा। राष्ट्रगीत ऐसे अवसरों पर भी गाया जा सकता है, जो भले ही पूरी तरह औपचारिक समारोह न हों, लेकिन मंत्रियों आदि की मौजूदगी के कारण महत्वपूर्ण हों। ऐसे मौकों पर (वाद्य यंत्रों के साथ या बिना) राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन वांछनीय है। यह भी कहा कि उन सभी अवसरों की पूरी सूची देना संभव नहीं है, जहां राष्ट्रगीत का गायन किया जा सकता है लेकिन यदि मातृभूमि को सम्मान देने और उचित मर्यादा बनाए रखने के साथ राष्ट्रगीत गाया जाता है, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आदेश में विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान की भावना विकसित करें।

यूपी बजट 2026-27

दुग्ध विकास को बढ़ावा

- मथुरा में 30 हजार लीटर क्षमता की प्रस्तावित परियोजना को संशोधित कर 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का नया डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 23 करोड़ का प्रावधान है। 220 नई दुग्ध समितियों के गठन और 450 के पुनर्गठन के लिए 107 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

पशुधन संरक्षण

- प्रदेश के 7,497 गो-आश्रय स्थलों में 12 .38 लाख गोवंश संरक्षित हैं। छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 2,000 करोड़ तथा वृहद गो-संरक्षण केंद्रों के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित हैं। पशु रोग नियंत्रण हेतु 253 करोड़ और पशु चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण के लिए 155 करोड़ रखे गए हैं।

मत्स्य क्षेत्र में विस्तार

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 195 करोड़ (पुरुष घटक) और 115 करोड़ (महिला घटक) का प्रावधान है। एकीकृत एक्वा पार्क हेतु 190 करोड़ तथा अत्याधुनिक मत्स्य थोक बाजार व प्रसंस्करण केंद्र के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित हैं।

खाद्य एवं रसद

- खाद्य एवं रसद विभाग की योजनाओं के लिए 20,124 करोड़ का प्रावधान है। अन्नपूर्ति योजना हेतु 15,480 करोड़, नि:शुल्क एलपीजी रिफिलिंग योजना के लिए 1,500 करोड़ और अन्नपूर्णा भवन निर्माण के लिए 500 करोड़ रखे गए हैं।

उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण

- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए 2,832 करोड़ का प्रावधान है। राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के लिए 715 करोड़, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 478 करोड़ और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 के क्रियान्वयन के लिए 300 करोड़ रखे गए हैं।

प्रमुख प्रावधान

2,400 करोड़ रुपये निजी नलकूपों को निर्बाध बिजली के लिए

2,832 करोड़ रुपये उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण के लिए

100 करोड़ रुपये मत्स्य थोक बाजार/एक्वा पार्क/ प्रसंस्करण के लिए

2,000 छुट्टा गोवंश रखरखाव के लिए || **20,124** करोड़ रुपये खाद्य एवं रसद योजनाओं के लिए

किसानों पर मेहरबानी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि कृषि, मत्स्य, उद्यान, दुग्ध विकास, खाद्य-रसद पर खास फोकस है।

बजट में कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ रुपय का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 20% अधिक है। सरकार ने 2026-27 में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न और 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कृषकों के डीजल पंप सेट को सोलर पम्प में परिवर्तित करने के लिए 637.84 करोड़ रुपये खर्च करने का एलान किया गया।

637.84 करोड़ रुपये कृषकों के डीजल पंप सेट को सोलर पम्प में परिवर्तित करने के लिए

डीजल पंप से सोलर की ओर

- किसानों के डीजल पंप सेट को सोलर पंप में बदलने के लिए 637 .84 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए 298 करोड़ रखे गए हैं। निजी नलकूपों को निर्बाध बिजली आपूर्ति हेतु 2,400 करोड़ प्रस्तावित हैं।

एग्री-एक्सपोर्ट और यूपी एग्रीज

- यूपी एग्रीज परियोजना के तहत एग्री-एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ तथा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए 75 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड प्रस्तावित है। एक्वा कल्चर अवसंरचना के अंतर्गत विश्वस्तरीय हैचरी व प्रशिक्षण केंद्र के लिए 155 करोड़ की बाह्य सहायता परियोजना भी शामिल है।

51.82 लाख परिवारों को 100 दिन काम

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार : निवर्तमान योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने गांवों में जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार देने के साथ उनका शहर की तरफ पलायन रोका है। प्रतिवर्ष महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। लखनऊ की बात करें तो मनरेगा का दायरा छोटा है। फिर भी इस वर्ष 11 फरवरी तक 16 हजार परिवारों ने काम करके 6.15 लाख मानव दिवस सृजित किए हैं। 370 परिवार ने गारंटी के 100 दिन काम किए हैं।

वहीं, प्रदेश के आंकड़ों पर गौर करें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11 फरवरी तक प्रदेश में 21 करोड़ 92 लाख 17 हजार मानव दिवस सृजित हुए हैं। इनमें 51.82 लाख परिवार ने काम किया है। 1,60,152 परिवार को लगातार 100 दिन तक काम मिला है। इसमें महिलाओं की 41.31 फीसद भागीदारी है। अभी फरवरी और मार्च तक रोजगार का आंकड़ा और बढ़ेगा। पिछले वर्ष 2024-25 में मार्च तक 33 करोड़ 63 लाख 89 हजार मानव दिवस सृजित हुए थे, जबकि 65.26 लाख परिवारों ने काम किया था। उस समय महिलाओं की 41.87 फीसद भागीदारी रही है। जबकि 100 दिन गारंटी के 65.26 लाख परिवार ने काम किया था। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना विकसित भारत - जी राम जी ने नाम से संचालित होकर श्रमिकों को और सशक्त बनाएगी। इसमें पहले से अधिक बजट और 125 दिन काम के साथ कई प्राविधान किए गए हैं।

41.36 फीसद महिला श्रमिकों की रही भागीदारी वित्तीय वर्ष में

21.92 लाख मानव दिवस हुए सृजित प्रदेश में 11 फरवरी तक

यूं बढ़ीं महिला श्रमिक

2021	2022	30 .96
2022	2023	31 .75
2023	2024	42 .46

- गांव में काम मांगने पर मिला है। भुगतान भी समय से खाते में आता है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और भरोसा भी बढ़ा है। जी राम जी में अधिक फायदा है।

– **सुरेश चंद्र**, श्रमिक, टिकारी बीकेटी

- मनरेगा में काम मिलने पर गांव के बाहर नहीं गए। इसके साथ खेतीबाड़ी भी करते हैं। सही से भरण-पोषण हो जाता है। आगे और अधिक फायदे मिलेंगे।

– **प्रेमलाल**, श्रमिक, रामपुर देवरई बीकेटी

महिलाओं को सस्ती दर पर ऋण, आवास के साथ सामाजिक सुरक्षा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में महिला सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 11 प्रतिशत वृद्धि करते हुए कुल 18,620 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय भागीदारी को नई ऊंचाई देना है।

सरकार ने महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है, ताकि वे स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें। स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बजट में सफाई कर्मियों और निर्माण श्रमिकों को आवास उपलब्ध कराने की पहल भी शामिल है। इससे शहरी क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास सुविधा मिलेगी। बजट 2026-27 में महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं का विस्तार करते हुए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाने की स्पष्ट रणनीति पेश की है। यह बजट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा

- निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान।
- 2016-17 में लाभार्थी : 17 .32 लाख
- 2025-26 में लाभार्थी : 38 .58 लाख से अधिक
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 400 करोड़ की व्यवस्था।
- कामकाजी महिलाओं के छात्रावास निर्माण हेतु 100 करोड़।
- मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास निर्माण योजना के लिए 35 करोड़।

बच्चों के संरक्षण और पोषण पर जोर

- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़।
- मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत भवन निर्माण हेतु 80 करोड़।
- अनुपूरक पुष्टाहार कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1 .57 करोड़ लाभार्थियों को पोषण सहायता।

तकनीकी महाशक्ति की दिशा में कदम

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को विकास की नई धुरी बनाया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस सेक्टर के लिए 2,059 करोड़ का प्रावधान किया है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक है। बजट में एआई मिशन के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

30,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य डाटा सेंटर में

30,000 करोड़ के अनुमानित निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने और 900 मेगावाट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 8 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किए गए हैं, जिनमें 6 डाटा सेंटर पार्क और 2 डाटा सेंटर इकाइयां शामिल हैं। इनसे लगभग 21,342 करोड़ का निवेश और 644 मेगावाट क्षमता अर्जित की जा चुकी है।

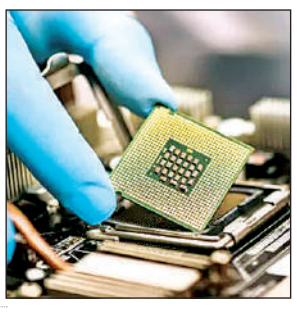

साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता

साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना को 95 .16 करोड़ का दिए गए हैं। पहले से संचालित 'एआई प्रज्ञा' कार्यक्रम के तहत माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, आईबीएम और वन एम वन बी जैसी कंपनियों के सहयोग से किसानों, स्वयं सहायता समूहों, विद्यार्थियों, चिकित्सकों और सरकारी कर्मियो को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में अग्रणी

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है। देश के कुल मोबाइल उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है। भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां भी यहीं स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़कर 44,744 करोड़ तक पहुंच गया है।

बढ़ेगी शिक्षा की गुणवत्ता

अमृत विचार, लखनऊ : वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में योगी सरकार ने शिक्षा को विकास की केंद्रीय धुरी बनाते हुए व्यापक प्रावधान किए हैं।

बेसिक से लेकर उच्च, प्राविधिक और कौशल विकास तक हर स्तर पर उल्लेखनीय बढ़ोतरी कर प्रदेश को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा, कौशल और तकनीकी प्रशिक्षण पर अभूतपूर्व निवेश कर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नया उत्तर प्रदेश ज्ञान, नवाचार और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के मजबूत आधार पर ही निर्मित होगा।

- **बजट 2026-27 में ज्ञान और कौशल पर सबसे बड़ा निवेश**

पढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे

बेसिक शिक्षा

- बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- कक्षा 1–8 के विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म, बैग, जूते, मोजे व स्टेशनरी हेतु 650 करोड़।
- 75 जनपदों में 2-2 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय।
- आवासीय बालिका विद्यालय विस्तार के लिए 580 करोड़।
- कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा : 358 करोड़।
- स्मार्ट स्कूल योजना : 300 करोड़।
- सहायता प्राप्त विद्यालयों के अनुरक्षण हेतु 300 करोड़।

माध्यमिक शिक्षा

- माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ (15% वृद्धि)।
- राजकीय विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु 520 करोड़।
- सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए 10 करोड़।
- संस्कृत पाठशालाओं की छात्रवृत्ति : 20 करोड़।
- ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर : 150 करोड़।
- शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा : 89 .25 करोड़।
- छात्राओं हेतु नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन : 300 करोड़।
- गोरखपुर में दूसरे सैनिक स्कूल का संचालन आरंभ।

उच्च शिक्षा

- उच्च शिक्षा के लिए 6,591 करोड़ (7% वृद्धि)।
- रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना : 400 करोड़
- मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन : 40 करोड़

नए विश्वविद्यालयों हेतु आवंटन

- मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर– 50 करोड़
- गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद– 50 करोड़
- मां पटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर– 50 करोड़
- स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय शाहजहांपुर– 21 करोड़
- काशी नरेश विवि भदोही – 21 करोड़
- मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण : 14 .5 करोड़।
- एआई प्रमाणन शुल्क प्रतिपूर्ति :10 करोड़
- मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना : 30 करोड़

व्यावसायिक शिक्षा

- व्यावसायिक शिक्षा बजट में 88% वृद्धि, कुल 3,349 करोड़। शिक्षा बजट में 72% वृद्धि, कुल 2,365 करोड़।
- 286 राजकीय आईटीआई 1 .90 लाख सीटें।
- 2,963 निजी आईटीआई 4 .58 लाख सीटें।
- 47 आईटीआई में महिला शाखाएं 12 महिला आईटीआई स्वतंत्र।
- टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से 149 आईटीआई उन्नत 62 और प्रगति पर।
- कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण व्यय : 1,000 करोड़।
- दस्तकार प्रशिक्षण योजना : 836 करोड़
- प्रोजेक्ट प्रवीण : 500 करोड़।
- मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण : 20 करोड़

हरियाली पर जोर

सामाजिक वानिकी व रोपण

- सामाजिक वानिकी योजना : 800 करोड़
- पौधशाला प्रबंधन योजना : 220 करोड़
- राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण योजना : 189 करोड़

रानीपुर बांध फाउंडेशन

- रानीपुर बांध से जुड़े रानीपुर बांध फाउंडेशन, चित्रकूट के कॉर्पस फंड गठन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

स्वच्छ वायु

- उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (2025-26 से 2030-31) : 194 करोड़
- यह विश्व बैंक सहायतित बहु-क्षेत्रीय योजना है।

अपशिष्ट निस्तारण

- सामूहिक जैव-चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सुविधा
- ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग एवं उपचार सुविधा की स्थापना की कार्यवाही

प्राविधिक शिक्षा

- प्राविधिक शिक्षा बजट में 72% वृद्धि, कुल 2,365 करोड़।
- 195 डिप्लोमा संस्थान संचालित
- 23 नए पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन।
- उत्कृष्टता केंद्र व उन्नयन : 714 करोड़।
- स्मार्ट कक्षाएं (251 स्थापित, 143 प्रक्रियाधीन)।
- अवसंरचना विकास : 254 करोड़।
- नए पॉलिटेक्निक : 50 करोड़।

प्रतिक्रियाएं | विशेषज्ञ बोले- डिजिटल कक्षाएं, आवासीय व्यवस्था और कैशलेस चिकित्सा से प्राथमिक शिक्षा का होगा कायाकल्प

ज्ञान, विज्ञान और नवाचार को मिलेगी उड़ान

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: उत्तर प्रदेश का बजट 2026-27 में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बजट में पिछले वर्षो की तुलना में बढोत्तरी की गई है, जिसका शिक्षाविदों और अर्थशास्त्र के जानकारों ने स्वागत किया है। बजट में प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष फोकस किया गया है।

बजट प्रस्तावों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के ढांचे में व्यापक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी के साथ प्राविधिक और औद्योगिक शिक्षा में सरकार के नए प्रयोग, नवाचार और इंडिया एआई मिशन युवाओं को समर्पित है।

अर्थव्यवस्था को गति देगा यह बजट

- बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को गति को देने वाला विकासोन्मुखी बजट है। युवाओं के कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण योजनाओं, एवं प्रोत्साहन योजनाओं से उनकी सामाजिक आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी, जिससे निसंदेह कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। साथ ही कार्यरत महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधाएं महिला सुरक्षा की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम हैं। पूंजीगत व्यय में वृद्धि से निवेश बढ़ेगा, जो रोजगार सृजन में सहायक होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति की नई योजना एक अच्छी पहल है जिससे ड्राप आउट रेट भी कम होगा।

–**प्रो. पूनम वर्मा**, अर्थशास्त्र विभाग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय

'सप्लाई-साइड इकोनॉमिक्स' की ओर झुकाव

- बजट केवल व्यय का ब्योरा मात्र नहीं है, बल्कि 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक 'मैक्रो-इकोनॉमिक रोडमैप' है। यह बजट स्पष्ट रूप से 'सप्लाई-साइड इकोनॉमिक्स' की ओर झुकाव दर्शाता है, जहां सरकार का प्राथमिक दर्शन 'इंफ्रास्ट्रक्चर से एम्प्लॉयमेंट' के बहुआयामी प्रभाव पर आधारित है। पूंजीगत व्यय और ढांचागत प्रोत्साहन बजट का लगभग 19 .5% हिस्सा आवंटित करना एक साहसिक आर्थिक निर्णय है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयों में 55% की राष्ट्रीय हिस्सेदारी एक रणनीतिक कदम है। बजट में कौशल विकास के लिए पीपीपी मॉडल का प्रस्ताव 'ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन' की आवश्यकता को रेखांकित करता है। औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं की भागीदारी प्रगतिशील पहल है।

–**डॉ. अनामिका चौधरी**, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

संतुलित और स्वागत योग्य बजट

- प्रस्तुत बजट आम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप है। शिक्षा के प्रत्येक मद में वृद्धि की गई है। इससे उत्तरप्रदेश का युवा अधिक ज्ञान और कौशल सम्पन्न होगा जिससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ वह सम्मन्न भी होगा। महिलाओं के कौशल विकास केंद्रों को विकसित करना आगामी चुनाव को देखते हुए घोषणा है। यह बजट सभी क्षेत्र की जरुरतों को पूरा करने वाला संतुलित बजट है।

–**डॉ. पीयूष कुमार त्रिवेदी**, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

विकसित उत्तर प्रदेश का बजट है यह

- पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यह लगभग 12 .9 प्रतिशत अधिक है। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए 'विकसित उत्तर प्रदेश' पर फोकस करता है। बजट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सीएम युवा उद्यमी योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गई है। साथ ही 40 लाख युवाओं को टैबलेट बांटने का भी प्रावधान है। जिसके लिए 575 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ओडीओसी (एक जिला एक व्यंजन) योजना लागू की गई है। राजकोषीय-जीएसडीपी अनुपात को अनुकूलतम 3 प्रतिशत पर रखा गया है।

–**प्रो. भारती पाण्डेय**, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, श्रीजयनारायण पीजी कॉलेज

धुआं न शोर, इको फ्रेंडली ई-बसें बढ़ाने पर जोर

पर्यावरण की 'मित्र' इलेक्ट्रिक बसों की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी, बस स्टेशनों पर बनेंगे चार्जिंग प्वाइंट

नीरज मिश्र, लखनऊ

अमृत विचार: न धुआं होगा और न ही शोर, इको फ्रेंडली ई-बसों के बढ़ाने पर इस बार सरकार का जोर। प्रदेश सरकार ने प्रदूषण पर गंभीर पहल करते हुए पर्यावरण के 'मित्र' इलेक्ट्रिक बसों की रफ्तार को और बढ़ाने का अपना विजन साफ कर दिया है। बजट में तात्कालिक लाभ से इतर दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उप्र. राज्य सड़क परिवहन निगम को 550 करोड़ का बजट आवंटित कर दिया है। इससे न केवल इलेक्ट्रिक बसों का कुनबा बढ़ेगा, बल्कि उनके करंट का भी ठोस इंतजाम करने पर अपनी मुहर लगा दी है। ई-बसों और ई-वाहनों को भविष्य मानते हुए सरकार न केवल गाड़ी के पंजीकरण में छूट बल्कि क्रय सब्सिडी तक में रियायत दे रही है। इसकी समय सीमा तक बढ़ा दी गई है। और तो और प्रदेश में ई-वाहनों की निर्माता कंपनियों के लिए भी विशेष तरह के छूट के पैकेज जारी किए जा चुके हैं।

400 करोड़ से खरीदी जाएंगी ई-बस

परिवहन निगम के बेड़े के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट में 400 करोड़ रुपये मिले हैं। इस आवंटित धनराशि से इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी। इसका प्रयोग अन्यत्र नहीं किया जा सकेगा। सिर्फ ई-बसें की कुनबे में शामिल की जाएंगी।

रोडवेज बेड़े में अभी 220 ई-बसें

परिवहन निगम के पास अब तक 220 ई-बसें आ गई हैं। यह बसें करीब 9 स्थानों पर चल रही हैं। इनमें प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बाराबंकी, गोरखपुर, आगरा, मुरादाबाद, साहिबाबाद, नोएडा आदि शहरों में चल रही हैं। नई मिली धनराशि से ई-बसों की फ्लीट मजबूत और बड़ी होगी।

बस स्टेशनों पर 150 करोड़ से बनेंगे चार्जिंग स्टेशन

बजटीय प्रावधान में इन बसों के ईंधन यानी ई-करंट की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है। बस स्टेशन निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इनसे रोडवेज प्रबंधन बस अड्डों पर ई-चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करेगा। यही नहीं सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनमें से 50 करोड़ का आवंटन जीरो फैटलिटी के लिए उपलब्ध कराया गया है। "मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा विजन योजना" के अंतर्गत दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं दुर्घटना के पश्चात त्वरित कार्रवाई के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रदेश बजट में परिवहन विभाग के प्रावधानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का आभार जताया है।

-दयाशंकर सिंह, परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

बजट में नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने, बस अड्डों के निर्माण एवं चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए दिए गए 600 करोड़ के लिए संगठन राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता है। इलेक्ट्रिक बसें बढ़ने से परिवहन निगम की रफ्तार और तेज होगी। संगठन का कहना है कि परिवहन निगम में दशकों से कार्यरत संविदा चालकों-परिचालकों व आउटसोर्स कर्मियों के चरणबद्ध नियमितीकरण पर भी निर्णय कराने की कृपा करें। **-गिरीश चंद्र मिश्र, महामंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उप्र.**

हर मंडल में खेल महाविद्यालय 2032-36 ओलंपिक लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- **ग्रीनपार्क का पुनर्विकास, मेरठ खेल विश्वविद्यालय को 170 करोड़**
- **403 विधानसभा व 80 संसदीय क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिता के लिए 20 करोड़**

अमृत विचार: वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रदेश के खेल ढांचे को नई दिशा देने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि प्रत्येक मंडल में एक खेल महाविद्यालय स्थापित कर उसे उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि वर्ष 2032 और 2036 ओलंपिक को लक्ष्य बनाकर खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रति विधानसभा 3 लाख रुपये और 80 संसदीय क्षेत्रों में प्रति क्षेत्र 10 लाख रुपये की दर से सांसद/विधायक खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय, मेरठ के नवीन भवन निर्माण एवं विकास कार्य के लिए 80 करोड़ रुपये, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए 30 करोड़ रुपये तथा शैक्षणिक व खेल गतिविधियों के संचालन के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल 170 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान नई मांग के माध्यम से किया जा रहा है।

कानपुर स्थित ग्रीनपार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के उच्चीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है, जिससे स्टेडियम का पुनर्विकास कर उसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराएं और उत्तर प्रदेश खेल प्रतिभा का नया केंद्र बने। वर्तमान में गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज और सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज हैं।

श्रमिकों की उन्नति पर जोर, रोजगार मिशन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में योगी सरकार ने श्रमिकों और असंगठित कामगारों के कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में बताया कि उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के श्रमिकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

बजट 2026-27 में रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से श्रमिक परिवारों को सशक्त बनाने का स्पष्ट रोडमैप दिखाई देता है, जो प्रदेश में श्रम आधारित विकास मॉडल को मजबूती देने की दिशा में निर्णायक कदम है। सरकार ने घर से दूर शहरों में कार्यरत मजदूरों के लिए लेबर अड्डों के निर्माण की घोषणा की है, ताकि उन्हें सुरक्षित, संगठित और सुविधायुक्त कार्यस्थल मिल सके। इसे प्रवासी श्रमिकों

70 करोड़ रुपये अटल आवासीय विद्यालयों में श्रमिकों के बच्चों के लिए

8.41 करोड़ कामगारों को फैमिली आईडी, लेबर अड्डों का निर्माण

के श्रम प्रबंधन और सुविधा विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

शिक्षा और स्वास्थ्य से सशक्तिकरण

श्रमिक परिवारों के सामाजिक उत्थान के लिए अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। वर्तमान में इन विद्यालयों में 10,876 श्रमिक बच्चों का नामांकन है। इस योजना के लिए 70 करोड़ की व्यवस्था की गई है। निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए पहली बार मोबाइल हेल्थ वैन पायलट परियोजना के रूप में संचालित की गई है। एक्स-ग्रेशिया अनुदान के तहत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख तथा आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख की सहायता का प्रावधान जारी रखा गया है।

8.41 करोड़ कामगारों को फैमिली आईडी

वित्त मंत्री ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8.41 करोड़ कामगारों को फैमिली आईडी से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लक्षित क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। डिजिटल पहचान के माध्यम से श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड से आधी आबादी को संबल

स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा और दिव्यांगजन कल्याण के साथ विकास का व्यापक खाका

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट 2026-27 की प्रमुख उपलब्धियां बताते हुए कहा कि यह बजट महिलाओं, युवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन और दिव्यांगजन कल्याण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से महिलाओं को ब्याज-मुक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे छोटे उद्यम शुरू कर सकें। इसके साथ ही महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना लागू की जाएगी, जो केंद्रीय स्तर की सी-मार्ट अवधारणा की तर्ज पर कार्य करेगी। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है। प्रत्येक जिले में श्रमजीवी महिला छात्रावास के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है, जिससे कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास मिल सके।

दिव्यांग छात्राओं के लिए ई-ट्राइसाइकिल, डीडीआरसी केंद्र, कृत्रिम अंग वितरण केंद्र तथा 3-7 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, झांसी, मेरठ और आगरा में विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे।

पीपीपी मॉडल पर 1 लाख अतिरिक्त होटल कक्ष

प्रदेश में 2024-25 में 122 करोड़ पर्यटकों के आगमन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने पीपीपी मॉडल पर 1 लाख अतिरिक्त होटल कक्ष और 50,000 होम-स्टे विकसित करने की घोषणा की। महिला गाइडों के लिए लाइसेंस शुल्क माफ किया जाएगा।

एसपीजीआई में खुलेगा देश का पहला क्वाटर्नरी हेल्थ केयर सेंटर

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में 36 मेडिकल कॉलेज थे, अब 81 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स संचालित हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5.46 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। एसपीजीआई में देश का पहला क्वाटर्नरी हेल्थ केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए प्रथम चरण में 250 करोड़ का प्रावधान है। यह विशेष रूप से अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम होगा। मेडिकल कॉलेजों में छात्रावास निर्माण, सड़क सुरक्षा और ट्रॉमा सेंटर सुदृढ़ीकरण के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडटेक (मेडिकल टेक्नोलॉजी) के अंतर्गत एआई और रोबोटिक तकनीक को जोड़ा जाएगा। वर्तमान में दो उत्कृष्टता केंद्र एक एसजीपीजीआई और दूसरा आईआईटी कानपुर के सहयोग से संचालित को भी बजट में समर्थन दिया गया है।

युवाओं और खेल के लिए ऐतिहासिक पहल

"वन डिस्ट्रिक्ट, वन कमिश्नरी, वन डिविजनल मुख्यालय, वन स्पोर्ट्स कॉलेज" की परिकल्पना के तहत 18 मंडल मुख्यालयों पर स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्पोर्ट्स कालेज मेरठ अप्रैल-मई तक पूर्ण रूप से संचालित होगी। इन कॉलेजों को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 ओलंपिक की तैयारी के दृष्टिकोण से उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम, मिनी स्टेडियम और खेल मैदान विकसित किए जाएंगे।

दोगुनी आय और घटती बेरोजगारी का किया दावा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

वित्त मंत्री का बजट भाषण

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

अमृत विचार: वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट अनुमानों पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सर्वांगीण विकास को प्रमुखता से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से लेकर अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, महिला सशक्तीकरण, युवाओं के कौशल संवर्धन, किसानों की खुशहाली और गरीबी उन्मूलन तक व्यापक बदलाव दर्ज किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूती की ओर अग्रसर है। वर्ष 2024-2025 (त्वरित अनुमान) में राज्य की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपये आंकी गई है, जो वर्ष 2016-2017 की 54,564 रुपये प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले दोगुने से अधिक है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि वर्ष 2025-2026 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपये होने का अनुमान है। सरकार ने लगभग छह करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है, जबकि बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने दावा किया कि आर्थिक वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार और निवेश-आधारित विकास मॉडल के चलते उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।

निवेश, निर्यात और नवाचार

अमृत विचार, लखनऊ: वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट अनुमानों पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति को विस्तार से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग वर्ष 2018-2019 में 29वें स्थान पर थी, जो बेहतर होकर वर्ष 2023-2024 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि फरवरी 2024 में आयोजित चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट ने निवेश के नए कीर्तिमान स्थापित किए। अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार सृजन की संभावना है। इनमें से करीब 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ी 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के चार ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह संपन्न हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश में निर्मित होता है। साथ ही, भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां भी प्रदेश में स्थित हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ-साथ नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग में "लीडर श्रेणी" का दर्जा प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि निवेश, विनिर्माण और नवाचार के इस त्रिकोणीय मॉडल ने प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में खड़ा कर दिया है।

भाजपा सरकार का आखिरी और विदाई बजट : अखिलेश

अमृत विचार, लखनऊ: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि यह भाजपा सरकार का आखिरी और विदाई बजट है। भाजपा जनता से किये वादों को भूल गयी। भाजपा जनता की भावनाओं से खेलती है। बजट में गरीबों, किसानों, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। बजट का आकार बड़ा है, मगर न तो मंहगाई कम हुई और न ही बेरोजगारी खत्म हुई। सपा प्रमुख बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार में बैठे लोग अयोग्य है, सरकार बजट खर्च नहीं कर पाती है। अभी तक पिछले बजट का 50 फीसदी भी नहीं खर्च कर पाई है। सरकार वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का सपना दिखाती है। उन्होंने कहा कि ट्रिलियन डालर इकोनामी के लिए जीएसडीपी 90 लाख करोड़ की होनी चाहिए और ग्रोथ रेट 30 फीसदी होनी चाहिए। जब आखिरी बजट पेश कर दिया तो 90 लाख करोड़ की जीएसटडीपी कहां से बनाएंगे।

बजट का आकार और तुलना

- **कुल बजट : 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ 35 लाख रुपये**
- **कुल प्राप्तियां: 8.48 लाख करोड़**
- **राजस्व प्राप्तियां: 7.29 लाख करोड़**
- **कुल व्यय: 9.13 लाख करोड़**
- **राजस्व व्यय: 6.64 लाख करोड़**
- **पूंजीगत व्यय: 2.48 लाख करोड़**

नई योजनाओं की भरमार

- **सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन**
- **बायोप्लास्टिक औद्योगिक नीति-2024**
- **वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति**
- **मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना**
- **महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना**
- **पशुधन बीमा एवं जोखिम प्रबंधन योजना**
- **सहकारी चीनी मिलों का आधुनिकीकरण**
- **ड्रीम स्किल लैब**
- **नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय**
- **छात्राओं के लिए प्रत्येक जनपद में छात्रावास**
- **टेक युवा-समर्थ युवा योजना**
- **चार सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (पीपीपी मोड)**
- **ट्रॉमा सेंटर लेवल-2**
- **चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्रावास**
- **उत्तर प्रदेश एआई मिशन**
- **स्टेट डेटा सेंटर**
- **डेटा सेंटर क्लस्टर**
- **यू-हब की स्थापना**
- **'ग्रीन' और 'पिंक' बजट पर फोकस**

बजट विकसित भारत की संकल्पनाओं को समर्पित

अमृत विचार, लखनऊ : विधान परिषद में बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को उप मुख्यमंत्री व नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के 2026-27 के बजट प्रावधानों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत की संकल्पनाओं को समर्पित बजट है। जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। इसमें नारीशक्ति, किसानों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों का खयाल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आवंटित बजट का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाये गये हैं। युवाओं को रोजगार देने, किसानों व आम जनता की खुशहाली के लिये संतुलित बजट है। बजट में ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के लिए 25,550 करोड़ रुपये, इनमें मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए क्रमशः 5,544 करोड़ रुपये एवं 4580 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

विशेष टिप्पणी | लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रो. मनोज अग्रवाल ने बजट को बताया संतुलित

प्रदेश के समग्र विकास का प्रगतिगामी बजट

यह बजट चुनावी बजट होते हुए भी प्रगति का बजट है और दीर्घकालीन रणनीति वाला बजट है। सबसे बड़ी बात की इसमें संतुलन रखा गया है। बजट घाटे को सीमित दायरे में रखा गया है, 2.98 प्रतिशत जो 3 प्रतिशत से नीचे है। इसके अलावा राजस्व व्यय को सीमित रखते हुए राजस्व आय बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। जिसके कारण हमारा पूंजीगत परिव्यय राज्य आय का 4.5 प्रतिशत हो गया है। यह आज से 9 साल पहले 3 प्रतिशत से काफी कम था। इसका लाभ यह हो रहा है कि जब विधि व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, डिजिटल चीजें अच्छी होने के साथ गर्वनेंस में सुधार हुआ है। इसके अलावा इज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हुआ है। सरकारी निवेश और आधारभूत संरचना बढ़ने से विदेशी निवेश के साथ घरेलू निवेश तेजी से बढ़ा है। जो इंवेस्टर समिट में दिखाई भी दिया।

प्रो. मनोज अग्रवाल, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

दूसरा, यह बजट युवाओं की संभावना वाला और महिलाओं के विकास वाला है। व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का बजट काफी बढ़ाया गया है, इसी के साथ आईटी सेक्टर और इलेक्ट्रानिक का बजट बढ़ाया गया है। दोनों का तालमेल करके लैब बनाया जाना है, एआई का लैब, डेटा सेंटर के लिए 30 हजार करोड़ के 6 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। यह सारी चीजें उत्तर प्रदेश को काफी आगे ले जाएंगी। कृषि में 20 प्रतिशत, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर 30 प्रतिशत बजट बढ़ा है, इसी प्रकार पंचायती राज में बहुत ज्यादा बजट बढ़ाया गया है। खेती को आधुनिक करने के लिए डीजल पम्पिंग सेट की जगह सोलर पम्पिंग सेट को बढ़ावा देना, सड़क बनाना, पुलिया आदि के अवस्थापना के लिए पर्याप्त बजट है। केंद्र सरकार के साथ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से जो प्रस्ताव पास हुआ है। जिससे हमारा टैक्सटाइल का निर्यात बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मित्र टैक्सटाइल पार्क योजना के तहत पार्क बनेगा। जिसका लाभ उठाते हुए हथकरघा और वस्त्र उद्योग का बजट 5 गुना कर दिया गया है, जिससे टैक्सटाइल सेक्टर में हमारा निर्यात बढ़ सके। इसी तरह एमएसएमई सेक्टर, अवस्थापना, उद्योग जगत का बजट भी बढ़ाया गया है। माइक्रो यूनिट में एक लाख लोगों को गारंटीमुक्त व ब्याज मुक्त ऋण देने की बात है, जिससे वह अपना व्यवसाय लगा सकें। युवाओं के प्रशिक्षण पर, मेडिकल एजुकेशन पर या मेडिकल सीट में जो बढ़ोत्तरी हुई है। उससे युवाओं के कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उनके रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही है। यह सारी चीजें प्रगतिगामी हैं।

● अमृत विचार

विभागीय आवंटन में प्राथमिकताएं

सबसे अधिक आवंटन प्राथमिक शिक्षा (80,997 करोड़), ऊर्जा (65,926 करोड़), गृह (44,145 करोड़) और लोक निर्माण विभाग (33,740 करोड़) को मिला है।

बुनियादी ढांचा और निवेश

- सात संचालित एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट शीघ्र शुरू
- 16,000 स्टार्टअप, 8 यूनिकॉर्न
- 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश प्रस्ताव

पर्यटन और धार्मिक अर्थव्यवस्था

- महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु
- 234 गांव पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित
- लखनऊ 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी'

बरेली न्यूरो एण्ड स्पाईन सुपर स्पेशलिटी सेंटर

डा. मोहित गुप्ता

M.Ch., Neurosurgery (AIIMS)
Senior Consultant Neurosurgeon
मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग विशेषज्ञ
Reg. No. UPMCI 65389
समय - प्रातः 10 से 12:30 बजे तक
एवं सायं 6 से 8:30 बजे तक
अब डॉ. मोहित गुप्ता
रविवार को भी मिलेंगे
प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक

सुविधायें

ब्रेन हैमरेज | स्लिप डिस्क
ब्रेन ट्यूमर | मिर्गी का दौरा
गर्दन दर्द (सर्वाइकल)
रीढ़ की चोट, टी.बी
सिर दर्द, माइग्रेन
कमर दर्द, कंधों में दर्द
पीठ दर्द, रीढ़ की गांठ
सिर की चोट (हेड इंजरी)
हाथ पैरों में झनझनाहट
फालिज (लकवा)
नसों का दर्द
सियाटिका (कमर में पैरों का दर्द)
दिमागी में पानी व खून जमना
दिमाग, रीढ़ एवं नस सम्बन्धित सभी बीमारियों का इलाज एवं ऑपरेशन

Bareilly Neuro and Spine Super Speciality Centre
Google Maps Location
सी-427, डिवाइन अस्पताल के सामने, के.के. अस्पताल रोड, राजेन्द्र नगर, बरेली
7417389433, 7017678157
9897287601, 8191879754

बजट से लोगों में शिक्षा और रोजगार की बढ़ी आस

मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा में होगा सुधार, बजट से कई वर्गों में खुशी तो कई निराश

- महिलाएं बोलीं- महंगाई के मुद्दे पर नहीं हुई कोई खास राहत

कार्यालय संवाददाता, पीलीभीत

अमृत विचार : प्रदेश सरकार से बजट में राहत की उम्मीद लगाए कई वर्गों को जहां खुशियां मिली तो कई निराश हो गए। कुछ का कहना है कि आम आदमी के लिए बजट में कोई खास प्रावधान नहीं दिखा। महिलाएं महंगाई के मुद्दे पर राहत न मिलने की बात कहती रही। हालांकि मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी देने की बात कही गई है। साथ ही चिकित्सा सुविधा को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा में सुधार होगा।

योगी सरकार की ओर से बुधवार को बजट पेश किया गया। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया। इसे लेकर सुबह से ही लोग टीवी पर नजरें लगाए रहे। कई जिलों के बड़े-बड़े दावे किए गए। हालांकि स्थानीय स्तर पर किसी बड़ी विकास योजना की कोई घोषणा फिलहाल नहीं रही।

उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान करने के लिए रानी लक्ष्मी बाई योजना को बढ़ावा दिया गया है। इस योजना से जिले के छात्र-छात्राओं को भी लाभ मिलेगा। मगर व्यापारी, महिलाएं और युवा जो सोच रहे थे, उनकी मानें तो बजट वैस देखने को नहीं मिला।

महिलाओं का कहना है कि बजट में महंगाई को लेकर कोई खास चर्चा नहीं की गई। व्यापारियों की मानें तो इस बजट में वहीं सब देखने को मिला। जो केंद्र सरकार के बजट में था। युवाओं को निःशुल्क टेबलेट की योजना को भी बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट और समर्पित जॉब प्लेसमेंट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को बाजार की मांग के अनुसार तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की घोषणा की गई।

आयुष फार्मेसी का होगा आधुनिकीकरण

इस बजट में आयुष क्षेत्र के विकास के लिए निवेश बढ़ाने का संकेत दिया है। इसका लाभ पीलीभीत स्थित राजकीय आयुष फार्मेसी को मिलने की उम्मीद है। फार्मेसी को आधुनिक मशीनों से लैस कर उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तैयारी है। वर्तमान में यहां से 19 जिलों को दवाओं की आपूर्ति की जाती है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण समयबद्ध आपूर्ति में कठिनाई आती रही है। बजट प्रावधान के बाद मशीनों की उपलब्धता से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार की संभावना है।

नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली योजना जारी

किसानों के हित में नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली योजना को जारी रखने की घोषणा की गई है। यह योजना एक अप्रैल 2023 से संचालित है और अब भी प्रभावी रहेगी। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे को बढ़ाने की बात कही गई है।

संविदाकर्मियों को कैशलैस इलाज की सुविधा

बजट में एक अहम घोषणा के तहत शिक्षकों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के संविदाकर्मियों को भी कैशलैस उपचार योजना से जोड़ा गया है। बेसिक, माध्यमिक, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों के संविदा कर्मचारी अब पांच लाख रुपये तक के इलाज का लाभ उठा सकेंगे। इससे लंबे समय से सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे संविदाकर्मियों को राहत मिलेगी।

क्या बोले युवा, विशेषज्ञ और किसान

सरकार का बजट को तो ठीकठाक है। मगर महंगाई कम करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जिसको लेकर खेद है। सरकार को आमजन को ध्यान में रखते हुए महंगाई के मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए था। सिलेंडर और अन्य खाद्य सामग्रियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जिसमें कटौती करना चाहिए था। तभी मध्यम वर्गीय परिवार खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। – **निधि निगम**, गृहणी

उप्र सरकार के बजट में युवाओं के लिए नए स्टार्टअप के लिए योजनाएं संचालित करने के बारे में कहा गया है। जोकि बेहतर है। स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के अंतर्गत युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट मिलने से पिछड़ा युवा और आगे बढ़ेगा, लेकिन जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। उन्हें नौकरी की जरुरत है। अगर रोजगार मिलेगा तभी प्रदेश उन्नित करेगा। – **आकाश श्रीवास्तव**, युवा

सरकार को चाहिए कि जो बजट बनाया जाए। आम आदमी को देखकर बजट बनाना चाहिए। जिससे आम आदमी की जो जरूरतमंद आवश्यकता है। वह सरकार के बजट के द्वारा आसानी से प्राप्त करने में मदद प्राप्त हो सके। बड़ा मुद्दा रोजगार का है, इसके लिए उप्र सरकार ने इंवेस्टर्स समिट की योजनाओं को धरातल पर लाने की जरुरत है। तभी युवाओ को रोजगार मिले सकेगा। – **मोहम्मद शाहरुख**, युवा

पीलीभीत जनपद के कई पुरातत्विक स्थल हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने कई शोध पत्र और एपीग्राफी इंडिका में इन स्थलों का उल्लेख किया है यदि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पीलीभीत के संरक्षित किसी स्थल को विकसित किया जाएगा तो संस्कृति, सभ्यता की दिशा में सार्थक प्रयास के साथ पीलीभीत को नई पहचान मिलेंगी। – **शिवम कश्यप**, समाजिक कार्यकर्ता

दुकान पर व्यापारियों संग बजट देखते व्यापारी नेता एमए जिलानी। ● अमृत विचार

सरकार को बजट में उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ानी चाहिए थी। कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली छूट को बढ़ाने की जरुरत थी ।ताकि किसान को राहत मिल सकती। साथ जमीन की मिट्टी की जांच करने के लिए लैबों की स्थापना कराने की जरुरत थी। बजट में कुछ बदलाव की जरुरत थी – **मंजीत सिंह**, जिलाध्यक्ष, भाकियू अराजनैतिक

विफलताओं को छिपाने का किया प्रयास

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पूरी तरह से जनविरोधी, दिशाहीन और आंकड़ों का मायाजाल है। किसान, नौजवान, मजदूरों, व्यापारियों और गरीब वर्ग की समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार की विफलताओं को छिपाने का प्रयास मात्र है। – **जगदेव सिंह जग्गा**, सपा जिलाध्यक्ष

पीलीभीत के विकास को मिलेगी तीव्र गति

प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में पीलीभीत जनपद के विकास को तीव्र गति प्रदान होगी। नए रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण होने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को गति मिलेगी। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट विकास उन्मुख है। – **संजय सिंह गंगवार**, राज्यमंत्री प्रदेश सरकार

सरकार के इस बजट में महंगाई के मुद्दे पर कोई बात नहीं की गई है। महंगाई के चलते घरेलू बजट बिगड़ रहा है। इस पर ध्यान देने की जरुरत थी। – **रितिका सहगल**, गृहणी

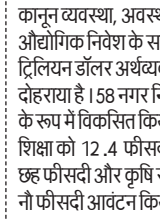

यूपी सरकार का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इसका मुख्य फोकस रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विस्तार और महिला सशक्तिकरण पर है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा तथा डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम शुरू की जाएगी, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़े और आर्थिक गतिविधियों को गति मिले। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के तहत एग्री-एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने कानून व्यवस्था, अवस्थापना विकास और औद्योगिक निवेश के समन्वय से यूपी को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दोहराया है। 58 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट में शिक्षा को 12.4 फीसदी और चिकित्सा को छह फीसदी और कृषि से संबद्ध सेवाओं में नौ फीसदी आवंटन किया गया है। – **शुभभ गुप्ता**, सीए

जिला अस्पताल में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर को मिलेगी रफ्तार

प्रदेश सरकार ने जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण पर जोर देते हुए प्रत्येक जिले में इमरजेंसी ट्रामा सेंटर की स्थापना की बात दोहराई है। जनपद में ट्रामा सेंटर का भवन पूर्व से निर्मित है, ऐसे में बजट प्रावधान के बाद इसके संचालन को गति मिलने की संभावना बढ़ गई है। ट्रामा सेंटर के शुरू होने से सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को 'गोल्डन आवर' में उपचार मिल सकेगा, जिससे गंभीर मरीजों की जान बचाने में मदद मिलेगी।

धूमधाम से निकाली निशान यात्रा, उड़ा गुलाल

संवाददाता, बरखेड़ा

अमृत विचार : खाटू श्याम सेवा कमेटी के तत्वावधान में कस्बे में बुधवार को तृतीय श्रीखाटू श्याम निशान यात्रा निकाली गई। मेला मैदान में श्रद्धालु एकत्र हुए।

श्रीखाटू श्याम तृतीय भव्य निशान यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई गांधी आश्रम, सीएचसी मार्ग होती हुई गाजीपुर कुंडा तिराहा, रेलवे स्टेशन आदि से गुजरी। श्रद्धालुओं ने गुलाल की होली भी खेली। महिलाएं पीले वस्त्र धारण किए थीं। निशान यात्रा में खाटू श्याम सेवा कमेटी के सदस्य अभिषेक गुप्ता, अर्पित सक्सेना, ऋषि राज गुप्ता, अमन गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, अरविंद कुमार, दर्पण सक्सेना, अभिषेक गंगवार, ऋतिक भारद्वाज, जितेंद्र मौर्य, योगेश सक्सेना, श्याम गुप्ता आदि मौजूद रहे। इसके बाद मेला मैदान में संकीर्तन चला।

निशान यात्रा में शामिल श्रद्धालु।

न्यूज डायरी

स्पोर्ट्स डे पर बच्चों ने प्रतियोगिताओं में दिखाई प्रतिभा, मिला पुरस्कार

पीलीभीत, अमृत विचार : शैमरॉक किरन स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया गया। प्राइमरी के विद्यार्थियों ने खेलो में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्राइमरी के बच्चों ने ड्रिल प्रस्तुत की। ऑब्टिकल्स रेस, 50 मीटर रेस व रिले रेस आदि कराए गए। डायरेक्टर हर्ष कंचन, प्रधानाचार्या अदिति सक्सेना ने उत्साह बढ़ाया। अंतिम चरण में हाउस गेम कराया गया। इसमें चारो हाउस मेंटर्स, मोटीवेटर्स, लीडर्स व पायनियर्स के बच्चों ने प्रतिभाग किया। डायरेक्टर हर्ष कंचन ने कहा कि पढ़ाई के साथ हमें खेलों में भी प्रतिभाग करना चाहिए। इससे मानसिक व शारीरिक विकास सुचारू रूप से होता रहे। अगर प्रतिभाग ही नहीं करेंगे तो जीत की महत्वता को नहीं समझ सकेंगे। यह केवल विद्या के क्षेत्र में ही नहीं अन्य क्षेत्र में भी निहित है। विजेताओं को सर्टिफिकेट व मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शानी, पल्लवी, विप्रा, रश्मि, सायमा, रूचि, सदफ, इकरा, सिदरा, सुबह, दीपिका, अदिति, लव, सागर, निधि, दिव्यांशी आदि मौजूद रहे।

24 मार्च को होगा लोक अदालत का आयोजन

पीलीभीत, अमृत विचार : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश के अनुपालन में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार 14 मार्च को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक दीवानी न्यायालय परिसर पीलीभीत, ब्राहय न्यायालय पूरनपुर और बीसलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

प्राधिकरण के सचिव अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने जनमानस से अपील की है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाद को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।

यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जनपद में समस्त विभागों को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है कि अपने अपने विभागों से सम्बन्धित अधिक से अधिक वादों/मामलों को नियत कर उनका निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाए। जिससे दोनों पक्षों को लोक अदालत का लाभ मिल सके।

क्षेत्रीय समस्याओं के निस्तारण की मांग, सीएम को सौंपा ज्ञापन

बिलसंडा, अमृत विचार : उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष अवनीश जायसवाल ने बीसलपुर विधायक विवेक वर्मा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्रीय समस्याओं के निस्तारण के लिए ज्ञापन सौंपा। खेल क्षेत्र में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नगर में स्टेडियम बनवाने, गांधी स्मारक सुंदर लाल इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रयोगशाला, फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए स्थायी सब्जी मंडी की व्यवस्था कराए जाने आदि मांगें रखी गई। बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने इसे लेकर आश्वस्त किया है।

स्वयंसेवकों ने निकाली जागरुकता रैली, लोगों को किया जागरूक

बिलसंडा, अमृत विचार : हेमपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करके की गई। प्राचार्य डॉ. दिनेश चंद्रा, एनएसएस प्रभारी डॉ. दिनेश कुमार के निर्देशन में शिविर आयोजित किया गया। कॉलेज के स्वयंसेवकों ने गांव हेमपुर में जागरूकता रैली निकाली। लोगों को राष्ट्रभावना, शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान प्रोफेसर नरेंद्र कुमार बत्रा, अनुजा अग्रवाल, सत्यभान सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।

बरखेड़ा व अमरिया ब्लॉक में बच्चियों को बांटी हिमालया किट, दिलाई शपथ

पीलीभीत, अमृत विचार : ब्लॉक बरखेड़ा और अमरिया में ब्लॉक में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक की गई। इसमें संरक्षण अधिकारी मीनाक्षी पाठक ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया। बैठक का उद्देश्य ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के माध्यम से जनपद के जरूरतमंद बच्चों को योजनाओं से जोड़ना रहा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना एवं स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में जानकारी दी गई। उपस्थित महिलाओं को बाल विवाह के दुष्परिणाम बताए गए। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत शपथ ली गई। सीएचसी बरखेड़ा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत नवजात पांच बच्चियों को हिमालया किट बांटी गई। इसके अलावा पीएस मॉडल स्कूल जंगरौली, उच्च प्राथमिक विद्यालय गाजीपुर मुगल में बाल विवाह अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रमनदीप कौर, काउंसलर मनिस्ता, अभिषेक, प्रदीप मौर्य आदि मौजूद रहे।

Lifelines MEDICAL OF BAREILLY
अमृत विचार
विज्ञापन हेतु सम्पर्क करें :- 8445507002

फोकस नेत्रालय
राजेन्द्र नगर, बरेली 731-098-7005
बरेली का सबसे बड़ा केवल आँखों के लिए समर्पित प्राइवेट अस्पताल ...
नवीनतम AI तकनीक एवं NABH मान्यता के साथ
● 40,000 से अधिक सफल सर्जरी सम्पन्न
● बिना इंजेक्शन एनेस्थीसिया (केवल आई ड्राप्स द्वारा)
● आयुष्मान/सीजीएचएस/ईसीएचएस/सीएपीएफ सभी स्वास्थ्य बीमा मान्य
● कैशलेस ईलाज

स्वास्थ्य जागरूकता अभियान
नि : शुल्क परामर्श
कैम्प में समस्त ब्लड जाँचें, ई.सी.जी., एक्स-रे 50% के छूट पर किये जायेंगे।
रजिस्ट्रेशन शुल्क 20/-
महीने के प्रत्येक रविवार को
समय : सुबह 10 से 5 बजे तक
डॉ. दीपक माहेश्वरी
MBBS., MD, Consultant Physucuan & Critical Care Specialist
ब्लड प्रेशर, हृदय रोग
श्वांस रोग, गम्भीर रोग विशेषज्ञ
प्रेमलोक हॉस्पिटल
नरियावल अड्डा, शाहजहाँपुर रोड, बरेली।
9084307201, 9412244430
डॉ. नितिन अग्रवाल हृदय रोग विशेषज्ञ मो. 9457833777

ADITYA आदित्य आई एण्ड लेजर सेन्टर
उपलब्ध सुविधायें :-
बिना सुई बिना टांका आधुनिक लेंस प्रत्यारोपण की सुविधा।
TPA कैशलेस सुविधा उपलब्ध
100000 से अधिक आँखों के आपरेशन का अनुभव
अल्ट्रासाउण्ड द्वारा पर्दे की जांच की सुविधा उपलब्ध
IOL Master 700 द्वारा लेंस का नम्बर
लेजर द्वारा आंख की झिल्ली हटाने की सुविधा उपलब्ध
बी स्कैन द्वारा पर्दे की जांच उपलब्ध
OCT द्वारा काला पानी एवं पर्दे की जांच व उपचार
8077344353
समय : प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए फ्री आपरेशन की सुविधा
डॉ. आदित्य त्यागी
MBBS, DOMS, DNB, MNAMS
CARARACT REFRATIVE & GLAUCOMA SURGERON
ड्यूलिप ग्राउंड के सामने, पीलीभीत बाईपास, बरेली

न्यूज ब्रीफ

विवाहिता से किया दुष्कर्म, रिपोर्ट दर्ज

बरखेड़ा, अमृत विचार : थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव के अजय कुमार पुत्र लीलाधर 16 जनवरी को रात करीब एक बजे उसे नौकरी दिलाने के बहाने घर से ले गया। उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद उसे मारपीट कर भगा दिया। उसने शर्म के मारे यह बात किसी को नहीं बताई। बाद में अपने भाई को बताया। इंस्पेक्टर प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि विवाहिता की ओर से आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है।

किशोरी को फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज

बरखेड़ा, अमृत विचार : थाना क्षेत्र के रहने वाले एक ग्रामीण ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को आठ फरवरी को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगा ले गया है। उसकी पुत्री घर में रखा कीमती जेवर एवं यूकेलिप्टस बेचकर रखें डेढ़ लाख रुपए भी ले गई है। उसने अपनी पुत्री को ढूंढने का काफी प्रयास किया लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं लग सका है। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है।

पति समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

बिलसंडा, अमृत विचार : बिलसंडा क्षेत्र के गांव भितेरा निवासी खुशबू देवी की ओर से पुलिस ने एसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की है। जिसमें पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2012 में माधौपुर जिला बरेली निवासी जॉनी से हुई थी। उसके तीन बच्चे हैं। आरोप है कि उसका पति नशा अधिक करता है। विरोध करने पर पति जॉनी, ससुर रामऔतार, देवर रामू व विशबंर ने मारपीट शुरू कर दी। जेवर छीन लिए और घर का सामान बेचकर नशा किया। इसके बाद गला दबाकर मारने की कोशिश की। पीड़िता की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।

सड़क हादसे में घायल युवक की जान गई

पीलीभीत, अमृत विचार : सुनगढ़ी क्षेत्र के मोहल्ला नखासा निवासी सिद्धार्थ चौधरी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका भाई राजेश 8 फरवरी की रात गेस्ट हाउस से काम कर घर लौट रहा था। इस दौरान कार ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर हालत में राजेश को जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

किशोरी को फुसलाकर ले जाने का आरोप

पीलीभीत, अमृत विचार : थाना सुनगढ़ी क्षेत्र की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। मां ने आरोप लगाया है कि रुद्रपुर निवासी विशाल उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया है। विशाल का रिश्तेदार राज भी इसमें शामिल है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की है।

घर में घुसकर महिलाओं पर किया हमला

बीसलपुर, अमृत विचार : पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट की गई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है। कोतवाली में दी गई तहरीर में ग्राम रूरिया निवासी छोटेलाल ने बताया कि उसका भाई इंद्रजीत जगह बंटवारे को लेकर रंजिश मानता चला आ रहा है। आए दिन नशा कर गाली गलौज करता है। 18 जनवरी की सुबह आठ बजे इंद्रजीत परिवार वालों से अभद्रता कर रहा था। विरोध करने पर घर के बाहर चला गया। कुछ देर बाद इंद्रजीत व उसकी पत्नी सावित्री देवी लाठी डंडे से लैस होकर घर के अंदर घुस आए। इसके बाद पीड़ित की मां कृष्णा देवी और बहन मोरकली को पीटा। जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है।

पीटीआर में वृद्धा का मिला क्षतविक्षत शव

वन्यजीव के हमले में हुई मौत, घर से 200 मीटर दूर मिला शव, पूजा में जाने के लिए निकली थी वृद्धा

कार्यालय संवाददाता, पीलीभीत

महोफ जंगल में महिला का शव मिलने के बाद जांच करती पुलिस व वन विभाग की टीम।

अमृत विचार : पीलीभीत टाइगर रिजर्व की महोफ रेंज में बुधवार सुबह एक बुजुर्ग महिला का क्षत विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के गले और पेट में गहरा घाव के निशान पाए गए। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पर वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। न्यूरिया पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।

पारूल राय।

महिला की मौत वन्यजीव के हमले में होना पाया गया है। फिलहाल महिला की मौत जंगल में हुई है या फिर वन्यजीव उसे उठाकर जंगल में ले गया, इसको लेकर जांच की जा रही है। ग्रामीण बाघ का हमला बता रहे हैं।

न्यूरिया थाना क्षेत्र की भद्र कॉलोनी निवासी 62 वर्षीय पारूल राय पत्नी सुकुमार बीते मंगलवार सुबह गांव में होने वाली पूजा में शामिल होने के लिए घर से निकली थी। देर शाम तक महिला घर वापस नहीं लौटी। जिस पर परिजनों ने आसपास क्षेत्र में उसकी तलाश की, मगर महिला का कोई सुराग नहीं लग सका। ग्राम प्रधान नरेश विश्वास ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दी। इधर बुधवार सुबह करीब सात बजे महिला का क्षत-विक्षत शव महोफ रेंज के जंगल में पड़ा मिला। महिला का शव जंगल में मिलने की जानकारी लगते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा होने लगी। महिला के गले और पेट पर गहरे घाव पाए गए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। न्यूरिया थाने के एसओ सुभाष मावी भी टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। ग्रामीण महिला की मौत बाघ या किसी हिंसक वन्यजीव के हमले में होने की आशंका जता रहे थे। महिला के परिवार वालों ने बताया कि पारुल मंगलवार को काली पूजा पर संजय नगर श्मशान घाट के पास हो रहे भंडारे में शामिल होने गई थी। हालांकि कुछ ग्रामीण महिला द्वारा जंगल में जाकर लकड़ी बीनने की संभावना जता रहे थे। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव पोस्टमार्टम को भेजा। जिसमें वन्यजीव के हमले में मौत होने की पुष्टि हुई है।

- **वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची न्यूरिया पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा**

> घटना की जानकारी पर टीम भेजी गई थी। बाघ समेत अन्य वन्यजीव के हमले में मौत हुई है या कोई अन्य वजह इसे लेकर पड़ताल चल रही है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। – **मनीष सिंह**, डिप्टी डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व

फिर उठे निगरानी पर सवाल, जंगल में कैसे पहुंची महिला

महिला के शव का पोस्टमार्टम बुधवार को ही करा लिया गया। इसमें महिला की मौत किसी वन्यजीव के हमले से होने की बात सामने आई है। हालांकि हमला बाघ ने किया या फिर किसी अन्य वन्यजीव ने, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। वहीं दूसरी ओर से महिला जंगल का शव जंगल में करीब 200 मीटर अंदर मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में महिला जंगल के अंदर लकड़ी बीनने गई थी, या फिर उसे वन्यजीव उठाकर ले गया, इन सभी को लेकर विभागीय जांच शुरू की गई है। अधिकारियों की ओर से जंगल की निगरानी के लिए किए जाने वाले दावों पर भी पुन: सवाल उठ गया है।

तो क्षेत्र में नहीं तार फेंसिंग और लाइट

महिला का शव मिलते ही बाघ हमले में मौत का शोर मच गया था। प्रधान से सूचना मिलने पर किसान नेता देव स्वरुप पटेल पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और जानकारी की। उनका कहना है कि परिजनों से वार्ता की गई। इस दौरान सामने आया है कि संबंधित क्षेत्र में लाइट एवं तार फेंसिंग नहीं है। इस समस्या को केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद के संज्ञान डाला जाएगा। परिवार को हरसंभव मदद का भी आश्वासन दिया गया। बरखेड़ा विधायक प्रतिनिधि नंदलाल वर्मा ने भी परिवार से मुलाकात की।

फार्मासिस्ट नहीं मिलने पर दो मेडिकल स्टोर सील

मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण करतीं ड्रग इंस्पेक्टर नेहा वैश्य। • अमृत विचार

कार्यालय संवाददाता, पीलीभीत

अमृत विचार : जिले में दवाओं की बिक्री में बरती जा रही लापरवाही पर औषधि विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। बिलसंडा कस्बे में औषधि निरीक्षक नेहा वैश्य की अगुवाई में की गई छापेमारी के दौरान दो मेडिकल स्टोरों पर पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति मिलने पर उन्हें तत्काल बंद करा दिया गया। वहीं दो अन्य दुकानों पर अभिलेखों में कमियां पाए जाने पर सुधार के निर्देश दिए गए हैं।

औषधि निरीक्षक नेहा वैश्य ने बताया कि शुभम मेडिकल स्टोर और बांके बिहारी मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण के दौरान कोई भी पंजीकृत फार्मासिस्ट मौजूद नहीं मिला। नियमानुसार बिना फार्मासिस्ट की उपस्थिति के दवाओं की बिक्री नहीं की जा सकती। इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए दोनों मेडिकल स्टोरों का संचालन बंद करा दिया गया। इसके अलावा सक्सेना मेडिकल स्टोर और सानू मेडिकल स्टोर पर जांच के दौरान कुछ दस्तावेज अधूरे पाए गए। संचालकों को आवश्यक अभिलेख तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। औषधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

- **दस्तावेजों में कमी मिलने पर दो दुकानों को नोटिस किया जारी सुधार करने के दिए निर्देश**

सरीसृप व छोटे स्तनधारी वन्यजीवों को रेस्क्यू करने का दिया प्रशिक्षण

कार्यालय संवाददाता, पीलीभीत

अमृत विचार : पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत वन्यजीव प्रबंधन के लिए क्षमता विकास पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में टाइगर रिजर्व समेत वन एवं वन्यजीव प्रभाग की सभी आठ रेंजों के वन अफसर एवं वनकर्मियों ने प्रतिभाग किया। जिसमें विशेषज्ञों द्वारा वन्यजीवों को आधुनिक विधि से रेस्क्यू करने एवं घायल वन्यजीवों के उपचार आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। कार्यशाला का समापन 12 फरवरी को होगा।

टर्टल सर्वाइवल एलायंस फाउंडेशन (टीएसए) के सहयोग से फील्ड डायरेक्टर कार्यालय के वन सभागार में बुधवार को आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत मुख्य वन संरक्षक बरेली वृत्त/फील्ड डायरेक्टर पीपी सिंह ने दीप प्रज्जवलित करके कराई।

दो दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते मुख्य वन संरक्षक पीपी सिंह।

- **वन्यजीव प्रबंधन के लिए क्षमता विकास पर दो दिवसीय कार्यशाला शुरू**

इसमें टीएसए फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉ. शैलेंद्र सिंह ने सरीसृर्प वन्यजीव मगरमच्छ, पैगोलिन, अजगर, सांप, कछुआ, गौह, बाइपर, करैत समेत स्तनधारी बाघ, तेंदुआ, भालू, चीतल, बारहसिंगा, पक्षी वर्ग के सारस, बंगाल फलोरिकन, किंगफिशर आदि को आधुनिक विधि से सफल रेस्क्यू करने एवं उनकी पहचान करने के बारे में बताया गया। उन्होंने घायल वन्यजीवों का उपचार के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान टीएसए फाउंडेशन की टीम सदस्यों द्वारा इससे संबंधित जानकारियां दी गई। कार्यशाला में टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह, वन एवं वन्यजीव प्रभाग के डीएफओ भरत कुमार डीके, प्रशिक्षु डीएफओ हिमांशु वाबले, उप प्रभागीय वनाधिकारी रमेश चौहान, रुद्र प्रताप सिंह, वन्यजीव एसओएस डॉ. गोचलन, टीएसए फाउंडेशन के डॉ. सौरभ देवान, अरूणिमा सिंह, हर्षित सिंह समेत दोनों प्रभागों के क्षेत्रीय वनाधिकारी एवं अग्रिम पंक्ति के फील्ड कर्मचारी मौजूद रहे। टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि कार्यशाला का समापन 12 फरवरी को होगा।

कोटेदार ने ग्रामीण पर किया हमला

पीलीभीत, अमृत विचार : सुनगढ़ी क्षेत्र के ग्राम रुपपुर कमालू के निवासी रामस्वरूप पुत्र सियाराम ने एसपी को दिए शिकायत पत्र में बताया कि 11 फरवरी को गांव के कोटेदार के पास राशन लेने गए थे। आरोप है कि कांटे पर सामने की तरफ जहां वजन दिखता है। वहा पर कपड़ा रखकर तौल की जा रही थी। इसका विरोध करने पर कोटेदार ने मारपीट की। पीड़ित ने वीडियो बनाने का प्रयास किया तो हमला कर दिया और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया। मफलर से गला दबाने की कोशिश की गई। आरोप है कि कोटेदार ने सरकारी जमीन पर कब्जा भी कर रखा है। इसकी शिकायत पर पूर्व में लेखपाल और कानूनगो ने कार्रवाई की थी, जिसके बाद से आरोपी रंजिश मानता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

प्रेमिका की मौत के बाद प्रेमी ने लगाया फंदा, मौत

कार्यालय संवाददाता, पीलीभीत

अमृत विचार : थाना सुनगढ़ी क्षेत्र की 15 वर्षीय किशोरी ने मंगलवार को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। उसका थाना जहानाबाद क्षेत्र के 20 वर्षीय युवक से से प्रेमप्रसंग चल रहा था। वह किशोरी के गांव स्थित अपनी ननिहाल में जाता था, इसी दौरान दोनों का संपर्क हो गया था। सूचना पर पहुंची सुनगढ़ी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार शाम को उसका शव गांव में पहुंचा। गांव में किशोरी के शव का अंतिम संस्कार किया गया। इसकी जानकारी जैसे ही युवक को हुई, वह भी अचानक घर से लापता हो गया। परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। उसका शव गांव में ही एक बाग में रस्सी के बने फंदे से लटका मिला। शव लटका होने की जानकारी मिलने पर परिजनों के अलावा गांव के तमाम लोग एकत्र हो गए। सूचना पुलिस को दी गई तो इंस्पेक्टर सुनगढ़ी नरेश त्यागी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इंस्पेक्टर सुनगढ़ी ने बताया कि युवती की मौत की सूचना मिलने पर युवक ने भी आत्महत्या कर ली है। अभी किसी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है।

- **सूचना पर पहुंची सुनगढ़ी पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम ने जुटाए साक्ष्य**

युवती ले जाने की रिपोर्ट

पीलीभीत, अमृत विचार : जहानाबाद क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि नौ फरवरी की रात बरेली निवासी विनय उसकी 18 वर्षीय बहन को बहला-फुसलाकर ले गया। काफी तलाशने के बाद भी बहन का कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लंबित मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

कार्यालय संवाददाता, पीलीभीत

अमृत विचार : सिंचाई विभाग ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन ने दो वर्ष पूर्व आश्वासन दिए जाने के बाद भी लंबित मांगों का निस्तारण न होने पर रोष जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम सदर को सौंपा। ज्ञापन में संगणक प्रोन्नति मामले में 22 फरवरी तक कोई ठोस निर्णय लिए जाने पर 16 मार्च को प्रदेश स्तर पर संघर्ष कार्यक्रम कर मुख्यमंत्री आवास तक शांति मार्च निकालने की चेतावनी दी।

सिंचाई विभाग ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार के नेतृत्व में तमाम पदाधिकारी बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मांग पत्र एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि संघ द्वारा वर्ष 2023 में मंडल स्तर पर संघर्ष कार्यक्रम किया गया था। समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन भी मिला था, मगर दो वर्ष बीतने के बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई। शासन एवं विभाग की उदासीनता एवं उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण संवर्ग के सदस्यों में घोर निराशा एवं हताशा व्याप्त है। ज्ञापन में संगणक से सहायक अभियंता (सिविल) पद पर प्रोन्नति करने, ड्राइंग संवर्ग के पदों का पुनर्गठन कर विभागीय समिति द्वारा की गई पदोन्नति पदों की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा नियमावली-1985 संशोधित करने, एसीपी के अंतर्गत अवर अभियन्ता की भांति 4600 रुपये ग्रेड पे इग्नोर कर वेतनमान स्वीकृत करने, ड्राइंग संवर्ग के कार्मिकों के लिए अवर अभियंता (सिविल/यांत्रिक) पद पर प्रोन्नति के लिए पृथक कोटा निर्धारित करने, ड्राइंग संवर्ग के पदों पर 01 जनवरी 1986 से व्याप्त वेतन विसंगति दूर करते हुए समतुल्य वेतनमान अनुमन्य करने आदि की मांग की गई।

एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपते सिंचाई विभाग ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन के सदस्य।

- **मांग पर ठोस निर्णय न लेने पर 16 को लखनऊ में शांति मार्च निकालने की दी चेतावनी**

ज्ञापन में कहा कि मांग पत्र में शामिल मुख्य मांग संगणक से सहायक अभियंता सिविल के पद पर पदोन्नति मामले में यदि 22 फरवरी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 16 मार्च को प्रदेश स्तरीय संघर्ष कार्यक्रम होगा। ज्ञापन देने वालों में अशोक कुमार, मुनेश्वर, संदीप कुमार, अंकुर अग्रवाल, मुकद्दस अली आदि शामिल रहे।

न्यूज डायरी

आश्वासन पर धरना समाप्त, टोल टैक्स माफ करने समेत रखी 11 मांगें

बीसलपुर, अमृत विचार : भाकियू कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन बुधवार को तहसीलदार हबीब उर्रहमान के आश्वासन पर समाप्त हुआ। इस दौरान ज्ञापन देकर 11 सूत्रीय मांगों को रखा। भाकियू कार्यकर्ताओं ने दिए गए ज्ञापन में बताया कि तहसील क्षेत्र के गांव कनपरी में पारंपरिक तालाब चकरोड, मृत मवेशियों के दफन स्थल, जल निकासी की पुलिया को बंद कर सार्वजनिक सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण को तत्काल ध्वस्त कराने की मांग की गई। कनपरी गांव के एक परिवार को फर्जी जियो टैगिंग कर प्रधानमंत्री आवास का लाभ देने का आरोप लगाया। कहा कि तहसील स्तर पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी हो रही है। साथ ही वसूली भी होती है, इसे बंद कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास आवंटन में पात्रों को लाभान्वित कराने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ताओं का टोल टैक्स माफ करने समेत 11 मांग रखी। तहसीलदार के आश्वासन पर दूसरे दिन धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। इस मौके पर धर्मेंद्र कुमार, महेंद्र पाल, रणजीत सिंह, संचित दीक्षित, ओमप्रकाश राजपूत, जिला अध्यक्ष भजनलाल आदि मौजूद रहे।

हज यात्रियों के लिए 14 फरवरी को लगेगा वैक्सीनेशन कैंप

पीलीभीत, अमृत विचार : हज यात्रा की शुरुआत अप्रैल से होने जा रही है। इससे पहले सभी को टीकाकरण एवं दवाओं की खुराक देने की कवायद पूरी करनी होगी। इसको लेकर 14 फरवरी को हज यात्रियों के मेडिकल स्क्रीनिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एवं वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है। जनपद के 106 जायरीनों को अप्रैल से शुरू हो रही धार्मिक यात्रा पर जाने की अनुमति दी गई है। हज पर जाने वाले यात्रियों को कवाड्रिवेलेंट मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस वैक्सीन व 65 वर्ष से अधिक आयु के हज यात्रियों को सिजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन की खुराक दिलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुरेश चंद्र मौर्य ने बताया कि मेडिकल स्क्रीनिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एवं वैक्सीनेशन कैंप 14 फरवरी को सुबह 09 बजे से आयोजित किया जाएगा।

देवहा नदी किनारे मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत

अमरिया, अमृत विचार : तहसील क्षेत्र के गांव नगरिया कॉलोनी के पास देवहा नदी किनारे इन दिनों मगरमच्छों की चहलकदमी देखी जा रही है। सुबह -शाम नदी के तट पर कई बार मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी किनारे पशु चराने और खेतों की ओर जाने वाले ग्रामीणों को खतरा बना हुआ है। बच्चों को भी नदी की तरफ न जाने की हिदायत दी जा रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग से निगरानी बढ़ाने और आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। वहीं, प्रशासन से नदी किनारे चेतावनी बोर्ड लगाए लगाने की मांग की है।

ओवरलोडिंग करने पर पांच वाहन किए सीज

पीलीभीत, अमृत विचार : परिवहन विभाग की ओर से नियम उल्लंघन कर दौड़ रहे वाहनों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान पांच माल वाहनों को ओवरलोडिंग मिलने पर सीज किया गया। एआरटीओ वीरेंद्र सिंह, यात्रीकर अधिकारी बर्डिस चतुर्वेदी ने विभिन्न मार्गों पर चेकिंग की। इस दौरान दो ट्रक, दो डंपर, एक डीसीएम समेत कुल पांच वाहन सीज किए गए। दो वाहनों को गढ़वाखेड़ा पुलिस चौकी, एक पूरनपुर चीनी मिल पुलिस चौकी और एक वाहन को बीसलपुर थाना में निरुद्ध किया गया। इसी प्रकार एक बस जोकि बहराइच से दिल्ली जा रही थी, उसकी भी जांच की गई। प्रपत्र की जांच करने परमिट शर्तों का उल्लंघन मिला। इस पर भी कार्रवाई की गई। एआरटीओ ने बताया कि नियम उल्लंघन कर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।

अमृत विचार
क्लासीफाइड
विज्ञापन हेतु सम्पर्क करें
9756905552, 8445507002

सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम फैज अहमद सिद्दीकी पुत्र स्व. शकील अहमद सिद्दीकी है मैं अपना नाम फैज अहमद सिद्दीकी से बदलकर फैज अहमद करना चाहता हूं। अत: भविष्य में मुझे फैज अहमद के नाम से ही जाना जाये।

सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपने पुत्र गुड्डू व पुत्रवधु फातिमा को उसके गलत व्यवहार व आचरण के कारण अपनी समस्त चल -अचल संपत्ति से बेदखल कर संबंध विच्छेद कर लिया है। अब मेरे व मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से उनका कोई संबंध व सरोकार नहीं होगा वह अपने कृत्य का स्वयं जिम्मेदार होंगे। **आरिफ पुत्र हामिद निवासी ग्राम नदायल परगना व तहसील सहसवान जिला (बदायू)**

सूचना
मैंने अपना नाम MOHAMMAD SHUAIB SHAMSI से बदलकर SHUAIB SHAMSI कर लिया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए। **शोएब शम्सी पुत्र अफजाल उल हक शम्सी, निवासी मोहल्ला पकड़िया गुरूद्वारा रोड, पीलीभीत।**

सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी PNB METLIFE पॉलिसी में पिता का नाम भूलवश समर पाल अंकित हो गया है जबकि उनका वास्तविक नाम समर पाल सिंह है। आधार कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में भी उनका नाम समर पाल सिंह ही दर्ज है। **केन्द्र सिंह पुत्र श्री समर पाल सिंह निवासी ग्राम परौरा तहसील मीरगंज जिला बरेली।**

सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपने पुत्र ईबने अली व उसकी पत्नी रिहाना को गलत आचरण एवं दुर्व्यवहार के कारण सम्बन्ध विच्छेद कर अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति व जात जायदाद से बेदखल कर दिया है। भविष्य में उनके द्वारा किए गए कृत्यों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। मेरा व मेरे परिवार से कोई वास्ता नहीं होगा। **फातिमा बेगम पत्नी इसरत अली निवासी मोहल्ला मीरखां बाबर नगर कस्बा व तहसील मीरगंज जिला बरेली।**

बिकाऊ है
225 गज मकान
कॉर्नर का पूर्वमुखी
आशीष रॉयलपार्क फेस-2,
इच्छुक व्यक्ति ही संपर्क करें- बरेली
मो. 9897211014

वैधानिक सूचना :- समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन जैसे टावर सम्बन्धी, नौकरी सम्बन्धी, ऋण सम्बन्धी या अन्य किसी भी प्रकार के विज्ञापन में पाठकों को सावधान किया जाता है। विज्ञापनदाता द्वारा किये गये दावे या उल्लेख, समर्थन की पुष्टि समाचार पत्र नहीं करता है।

रोहिलखण्ड मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल
पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली की ओर से
नि:शुल्क नेत्र, दन्त व हृदय चिकित्सा शिविर
12 फरवरी 2026, (बृहस्पतिवार) | प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक | स्थान : अंकुर राईस मिल, निकट असम चौराहा, पूरनपुर रोड, पीलीभीत
- आँखो के कैम्प में आये मरीजों को दवाईयाँ मुफ्त।
- मोतियाबिंद का ऑपरेशन व दवाईयाँ एवं लैंस मुफ्त।
- मोतियाबिन्द के भर्ती मरीज को खाना मुफ्त एवं बस द्वारा लेकर जाना मुफ्त।
- यदि मोतियोबिन्द निकलता है तब आपरेशन रोहिलखण्ड हास्पिटल में ले जाकर मुफ्त में किया जायेगा।
- मोतियाबिन्द के मरीज घर से आधार कार्ड व कम्बल साथ लाना न भूलें।
- दन्त रोग परीक्षण व इलाज मुफ्त।

शिविर में उपलब्ध जाचें
नि:शुल्क परामर्श | नि:शुल्क ई.सी.जी. | नि:शुल्क ब्लड शुगर | ब्लड प्रेशर की जांच | नि:शुल्क दवाईयाँ
सौजन्य से :- • स्वामी प्रवक्ता नन्द, विधायक 128-बरखेड़ा विधान सभा, पीलीभीत • डॉ. आस्था अग्रवाल अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पीलीभीत • कविता बंसवाल, अध्यक्ष, हीमोफीलिया सोसायटी पीलीभीत
नि:शक्त जन सेवा संस्थान पीलीभीत
अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें। शकीब उद्दीन मो. नं. 8534088093

अमृत विचार

बरेली, गुरुवार, 12 फरवरी 2026

पीलीभीत

अम्बा हैल्थ क्लीनिक

डॉ.आर.एस.सिंह
B.A.M.S.
(आयुर्वेदाचार्य)
स्त्री-पुरुष रोग विशेषज्ञ
30 वर्षों से चिकित्सा का अनुभव प्राप्त
ISO.9001:2015 Certify Tredmark Clinic

★ पतले-दुबले
★ गाल पिचके
★ कमजोर स्त्री-पुरुष
★ मोटापा व वजन बढ़ाने के लिए
परामर्श लें।

चिकित्सा जानकारी
भूख न लगना, अपच, कब्ज, गैस बनना, खाने के बाद शौचालय जाना, बच्चों का शारीरिक विकास न होना, पुलिस व फोर्स आदि नौकरी में नाप तौल में कमी होना, बच्चों का बिस्तर गीला करना, मोटे पेट व थुल-थुले व्यक्ति का वजन कम करना, कील-मुंहासे, झाइयां, सफेद दागों व सावलापन हटाना, सुन्दर दिखाना, बालों का समय से पहले झड़ना, टूटना, सफेद होना एवं गंजापन होना, खूनी व वादी बवासीर आदि सभी बिमारियों का परामर्श लें।

किसी भी प्रकार का नशा जैसे
शराब, अफीम, गुटखा, सुल्फा, गांजा बीड़ी, सिगरेट आदि नसा छुड़ाने की रोगी को बिना लाये बिना बताये जानकारी प्राप्त करें।

स्त्री-पुरुष गुप्त समस्याएं
- स्वपन दोष, शीघ्रपतन, मर्दाना कमजोरी होना
- हस्तमैथुन, धात जाने से कमी होना
- इन्द्री का ढीलापन-छोटापन व पतलापन होना
- वीर्य में शुक्राणु का कम होना
- ल्यूकोरिया, बांझपन, बच्चेदानी में रसोली होना
- यौन अंगो का ढीलापन या इच्छा कम होना
- मासिक धर्म अनियमित होना या उम्र से पहले बन्द होना

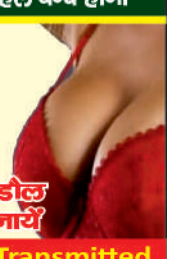

वैवाहिक जीवन को सफल बनायें अविकसित सीना को सुडौल आकर्षक बनायें
Sexually Transmitted Bacterial Disease
सुजाक, गिनोरिया, एड्स, यौन अंगो पर खुजली या छाले पड़ने पर तुरन्त डाक्टर से सम्पर्क करें
गलत फिल्में देखने व फोन पर बातें करने से या पेशाब में विषविषा पदार्थ निकलने पर तुरन्त सम्पर्क करें
डॉ. साहब
आपके विश्वास पर सभी बिमारियों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं दावा या गारंटी नहीं दे सकते
मिलें सुबह 11 से सायं 5 बजे तक
दिनांक :-
8 फरवरी 2026, रविवार
22 फरवरी 2026, रविवार
निकट बरेली कॉलेज, होटल मोती महल काली बाड़ी चौराहा, बरेली
9837069463
7599211076

मौत की वजह भी बन चुका जाम, नहीं हटाया अतिक्रमण

शहर की मुख्य सड़कों पर बेतरतीब वाहन पार्किंग बड़ी वजह, जाम में फंसने से घायल महिला की हो गई थी मौत

कार्यालय संवाददाता, पीलीभीत

अमृत विचार : शहर की सड़कों पर लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। दो दिन पहले ही सड़क हादसे में घायल हुई महिला की जान तक ई-रिक्शा जाम में फंसने के बाद चली गई थी। उसे समय पर उपचार नहीं मिल सका। इससे पूर्व भी इस तरह से एंबुलेंस जाम में फंस चुकी है, लेकिन समस्या की वजह बन चुके अवैध तरीके से सड़कों पर खड़े वाहन पर सख्ती हो सकी है, न ही अतिक्रमण हटाया जा सका है। कई बार ज्ञापन और धरना-प्रदर्शन के बाद भी प्रशासनिक स्तर से मुहिम ठप है। मुख्य मार्गों पर दिन में कई बार जाम से राहगीरों को जूझना पड़ रहा है।

शहर की मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण की भरमार है। बाजार से लेकर मुख्य मार्गों पर फुटपाथ पर दुकानें सजाई जा रही हैं। इसके बाद सड़क तक बेतरतीब तरीके से ग्राहकों के वाहन खड़े होते हैं। अधिकांश प्रतिष्ठानों में पार्किंग की कोई व्यवस्था तक नहीं है। इस वजह से सड़कों पर अव्यवस्था फैली हुई है। नतीजतन वाहनों की आवाजाही बढ़ते ही जाम की समस्या खड़ी हो जाती है। रेलवे स्टेशन रोड, गांधी स्टेडियम रोड, चूड़ी वाली गली, लोहा मंडी, जेपी रोड, किराना बाजार ही नहीं टनकपुर हाईवे पर भी शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण बड़े पैमाने पर हो रखा है। इसे हटाने के लिए कई बार अभियान चलाने की तैयारी की गई, लेकिन कभी व्यापारी नेताओं के विरोध तो कभी राजनीतिक दबाव में कार्रवाईयां थमती चली गई। वर्ष 2015 में तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट जितेंद्र शर्मा ने इसे लेकर जरूर सख्ती की थी। इसके बाद अवैध दुकानें तक मुख्य बाजार में ढहा दी गई थी। उस वक्त सड़कों की असल चौड़ाई दिखाई दे सकी। मगर, इस कार्रवाई को आगे जिम्मेदार बरकरार नहीं रख सके और अतिक्रमण फैलता चला गया। नतीजतन हालात बद से बदतर होते चले गए। पिछले साल जाम की दिक्कत को दूर करने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से कई ज्ञापन दिए गए और धरना प्रदर्शन भी किया। मगर, ये मुहिम भी आश्वासन घुट्टी में दबकर रह गई। इसके अलावा वेंडिंग जोन बनाने की बात कही गई लेकिन इसके बाद जिन स्थानों पर अतिक्रमण था, वहीं पर वेडिंग जोन के बोर्ड लगाकर हास्यास्पद समाधान दर्शा दिया गया। अभी दो दिन पहले ही हादसे में घायल एक महिला की मौत के मामले में सामने आया कि उसे जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो ई-रिक्शा जाम में फंस गया। जिसके बाद अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अभी भी कोई एक्शन अतिक्रमणकारियों पर नहीं लिया जा सका है। हालांकि प्रशासनिक स्तर से जल्द अभियान चलाने की बात कही जा रही है। मगर इसकी अभी कोई तिथि आदि घोषित नहीं की गई है।

गांधी स्टेडियम रोड पर फुटपाथ पर बेतरतीब खड़े वाहन। ● अमृत विचार

गौहनिया चौराहा के पहले अशोक कॉलोनी गेट के पास फुटपाथ पर अतिक्रमण।

सुनगढ़ी तिराहा पर जाम में फंसे राहगीर। ● अमृत विचार

● लंबे समय से चली आ रही मांग जिम्मेदार नहीं कर पाए समाधान

नो पार्किंग जोन घोषित स्टेडियम रोड अतिक्रमण की जद में

गांधी स्टेडियम रोड को बीते सालों में नो पार्किंग जोन घोषित किया गया था। उस वक्त इस मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के साथ ही सड़क पर खड़े होने वाले वाहनों के चालान भी किए गए थे। मगर, कुछ समय तक सख्ती जारी रही। पिछले कुछ समय में हालात ये बन चुके हैं कि इस मार्ग पर फुटपाथ पर कहीं दुकानों का सामान सजा है तो कहीं मैकेनिक शॉप चलाई जा रही है। इस मार्ग पर कई बैंक और अस्पताल भी हैं। इक्का-दुक्का को छोड़ अन्य पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा ठेले फड़ भी लगाए जा रहे हैं जिससे जाम की स्थिति दिन में कई बार बनती है। सुनगढ़ी तिराहा पर भी आए दिन जाम लगता है। बाजार में पहले ही बदतर हालात हैं।

जहां हुई कार्रवाई, अब फिर बिगड़ी तस्वीर

पिछले साल सिटी मजिस्ट्रेट के स्तर से सख्ती अपनाई गई थी। जिसके बाद रामस्वरुप पार्क के आसपास की सड़क और पुरानी सब्जी मंडी में टीम के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान कई पक्के निर्माण भी ध्वस्त किए गए थे। मगर, इसके बाद यहां पर भी दोबारा से अतिक्रमण हो चुका है। पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ इसी तरह का हाल किराना बाजार वाली सड़क का भी है। पिछली बार भी यहां पर अभियान चलाने की बात तो कही गई लेकिन बाद में एक्शन नहीं लिया गया। इसके पीछे नगर पालिका के जिम्मेदारों द्वारा रुचि न लेना वजह के तौर पर चर्चा में रहा था।

वार्ड चार में सड़क और नाली का किया लोकार्पण

संवाददाता, पीलीभीत

अमृत विचारः नगर पालिका परिषद शहर में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 28 दिन, अट्ठाइस लोकार्पण अभियान के तहत बुधवार को वार्ड नंबर चार में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का चेयरमैन डॉ. आस्था अग्रवाल ने फीता काटकर लोकार्पण किया गया। ध्रुव नर्सिंग होम से बेनहर किड्स स्कूल की ओर निर्मित सड़क एवं नाली निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया। चेयरमैन ने कहा कि शहर के प्रत्येक वार्ड में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा हैं। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है, इसे लेकर स्थानीय लोगों ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सभासद राजेन्द्र भारती, अवतार सिंह मोनू, साकेत सक्सेना, चारु अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

सड़क का लोकार्पण करती चेयरमैन डॉ.आस्था अग्रवाल।

ट्राली खड़ी करने को लेकर मारपीट

पीलीभीत, अमृत विचार : सुनगढ़ी क्षेत्र गांव रूपपुर कमालू निवासी विमला देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 8 फरवरी को जानकारी हुई कि उनके खेत पर एक ट्रैक्टर-ट्राली अवैध रूप से खड़ी है। जब वह अपने बड़े बेटे विष्णु के साथ मौके पर पहुंचीं, तो वहां गांव के ही रितेश, रितिक, कमल और महेंद्र अपने साथियों के साथ मौजूद थे।

आरोप है कि पूछने पर आरोपी ने गाली-गलौज की। विरोध करने पर लाठी डंडो से हमला कर पीटा। आरोपी रितेश ने धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया। ग्रामीणों के जमा होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है।

यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान नियमित संचालित रहेंगे सीसीटीवी

● बोर्ड परीक्षा को लेकर डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक

कार्यालय संवाददाता, पीलीभीत

अमृत विचार : अठारह फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन संपन्न कराने के लिए डीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। स्पष्ट कहा कि पूर्व में ही निरीक्षण कर बंदोबस्त परख लिए जाएं, ताकि कोई कमी हो तो उसे तत्काल दूर किया जा सके।

डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गांधी प्रेक्षागृह में यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बैठक हुई। जिसमें परीक्षा शांतिपूर्ण, नकलविहीन संपन्न कराने पर जोर दिया गया। इसमें नामित जोनल, सेक्टर, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक एवं अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापक अदि शामिल हुए। बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 69 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हाईस्कूल में 23451 व इंटरमीडिएट परीक्षा में 19903 परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। डीएम ने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए अलग से स्ट्रांगरूम की व्यवस्था की गई है। इसमें 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी होगी। निर्देश दिए कि समस्त परीक्षा केन्द्र के लिए नामित अधिकारी समय से परीक्षा केन्द्रों पर पहुंचे और अपनी निगरानी में सीसीटीवी के सामाने पेपर खोले व परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त कापियों के सील कराने का कार्य करें। परीक्षा के दौरान सीसीटीवी नियमित संचालित रहें। परीक्षा पूर्व सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करें। बुनियादी सुविधाऐं व परीक्षा केन्द्र के मानकों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अगर कोई कमी पाई गई तो तत्काल केन्द्र व्यवस्थापक ठीक कराएं। इस मौके पर एसपी सुकीर्ति माधव मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर, एसडीएम श्रद्धा सिंह, डीआईओएस राजीव कुमार आदि मौजूद रहे।

निर्देश देते डीएम ज्ञानेंद्र सिंह।

ड्यूटी वाले कर्मचारियों को साथ रखना होगा आई कार्ड

डीएम ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट व केन्द्र व्यवस्थापक के अतिरिक्त अन्य किसी कर्मचारी के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। केन्द्र पर जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है वह अपना आई कार्ड अवश्य रखें। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कोई अनावश्यक पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई तय है। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर कन्ट्रोल रूम नम्बर 05882-299844 पर बताएं।

पति समेत ससुरालियों पर रिपोर्ट दर्ज

बरखेड़ा, अमृत विचार: क्षेत्र के गांव अरसियावोझ निवासी सुंदरलाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पुत्री रोशनी देवी की शादी गांव गहलुइया पचपेड़ा निवासी प्रेम पाल से हुई थी। कुछ दिन बाद पति प्रेमपाल, ससुर धरमाईलाल, सास, जेठ जोगिंदर, जेठानी गीता देवी उसकी पुत्री के साथ मारपीट करने लगे। दहेज में घरेलू सामान,बाइक और दो लाख रुपये की मांग करने लगे। पिछले कुछ दिन पहले पुत्री को ससुराल वालों ने मारा पीटा। तभी उसे मायके ले आए। 10 फरवरी को पुत्र महिपाल, पुत्रवधू चमेली देवी के साथ पुत्री रोशनी देवी को विदा कर दिया। जैसे यह लोग ससुराल पहुंचे वैसे ही ससुरालियों ने हमला कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पत्नी के खाते में एक करोड़

घोटाले की आशंका

● 21 एनईएफटी से पत्नी के खाते में पहुंचे 24 लाख से अधिक रुपये खाता किया फ्रीज

कार्यालय संवाददाता, पीलीभीत

अमृत विचार : डीआईओएस कार्यालय में सालों से अटैचमेंट पर लेखाकार की जिम्मेदारी संभाल रहे बीसलपुर के एक इंटर कॉलेज में तैनात चर्चित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इल्हाम की पत्नी के बैंक खाते ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़े घोटाले की ओर इशारा कर दिया है। कर्मचारी की पत्नी के खाते में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से जुड़े 21 एनईएफटी के माध्यम से 24.27 लाख रुपये की धनराशि हस्तारित होना पाई गई हैं।

इन एनईएफटी को लेकर बैंक को संदिग्धता लगी, तो खाते का स्टेटमेंट चेक कराया गया। जिससे देखकर बैंक कर्मियों के भी होश उड़ गए। उस खाते में एक करोड़ से अधिक धनराशि होना पाया गया। इस पर बैंक की ओर से डीएम और ट्रेजरी को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराया गया। फिलहाल अब सीडीओ ने डीआईओएस को पत्र भेजकर इस मामले में दो दिन में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के बाद खाते को फ्रीज कर दिया गया है।

> ये मामला संज्ञान में आया है। इसे गंभीरता से लिया जा रहीा है। जांच कराई जा रही हैं, जल्द ही अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी। - राजीव कुमार, डीआईओएस

बता दें कि लंबे समय से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात इल्हाम शम्सी संबद्ध चल है। उसकी मूल तैनाती बीसलपुर के जनता इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी पद पर है। डीआईओएस कार्यालय में उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लेखाकार बनकर काम संभाल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में इल्हाम की पत्नी अर्शी खातून का बचत खाता संचालित हो रहा है। बताते हैं कि 17 दिसंबर 2025 को बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से जिलाधिकारी को इल्हाम की पत्नी अर्शी खातून के खाते में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से जुड़ी 21 एनईएफटी का जिक्र किया गया। रिपोर्ट के अनुसार अर्शी खातून के बचत बैंक खाते में तीन दिसंबर 2025 को 21 एनईएफटी के माध्यम से कुल 24,27,920 रुपये हस्तांतरित किए गए। बैंक की आंतरिक जांच में सामने आया कि छह जून 2024 से अब तक खाते में कुल 1,01,95,135 रुपये जमा किए जा चुके हैं। बैंक प्रबंधन के अनुसार खाते से अब तक 36,41,885.56 रुपये यूपीआई लेनदेन के जरिए निकाले जा चुके हैं, जबकि वर्तमान में खाते में 66.18 लाख से अधिक रुपये शेष हैं। संदिग्ध गतिविधि की आशंका पर बैंक ने खाते को फ्रीज कर दिया है ताकि आगे कोई निकासी न हो सके। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की ओर से कोषागार से इस खाते से जुड़ी रिपोर्ट मांगी गई। वरिष्ठ कोषाधिकारी की ओर दी गई रिपोर्ट में बताया कि तीन दिसंबर को किए गए 21 एनईएफटी हस्तांतरण जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय से संबंधित हैं। मामला सामने आने के बाद सीडीओ राजेंद्र श्रीवास की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक से दो दिन के भीतर जवाब तलब किया गया है। आखिरकार सरकारी धनराशि का प्रयोग निजी खाते में कैसे किया गया है। इसे लेकर खलबली मच गई है। मामला संज्ञान में आने के बाद विभाग में खलबली है।

निजी खाते में कैसे हस्तांतरित हुई सरकारी रकम

सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकारी कार्यालय से जुड़े एनईएफटी एक निजी खाते में कैसे और किन परिस्थितियों में हस्तांतरित हुए। यदि प्रारंभिक जांच में अनियमितता की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भी मुश्किल बढ़ना तय मानी जा रही है। फिलहाल बैंक, कोषागार और जिला प्रशासन की संयुक्त जांच की दिशा में मामला आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी।

यातायात नियमों का करें पालन, दूसरों से भी कराएं

कार्यालय संवाददाता, पीलीभीत

अमृत विचार : गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पूरनपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत बुधवार को सामान्य शिविर का आयोजन ग्राम नारायनपुर में किया गया। सड़क सुरक्षा जागरुकता अभियान को लेकर जागरूक किया गया। स्वयंसेवियों ने गांव में जागरुकता रैली निकाली और ग्रामीणों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। यातायात नियमों के पालन का महत्व बताया।

इसके साथ ही डोर-टू-डोर अभियान चलाकर विशेष रूप से महिलाओं को जागरूक किया गया कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य वाहन चलाने जाता है, तो उसे हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें।

कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मृदुला शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन भर नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की सुरक्षा से जुड़ा विषय है।

प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्वयं भी यातायात नियमों का पालन करे और दूसरों को प्रेरित करे। शिविर के द्वितीय सत्र में सोनू ने स्वयंसेवियों को सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने सड़क हादसों के मुख्य कारणों, सावधानियों और बचाव के उपाय पर प्रकाश डाला। युवाओं से जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया।

कार्यक्रम का समापन सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता बनाए रखने के संकल्प के साथ हुआ। इस मौके पर शाहिद खान, सुरेंद्र मौर्य, उपस्थित रहे।

बच्चों ने किया आईवीआरआई का भ्रमण

● बीएसए ने हरी झंडी दिखाकर बसों को कराया रवाना

कार्यालय संवाददाता, पीलीभीत

अमृत विचार : परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को एक्सपोजर विजिट पर बरेली आईवीआरआई ले गया गया। बीएसए रोशनी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना कराया।

बुधवार को करीब 200 स्कूली बच्चों को चार बसों से आईवीआरआई बरेली भेजा गया। बीएसए ने बताया कि इस तरह के भ्रमण से बच्चों को भौगोलिक जानकारी मिलेगी। पशु पक्षियों एवं बाहरी दुनिया से रूबरू होंगे। वह स्कूली शिक्षा के साथ-साथ देश दुनिया के बारे में जान सकेंगे। पूरनपुर, बिलसंडा, बरखेड़ा, ललौरीखेड़ा, अमरिया, मरौरी, नगर क्षेत्र के करीब दो सौ छात्र-छात्राओं को एक्सपोजर विजिट में भेजा गया। नाभिकीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला, केंचुआ पालन, पशु पक्षियों को दी जाने वाली वैक्सीन, सहित पशु पक्षियों में होने वाली बीमारियों से बचाव की भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली के सीनियर टेक्निकल ऑफीसर रवि प्रकाश ने जानकारी दी। बताया कि पशुओं में कौन-कौन से वायरस जानलेवा खतरनाक होते हैं। वैक्सीन रिसर्च के आधार पर बनाई जाती है। पशु चिकित्सा विज्ञान के अनुभाग, रिसर्च सेंटर, नेशनल एनिमल साइंस सेंटर, कृषि विज्ञान केंद्र, योगा पार्क, जैविक उत्पाद विभाग का भ्रमण कराया गया। वन्यजीव प्राणी संस्थान में छात्र-छात्राओं की बारह सिंघा, हिरन को करीब से देखा। म्यूजियम में मोर कछुआ शुतुरमुर्ग हेमू पक्षियों की जानकारी संस्थान की ओर से दी गई। जिला समन्वयक राकेश पटेल, सचिन चौधरी, राजीव कुमार, अजय कुमार, केके सागर, श्रीकृष्ण, केके सिंह, भूपेंद्र पाल सिंह, गीता रानी, करुणा गौर, मृदुला गंगवार आदि मौजूद रहे।

बस में बच्चों के साथ बीएसए रोशनी सिंह। ● अमृत विचार

भागवत कथा सुनने से मिलती है मुक्ति

बिलसंडा, अमृत विचार : गांव बमरोली के श्रीराधा रसिक बिहारी मंदिर परिसर में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया। प्रथम दिन भगवान के गुणों की महिमा का बखान किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने कथा का रसपान किया। वृंदावन से आए कथाव्यास बलरामकृष्ण महाराज ने कहा कि कैसा भी पापी मनुष्य क्यों न हो। श्रीमद् भागवत कथा सुनकर ही उसे मुक्ति प्राप्त होती है। कथा के माध्यम से भक्तों के प्रभु के निश्छल प्रेम की गाथा का श्रवण कराया। गोकर्ण और दंडकारी की कथा के बारे में बताया। आयोजक अनिल मिश्रा ने पूजन और आरती की।

बलरामकृष्ण महाराज।

पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई

कार्यालय संवाददाता, पीलीभीत

अमृत विचारः पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में बुधवार को मनाई गई। कांशीराम बारात घर में गोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह ने की।

मुख्य अतिथि क्षेत्रीय महामंत्री राकेश मिश्र अनावा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक महान नेता थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति में एकात्म मानववाद की विचारधारा को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। विशिष्ट अतिथि पीसीयू चेयरमैन सुरेश गंगवार रहे। कार्यक्रम संयोजक एवं संचालन संजीव मोहन अग्रवाल ने किया। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके सपनों को साकार करने के लिए काम करना चाहिए। उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। इस मौके पर मरौरी ब्लॉक प्रमुख सभ्यता वर्मा, जिला महामंत्री लेखराज भारती, दिनेश पटेल, जिला उपाध्यक्ष सुषमा देवी, आयुष मिश्रा, अनुराग अग्निहोत्री, अमिताभ त्रिपाठी, शांति स्वरूप सोनकर, अमरीश शर्मा, स्वतंत्र देवल महेश वर्मा, डालचंद वर्मा, सतनाम सिंह, गीता मिश्रा, सुमित गंगवार, सत्यपाल वर्मा, धर्मेंद्र लोधी, अनीता कश्यप, भरत राम राजपूत, राकेश लोधी आदि मौजूद रहे।

गोष्ठी को संबोधित करते पीसीयू सभापति सुरेश गंगवार। ● अमृत विचार

● भाजपा ने समर्पण दिवस के रूप में मनाई पुण्यतिथि, कांशीराम बारात घर में की गोष्ठी

न्यूज ब्रीफ

दंपती से मारपीट, तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

लखीमपुर खीरी, अमृत विचार : शहर से सटे गांव सुआगाड़ा निवासी अरविंद ने बताया कि वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। आरोप है कि विपक्षी कायम और जगदीश शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहे थे। जब उसने विरोध किया तो बव्वा भी मौके पर आ गया। तीनों ने मिलकर अरविंद व उसकी पत्नी पिंकी के साथ मारपीट की। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बकरियों के विवाद में महिला से मारपीट

निघासन, अमृत विचार : नगर पंचायत निघासन के आंबेडकर नगर मोहल्ला निवासी शांति देवी ने बताया कि वह घर के बाहर बकरियों की देखभाल कर रही थीं। इस दौरान पड़ोसी अनीता से बकरियों को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर अनीता ने अपने अन्य साथियों शांति, कोमल और श्रीकांत को बुला लिया। आरोप है कि सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी आंख और सीने में चोटें आईं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

तमंचा-कारतूस के साथ चार युवक गिरफ्तार

लखीमपुर खीरी, अमृत विचार : थाना खीरी एसओ निराला तिवारी ने बताया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोहल्ला डीहपुर निवासी शहबाज, मोहल्ला बाजार निवासी आदिल, मोहल्ला सैयदवाड़ा निवासी मोईद उर्फ रिहान और मोहल्ला बुखारी टोला निवासी जैफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। रिपोर्ट दर्ज कर सभी आरोपियों का चालान भेजा गया है।

पर्यटन के लिए जिले को कौड़ी भी नहीं, नाउम्मीद हुए लोग

काशी, मथुरा, अयोध्या और नैमिषारण्य जैसे स्थलों के विकास को बजट में विशेष प्रावधान

कार्यालय संवाददाता, लखीमपुर खीरी

अमृत विचार: प्रदेश के प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों के लिए बजट में जहां खुलकर धनराशि का प्रावधान किया गया है, वहीं जिले के हाथ इस बार भी खाली रह गए। काशी, मथुरा, अयोध्या और सीतापुर के नैमिषारण्य जैसे धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए, लेकिन जिले की पहचान मानी जाने वाली छोटी काशी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दुधवा टाइगर रिजर्व को प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं मिला। इससे पर्यटन से जुड़े लोगों और आम जनमानस में गहरी निराशा देखने को मिल रही है।

जिले के लोगों का कहना है कि छोटी काशी धार्मिक दृष्टि से वर्षों से आस्था का प्रमुख केंद्र रही है, जबकि दुधवा टाइगर रिजर्व प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थलों में शुमार है। इसके बावजूद बजट में इन दोनों स्थलों के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस घोषणा न होना जिले के साथ उपेक्षा जैसा माना जा रहा है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि दुधवा और छोटी काशी को बजट के माध्यम से संवारने का अवसर मिलता, तो जिले में रोजगार के नए अवसर पैदा होते। होटल, गाइड, परिवहन और स्थानीय उत्पादों से जुड़े सैकड़ों लोगों को सीधा लाभ मिल सकता था। लेकिन बजट में नाम तक न होने से उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

स्थानीय बुद्धिजीवियों और सामाजिक संगठनों का भी कहना है कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की बात तो करती है, लेकिन सीमावर्ती और वन क्षेत्र वाले जिलों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।

दुधवा जैसे पर्यटन स्थल को बेहतर सड़क, ठहराव, प्रचार-प्रसार और सुविधाओं की जरूरत है, जो बिना बजटीय सहयोग के संभव नहीं है। कुल मिलाकर, बजट में जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों की अनदेखी से विकास को झटका लगा है। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार छोटी काशी और दुधवा के लिए कुछ विशेष योजनाएं सामने आएंगी, लेकिन ऐसा न होने से जिलेवासियों में मायूसी और असंतोष साफ झलक रहा है।

छोटी काशी गोला का पौराणिक तीर्थ। ● अमृत विचार

दुधवा टाइगर रिजर्व का द्वार।

- छोटी काशी और दुधवा के लिए नहीं खुला पिटारा
- पर्यटन से जुड़े लोगों और जनमानस में निराशा

सत्तापक्ष ने सराहा, विपक्ष ने बताया निराशाजनक

बजट में किसी को फायदा होने वाला नहीं है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं, किसानों के हित की बात होनी चाहिए, लेकिन यह बजट सिर्फ छलावा है। भाजपा की सरकार में हर साल बजट तो बढ़ रहा है, लेकिन सुविधाओं को अकाल हो रहा है। बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। **-रामपाल यादव,** जिलाध्यक्ष- सपा।

प्रदेश का बजट भी महज लालीपाप

केन्द्र सरकार की तरह प्रदेश का बजट भी सिर्फ लॉलीपॉप जैसा है। धार्मिक स्थलों के नाम पर बजट देकर वोट पाने की जुगत है, लेकिन जिले को प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं मिला है। न तो फसलों के दाम बढ़ाने की बात है और न ही किसानों का हित। जिले के लिए बजट विश्वासघात की तरह है। **-प्रहलाद पटेल,** जिलाध्यक्ष- कांग्रेस।

बजट में सभी वर्गों को किया शामिल

प्रदेश की जनता को जैसी उम्मीद थी, वैसा ही सरकार ने बजट पेश किया है। युवाओं के रोजगार से लेकर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए काफी बजट दिया गया है। स्वास्थ्य की भी चिंता दिख रही है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, इससे बेटियों को स्कूल-कॉलेज तक जाने में सहूलियत होगी। **-सुनील सिंह, जिलाध्यक्ष-** भाजपा।

घोषणाएं पर्याप्त नहीं युवाओं को मिले नौकरी

बजट की भव्यता से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ सीधे युवाओं तक पहुंचे। इसके लिए समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया, योजनाओं के क्रियान्वयन में स्पष्टता, कौशल विकास के प्रभावी कार्यक्रम और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उनके ठोस और सकारात्मक परिणाम भी जमीन पर दिखाई देने चाहिए, ताकि प्रदेश का युवा वर्ग वास्तव में सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। **-संदीप कुमार वर्मा,** युवा स्वयंसेवक गोला।

यूपी बजट भी किसानों के लिए फीका

केंद्र सरकार के बजट की तरह प्रदेश सरकार से भी किसानों को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिला है। किसानों को उम्मीद थी कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश सरकार भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अंशदान देकर वार्षिक 6000 रुपये की जगह 9000 रुपये करेगी। लेकिन कुछ नहीं किया। पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों के लिए 68 .50 रुपये की बजट में सब्सिडी दी थी। किसानों को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को सब्सिडी देगी, लेकिन नहीं दी। **-पटेल श्रीकृष्ण वर्मा,** प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन।

घरेलू महिलाओं को सही नहीं लगा बजट

उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में मिशन शक्ति के अंतर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को नई गति मिलेगी। बालिकाओं को स्कूटी देने और गरीब कन्याओं की शादी में एक लाख रुपये का अनुदान देने का बजट में प्रावधान किया गया है, जो काफी सराहनीय कदम है। प्रदेश की घरेलू महिलाओं को अपने घर परिवार को चलाने एवं रसोई के सामान को सस्ता करने के लिए बजट से जो उम्मीदें थीं, उन पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। **-बबिता गुप्ता,** गृहणी गोला।

किसानों के लिए फीका रहा प्रदेश का बजट

उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में किसानों के लिए कुछ भी नया नहीं है। जो पूर्ववर्ती योजनाएं चल रहे हैं उन्हीं पर फोकस रहा है। सिर्फ आंकड़ों से पेट नहीं भरता साहब, जमीनी स्तर पर भी नजर आना चाहिए। आशा थी कि चुनावी वर्ष में कर्ज से घिरे हुए किसानों के लिए कुछ राहत मिलेगी, जो बजट में दिखाई नहीं पड़ी। सहकारी चीनी मिलों से जुड़े हुए किसानों के लिए कुछ राहत अवश्य मिलेगी। सिंचाई क्षेत्र में योजनाएं पहले से ही संचालित हैं और नया कुछ भी नहीं है। **-अंजनी कुमार दीक्षित,** जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन।

घरेलू वस्तुओं के दाम न घटने से निराशा

बजट में सी-मार्ट योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छी पहल है। इससे निश्चित ही महिला उद्यमियों के लिए बढ़ावा मिलेगा, लेकिन आम गृहिणियों और मध्यम वर्ग को किसी तरह की राहत बजट में नहीं दी गई है। प्रदेश में महंगाई को कम करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय का बजट में पूरी तरह से अनदेखी की गई है। रसोई की प्रमुख वस्तुओं के दाम घटाने के लिए भी कोई घोषणा नहीं की गई है। कुल मिलाकर बजट में ढाक के तीन पात ही नजर आ रहे हैं। **-मधुरानी सिंह,** गृहणी निवासी बादल नगर गोला गोकर्णनाथ।

बजट से कृषि क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

अनुभवी वित्त मंत्री द्वारा सबसे बड़ा बजट पेश किया गया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और छात्राओं के लिए स्कूटी योजना इस बजट का मुख्य आकर्षण है। चिकित्सा के क्षेत्र में आयुष विभाग को महत्व प्रदान किया गया है। कृषि क्षेत्र को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया गया। एक तरीके से यह 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसमें कई आकर्षक योजनाएं बनाई गई। एक ट्रिलियन प्रदेश की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। **- प्रो . पंकज सिंह,** प्राचार्य सीजीएन पीजी कॉलेज गोला गोकर्णनाथ।

व्यापारिक हित का नहीं है बजट

आंकड़ों के हिसाब से देखें तो तुम्हारे वातानुकूलित कमरों में गांव का मौसम गुलाबी दिख रहा है। बजट में 12 .9 प्रतिशत की वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, निवेश, उद्योग, स्टार्टअप में लाखों करोड़ों का निवेश कुल मिलाकर 9 .12 लाख करोड़ के ऐतिहासिक बजट के बावजूद गांव, कस्बों में व्यापारी से लेकर आम आदमी और किसान परेशान हैं। भले ही जीडीपी बढ़ रही हो लेकिन हकीकत में व्यापार खत्म हो रहे हैं। मोहल्ले के दुकान खत्म हो रही हैं, पूंजी चुनिंदा हाथों में सिमट रही है। **-महेश कुमार पटवारी,** सामाजिक कार्यकर्ता गोला।

दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए सप्ताह में दो दिन लगेगा कैंप

संवाददाता, लखीमपुर खीरी

अमृत विचार: जिला अस्पताल में दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए कई वर्षों से प्रत्येक माह सोमवार को विशेष कैंप का आयोजन किया जाता रहा है। इससे दिव्यांगजनों की भारी भीड़ रहती थी। उन्हें काफी देर तक इंतजार करने के साथ ही तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता ने बताया कि अब दिव्यांगजन पहचानपत्र कैंप सप्ताह में दो दिन आयोजित किया जाएगा। यह कैंप प्रत्येक सोमवार के साथ-साथ अब हर गुरुवार को भी लगाया जाएगा।

सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता।

- दिव्यांगों को हो रही दिक्कत को लेकर सीएमओ ने दिए निर्देश

इससे भीड़ का दबाव कम होगा और दिव्यांगजनों को अधिक सहज, सम्मानजनक और सुविधाजनक माहौल में अपना पहचान पत्र बनवाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी दिव्यांगजन को बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने बताया कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगजनों को स्वावलम्बी पोर्टल पर अपना पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) ऑनलाइन करना होगा। इसके बाद वे सोमवार या गुरुवार दोनों में से किसी भी एक दिन दिव्यांग बोर्ड के समक्ष अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पेश होकर पहचानपत्र बनवा सकते हैं। इस नई व्यवस्था से दिव्यांगजनों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें समय पर पहचानपत्र उपलब्ध हो सकेगा।

चोर पिकअप में लाद ले गए भैंस

पसगवां, अमृत विचार: थाना क्षेत्र के ग्राम हरना जाट में मंगलवार की रात महेंद्र कुमार की भैंस को चोर पिकअप पर लादकर ले गए। विरोध करने पर चोरों ने किसान की पिटाई कर दी। गांव के बाहर एक ट्रैक्टर ट्राली वाले ने भैंस को लादते हुए देखा और गांव में बताया।

महेंद्र ने भैंस गायब देख कर बाइक से पिकअप का पीछा किया। ग्राम मुड़िया चुणामणि के पास पिकअप को रोक लिया। चोरों ने पिकअप से उतर कर महेन्द्र की पिटाई कर दी और भैंस लदी पिकअप लेकर फरार हो गया। महेंद्र ने बताया कि भैंस चोरी और चोरों द्वारा पिटाई की सूचना उसने मोहम्मदपर ताजपुर चौकी पुलिस और थाना पसगवां पुलिस को दी है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई।

बजट ने तय की विकसित भारत की दिशा

संवाददाता, लखीमपुर खीरी

प्रेस वार्ता में बोलते पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी। ● अमृत विचार

- पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने की प्रेस वार्ता

अमृत विचार: केंद्रीय बजट को लेकर पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री एवं सांसद अजय मिश्र टेनी ने इसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला संतुलित और दूरदर्शी बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा नियंत्रित रहे, ताकि आर्थिक सुधार की रफ्तार धीमी न पड़े और विकास की निरंतरता बनी रहे।

पूर्व मंत्री ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब केंद्र सरकार कर्ज से अधिक राशि बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) पर खर्च करने जा रही है। उन्होंने बताया कि बजट में 12.2 लाख करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित किए गए हैं, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक आदर्श स्थिति मानी जाती है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि बाजार में पूंजी का प्रवाह भी बढ़ेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। कहा कि बजट का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक प्रबंधन से जुड़ा है-पैसा कहां से आएगा, कितना खर्च होगा, घाटा कितना रहेगा और उसे किस तरह नियंत्रित किया जाएगा।

सरकार ने इस दिशा में ऐसा प्रबंध किया है कि महंगाई पर नियंत्रण, धन की उपलब्धता, मुद्रा का मूल्य और शेयर बाजार-एक संतुलित ढांचे में आगे बढ़ें। पूर्व मंत्री ने कहा कि बजट पूरी तरह से विकसित भारत के संकल्प से जुड़ा है। विकसित भारत तभी संभव है जब देश के संस्थान मजबूत हों और मानव संसाधन की क्षमता का विकास किया जाए। इसी सोच के तहत सरकार ने कई बड़े और ठोस कदम उठाए हैं।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य मार्च 2031 तक बकाया ऋण को जीडीपी के लगभग 50 प्रतिशत तक लाना है। वर्ष 2026-27 में यह अनुपात 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो सरकार की वित्तीय अनुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष कुलभूषण सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख आशुतोष वर्मा, ब्लाक प्रमुख पवन गुप्ता, अरविंद गुप्ता, नगर अध्यक्ष देवदत्त चढ्ढा, पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद मिश्रा आदि मौजूद रहे।

समिति सचिव की बोर्ड परीक्षा में लगी ड्यूटी

संवाददाता, भीरा

अमृत विचार: सहकारी गन्ना विकास समिति अध्यक्ष डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि सचिव जगपाल सिंह को 18 फरवरी से प्रारंभ होने वाली इलाहाबाद बोर्ड परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए परीक्षा ड्यूटी में लगा दिया गया है।

इस कारण गन्ने के सीजन में चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति के इंडेंट जारी करने के साथ किसानों को समय पर गन्ना पर्ची मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही समिति क्षेत्र में लेनदेन करने वाले लगभग 25,000 किसानों को खाद लेने के लिए इंडेंट के ऋण पत्रों पर हस्ताक्षर व गन्ने की पर्चियां संबंधी समस्याओं को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना है पहले से ही यहां वरिष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक का पद खाली है।

अब सचिव प्रभारी की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में लगा दी गई। उन्होंने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और डीसीओ वेद प्रकाश सिंह से बोर्ड परीक्षा ड्यूटी से सचिव प्रभारी कार्य मुक्त करवाने की मांग की है।

विद्यालयों में होता है वंदे मातरम् का गायन

संवाददाता, गोला गोकर्णनाथ

- राष्ट्रभक्ति, विद्यार्थियों के विकास हेतु वंदे मातरम समिति के कार्य जारी

अमृत विचार: राष्ट्रभक्ति और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए वंदे मातरम समिति की पहल प्रभावशाली ढंग से जारी है। नगर सहित क्षेत्र के विद्यालयों में वंदे मातरम के सामूहिक गायन को लेकर प्रबंधक, प्रधानाचार्य से संपर्क कर उन्हें इस संबंध में पत्र सौंपकर विद्यार्थियों को जागरूक भी कर रही है।

वंदे मातरम् समिति के राष्ट्रभक्ति की भावना और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नगर सहित क्षेत्र के 25 से अधिक

स्कोरवेल स्कूल में प्रबंधक को पत्र सौंपते वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष।

विद्यालयों में प्रतिदिन वंदे मातरम् का सामूहिक गायन कराया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष अनिकेत अवस्थी, सदस्य कृष्णा ठाकुर ने समिति की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

बुधवार को समिति के पदाधिकारी स्कोरवेल इंटरनेशनल स्कूल खम्हौल पहुंचे प्रबंधक आशीष वर्मा को वंदे मातरम के सामूहिक गायन के लिए पत्र सौंपा। विद्यालय प्रबंधन ने इस पहल का समर्थन किया और नियमित रूप से वंदे मातरम् का सामूहिक गायन कराने का आश्वासन दिया।

समिति अध्यक्ष ने बताया कि वंदे मातरम् समिति का उद्देश्य विद्यालय में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना है।

बाइकों की टक्कर में तीन लोग घायल

बेहजम, अमृत विचार : थाना नीमगांव क्षेत्र में बेहजम-नीमगांव मार्ग के मुकरेहटा मोड़ के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में तीन लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान लखहा निवासी 15 वर्षीय समर्पित, सनिगवां निवासी पंकज और लखहा निवासी अभिनव के रूप में हुई है। सभी घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी में भर्ती कराया गया। जहां पर समर्पित और पंकज की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल मोतीपुर रेफर कर दिया गया है। लखहा निवासी समर्पित और अभिनव कुमार नीमगांव की ओर जा रहे थे, जबकि सनिगवां निवासी पंकज बेहजम की तरफ आ रहे थे।

सीडीओ ने खुदवाई सड़क, सैंपल भेजा

सड़क खुदवाकर नमूना एकत्र कराते सीडीओ अभिषेक कुमार। ● अमृत विचार

संवाददाता, लखीमपुर खीरी

- राजापुर-नहर पटरी फोरलेन निर्माण में गड़बड़ी पर सीधा एक्शन
- सीडीओ ने रोड पर ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की लगाई क्लास

अमृत विचार: विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन ने सख्त संदेश दे दिया है। राजापुर से नहर पटरी फोरलेन सड़क निर्माण में मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सीडीओ अभिषेक कुमार ने बुधवार को निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सीधा प्रहार किया।

सीडीओ ने मौके पर पहुंचते ही औपचारिकता छोड़ दी और सड़क की खुदाई कराकर निर्माण सामग्री का नमूना संग्रहित कराया। सैंपल को विधिवत सील कर प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया है। सीडीओ ने रोड पर ही पीडब्लूडी के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, निर्माण में हो रही लापरवाही को लेकर स्पष्ट किया कि सिर्फ कागज़ पर रिपोर्ट और औपचारिकताओं से काम नहीं चलेगा। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य को तत्काल रोक दिया और निर्देश दिया कि सिर्फ गुणवत्ता सुनिश्चित होने पर ही सड़क निर्माण जारी होगा। सीडीओ के सख्त रवैये ने अधिकारियों और ठेकेदारों में खलबली मचा दी। निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड-1 के अधिशासी अभियंता केके झां को स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि जांच में गुणवत्ता मानकों से विचलन पाया जाता है तो अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आर्थिक दंड लगाने की प्रक्रिया तय मानते हुए तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।

सीडीओ अभिषेक कुमार ने दो टूक कहा कि जनता के टैक्स के पैसे से बनने वाले कार्यों में लापरवाही अस्वीकार्य है। हर सड़क टिकाऊ, सुरक्षित और मानक अनुरूप होनी चाहिए। गुणवत्ता से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग, तकनीकी परीक्षण और समयबद्ध प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

डीएम ने किया ब्लॉक नकहा का निरीक्षण, अलमारियों से अभिलेख चेक किए

संवाददाता, लखीमपुर खीरी

अमृत विचार: बुधवार को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने विकास खंड नकहा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली, अभिलेख व्यवस्था और योजना क्रियान्वयन की संपूर्ण समीक्षा की।

डीएम ने सर्वप्रथम पीएम आवास, स्थापना एवं आवास पटल का निरीक्षण किया। अलमारियां खुलवाईं, अभिलेखों का अवलोकन किया और प्रत्येक फाइल की प्रॉपर इंडेक्सिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रखरखाव और दस्तावेज प्रबंधन में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही नियमित, संविदा और आउटसोर्सिंग कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका भी जांची गई। इसके बाद कार्यालय परिसर में शौचालय और आधार सेवा काउंटर की क्रियाशीलता भी जांची।

गोढ़ी मजरा के नन्हें अर्नित (3) और विधि (5) का आधार नामांकन कराया जाता पाया गया। अभिभावकों से पूछताछ में पता चला कि कोई फीस नहीं ली गई। जिन आधार सेवाओं के लिए शुल्क नियत है, इसका डिस्प्ले भी मौके पर मिला। निरीक्षण के दौरान एसआईआर फीडिंग काउंटर पर ऑपरेटर दिव्यांशु फीडिंग करते मिले। डीएम ने नोटिस और अभिलेखों की बारीकी से जांच की और उपस्थित फीडिंग भी देखी। डीएम ने मौके पर अर्चना की नोटिस की फीडिंग संलग्न अभिलेखों की जांच की। नोटिस के दौरान उपस्थित की फीडिंग भी देखी। इसके बाद एनआरएलएम कक्ष में जाकर स्वयं सहायता समूह, रिवाल्विंग फंड और सीआईएफ सहित हर जरूरी जानकारी ली।

ब्लाक कार्यालय के निरीक्षण में उपस्थिति पंजिका चेक करतीं डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल।

- अलमारियों में कराए प्रॉपर इंडेक्सिंग, व्यवस्थाओं पर शिकंजा

बैठक के दौरान 10 ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

विकास खंड में बैठक के दौरान डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बीडीओ संगीता यादव को निर्देशित किया कि विकास के लिए उपलब्ध धनराशि का उपयोग नहीं करने वाली दस ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाए। डीएम ने कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता विकास कार्यों की पूर्णता और पारदर्शिता है और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समूहों की संख्या और उनकी सक्रियता पर भी निगाह रखी।

डीएम ने ब्लॉक परिसर में मूलभूत सुविधाओं सहित वहां संचालित विभिन्न कार्यालय और पटलों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की पड़ताल की।इसके बाद डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बीडीओ कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान प्रमुख क्षेत्र पंचायत पवन गुप्ता, बीडीओ संगीता यादव सहित विकासखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने स्थापना, बजट, स्टोर, स्टाफ की स्थिति, पीएम और सीएम आवास योजनाओं की प्रगति और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका भी देखी।

पीडी डीआरडीए को निर्देशित किया कि विकास खंडों में तैनात जिन कार्मिकों की डीपीसी पेंडिंग या कोई अन्य देयक लंबित हैं उन्हें नियमानुसार कराया जाए।

अमृत विचार

बरेली, गुरुवार, 12 फरवरी 2026

न्यूज ब्रीफ

नगर के मुख्य मार्गों से हटेगा अतिक्रमण

गोला गोकर्णनाथ, अमृत विचार : नगर के मुख्य मार्गों पर महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात निकलती है। शिव बारात में ट्रैक्टर, ट्राली, बैंड बाजा, डीजे सहित तमाम श्रद्धालु शामिल होते हैं, सीओ रमेश कुमार तिवारी ने बताया कि शिव बारात के मुख्य मार्गा के पटरी दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस ने नोटिस देकर दो दिन का समय दिया है। सभी पटरी दुकानदार निर्धारित अवधि में अतिक्रमण हटा लें ताकि शिव बारात निकलने वाले का मार्ग में कोई असुविधा न हो।

अशोभनीय टिप्पणी करने पर रिपोर्ट दर्ज

गोला गोकर्णनाथ, अमृत विचार : नगर निवासी पटेल संस्थान के अध्यक्ष राजीव पटेल ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहां है कि लखीमपुर रोड निवासी पियूष कुमार शुक्ला पुत्र रामकुमार शुक्ला ने ओबीसी वर्ग के लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिससे ओबीसी समाज की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

मंदिर का स्थापना दिवस समारोह आज से

गोला गोकर्णनाथ, अमृत विचार : खुटार रोड स्थित दतेली गांव में मां दुर्गा मंदिर कमेटी के प्रबंधक दुष्यंत कुमार वर्मा ने बताया कि 26वां मां दुर्गा जी का स्थापना दिवस 12 फरवरी गुरुवार को अखंड पाठ से प्रारंभ होगा। 13 को अखंड पाठ समापन, 14 को कलश पूजन, हवन और 15 फरवरी रविवार महाशिवरात्रि पर्व पर संत महात्माओं का अभिनंदन, कन्या भोज और भंडारा होगा।

दुर्घटना में घायल प्रधान की मां की मौत

बरवर, अमृत विचार : दस दिन पहले सड़क दुर्घटना में घायल हुईं गांव रसूलपुर तफज्जुल हुसैन निवासी ग्राम प्रधान अनुराग वर्मा की माता राजेश्वरी (55) का लखनऊ के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह लखीमपुर-मैगलगंज मार्ग पर औरंगाबाद से एक किमी पहले किसी अज्ञात वाहन के कार में टक्कर मारने से घायल हो गई थी। लखनऊ के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बुधवार को उनकी मौत हो गई।

बोर्ड परीक्षा में 3 हजार शिक्षकों की ड्यूटी

129 केंद्रों पर होगा कड़ा पहरा, 90 हजार से ज्यादा छात्र देंगे इम्तिहान, 18 फरवरी से बोर्ड परीक्षा होगी

कार्यालय संवाददाता, लखीमपुर खीरी

अमृत विचार: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना तेज कर दिया है। बुधवार को शहर के गुरु नानक इंटर कॉलेज में एडीएम नरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में एडीएम ने स्पष्ट किया कि परीक्षा की शुचिता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। प्रत्येक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाए और परीक्षा के दौरान पूरी सतर्कता बरते। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, वितरण और संधारण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और गोपनीयता के साथ संपन्न कराने पर विशेष जोर दिया गया। इस वर्ष जिले में कुल 129 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड परीक्षा में कुल 90,244 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें 49,980 हाईस्कूल तथा 40,264 इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राएं शामिल हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे सक्रिय कर दिए गए हैं तथा सुरक्षित स्ट्रांग रूम की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। परीक्षा से पूर्व सभी केंद्रों का निरीक्षण भी किया जा चुका है।

डीआईओएस विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि केंद्र व्यवस्थापक, सह-केंद्र व्यवस्थापक और स्टेटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम एक घंटे पूर्व केंद्र पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। प्रश्नपत्र निर्धारित समय पर स्ट्रांग रूम से निकालकर कड़ी निगरानी में कक्षों तक पहुंचाए जाएंगे। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात रहेंगे और सीसीटीवी कैमरों से निरंतर निगरानी की जाएगी। एएसपी पूर्वी पवन गौतम, बीएसए प्रवीण तिवारी सहित अन्य अधिकारियों ने भी तैयारियों की जानकारी दी।

बैठक को संबोधित करते एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह। ● अमृत विचार

बैठक में मौजूद शिक्षक। ● अमृत विचार

दिव्यांग परीक्षार्थियों को मिलेगा स्क्राइबर

बोर्ड परीक्षा में शामिल दिव्यांग छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर स्क्राइबर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सभी केंद्र व्यवस्थापकों को पूर्व में ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यदि किसी केंद्र पर स्क्राइबर या अन्य विशेष व्यवस्था को लेकर समस्या आती है तो तत्काल डीआईओएस कार्यालय से समन्वय कर समाधान कराया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी दिव्यांग परीक्षार्थी की परीक्षा प्रभावित नहीं होने दी जाएगी।

100 मीटर परिधि में फोटोस्टेट दुकानें रहेंगी बंद

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में स्थित फोटोस्टेट व साइबर कैफे की दुकानों को परीक्षा अवधि में बंद रखा जाएगा। इस संबंध में संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रों के आसपास धारा 144 के तहत शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

करीब तीन हजार शिक्षकों की लगेगी ड्यूटी

बोर्ड परीक्षा संचालन के लिए लगभग तीन हजार शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसमें 50 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा विभाग और 50 प्रतिशत बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक शामिल होंगे। सभी शिक्षकों को समय से ड्यूटी स्थल पर पहुंचने और परीक्षा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

छात्र को छात्रवृत्ति का चेक देते प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार वाजपेयी। ● अमृत विचार

अवध प्रांत में तृतीय स्थान प्राप्त छात्र सम्मानित

संवाददाता, मैगलगंज

● प्रधानाचार्य ने छात्र को दिया 5100 रुपये की छात्रवृत्ति का चेक

अमृत विचार: नगर स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय के मेधावी छात्र राम प्रताप सिंह को अवध प्रांत स्तर पर सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 5100 की छात्रवृत्ति का चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया।

विद्यालय के प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार वाजपेयी ने मंच पर छात्र को चेक दिया। उन्होंने छात्र के परिश्रम, अनुशासन और लगन की सराहना की। प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य परीक्षा परिणाम तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में संस्कार, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का विकास करना भी है। अवध प्रांत में प्रतिवर्ष कक्षा 5 एवं 8 के मेधावी भैया-बहनों के लिए सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित की जाती है। परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम तीन स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। गत सत्र में आयोजित परीक्षा में राम प्रताप सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया, जबकि लक्ष्य गुप्ता ने चतुर्थ स्थान हासिल कर सफलता अर्जित की। सम्मान समारोह के दौरान राम प्रताप सिंह के माता-पिता भी मौजूद रहे।

श्याम भक्ति में सराबोर हुई छोटी काशी

संवाददाता, गोला गोकर्णनाथ

अमृत विचार: नगर में बाबा खाटू श्याम की निशान यात्रा धूमधाम से निकाली गई। निशान यात्रा में काफी तादात में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं के हाथ में बाबा खाटू श्याम से सुसज्जित निशान थे। डीजे और बैंड की धुनों पर श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए निकले। नगर में कई जगह लोगों ने पुष्पवर्षा से यात्रा का स्वागत किया। जिससे पूरा नगर श्याममय हो गया।

बुधवार सुबह नीलकंठ मैदान से शुरू होकर खाटू श्याम निशान शोभायात्रा नगर के प्रमुख मार्गा पर होते हुए मोहम्मदी रोड कंजा बाबा देवस्थान स्थित खाटू श्याम मंदिर पर पहुंच कर पूजन, अर्चन और प्रसाद वितरण के साथ यात्रा का समापन हुआ। भावपूर्ण वातावरण में श्रद्धालु हारे के सहारे, श्याम प्यारे, श्याम प्यारे के जयकारे लगाते हुए ढोल, नगाड़े, डीजे की धुन पर बाबा के भजन गाते, झूमते बाबा की भव्य झांकी और दरबार सजाकर प्रमुख मार्गों पर निकले। लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया। रंग, गुलाल के साथ बाबा के निशान ध्वज को लेकर श्रद्धालु थिरकते नजर आए, जिससे माहौल पूरी तरह श्याममय हो गया। कंजा बाबा स्थित श्याम मंदिर पहुंचने पर भक्तों ने बाबा खाटू श्याम को निशान अर्पित किए और दर्शन कर मंगलकामना की। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल मौजूद रहा। श्याम बाबा की निशान यात्रा में विधायक अमन गिरि, नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू, धर्मेंद्र गिरि मोंटी, नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल, विपिन मिश्रा, समिति अध्यक्ष दीपक राजपूत, अनिरुद्ध गुप्ता, सुधीर गुप्ता आदि मौजूद रहे।

गोला में श्याम बाबा की निशान यात्रा में शामिल श्रद्धालु। ● अमृत विचार

● लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया यात्रा का स्वागत

सड़क पर डीजे की धुन पर नागिन डांस, जाम में फंसी एम्बुलेंस

कार्यालय संवाददाता, लखीमपुर खीरी

● बिना किसी आयोजन के दिन में थमा शहर, संकटा देवी चौराहे से मेला मैदान रोड तक लगा जाम

अमृत विचार: प्रशासनिक अधिकारियों और यातायात पुलिस की इसे लापरवाही कहा जाय या फिर अनदेखी। शहर वासियों को जाम से निजात मिलती नहीं दिख रही है। जाम को लेकर बनाए गए नियम और आदेश सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। मंगलवार रात शहर के सलेमपुर कोन नौरंगाबाद स्थित नामे महाराज कोठी के पास डीजे की तेज धुन पर नागिन डांस सड़क के बीचों-बीच होने के कारण यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार की रात डीजे की आवाज पर युवकों का समूह सड़क पर ही नाच-गाना कर रहा था। इस दौरान किसी ने यातायात की व्यवस्था संभालने की कोशिश नहीं की। राहगीरों और वाहन चालकों को काफी देर इंतजार करना पड़ा। एम्बुलेंस के सायरन बजाने के बावजूद भीड़ नहीं हटी, जिससे लोगों में आक्रोश था। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस तरह लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

चार दिन पूर्व ही कोतवाली सदर में एसडीएम सदर और सीओ सदर की मौजूदगी में डीजे संचालकों एवं गेस्ट हाउस मालिकों के साथ बैठक आयोजित की थी। बैठक में साफ निर्देश दिए गए थे कि किसी भी हाल में सार्वजनिक मार्ग पर कार्यक्रम नहीं होंगे और यातायात बाधित नहीं किया जाएगा। साथ ही ध्वनि प्रदूषण और समय सीमा का कड़ाई से पालन करने को कहा गया था। इसके बावजूद सड़क पर खुलेआम नियमों की अनदेखी से प्रशासनिक सख्ती पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस मौके पर पहुंचकर व्यवस्था संभालती तो एम्बुलेंस को जाम में नहीं फंसना पड़ता। अब देखना होगा कि प्रशासन इस प्रकरण में क्या कार्रवाई करता है।

उधर बुधवार को शहर की यातायात व्यवस्था उस समय चरमरा गई। जब संकटा देवी चौराहे से मेला मैदान रोड तक भीषण जाम लग गया। हैरानी की बात रही कि न तो शादी-ब्याह था। न बैंड-बाजा, न बारात और न ही किसी मैरिज लॉन में बड़ा आयोजन था। इसके बाद भी सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब डेढ़ घंटे लोग जाम में फंसे रहे।

नौरंगाबाद रोड पर जाम में फंसी एंबुलेंस। ● अमृत विचार

> जाम की समस्या को लेकर यातायात पुलिस को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी।
>
> -पवन गौतम, एएसपी पूर्वी।

पुण्यतिथि पर पं. दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि

गोला में पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते पालिकाध्यक्ष।

संवाददाता, गोला गोकर्णनाथ

अमृत विचार: नगर पालिका अध्यक्ष ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए उनके आदर्शों के बारे में बताया।

नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने कार्यकर्ताओं के साथ अलीगंज रोड दीनदयाल उपाध्याय मार्केट पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद का दर्शन और अंत्योदय का दृष्टिकोण समाज के अंतिम व्यक्ति को ऊपर उठाना था। वर्तमान केंद्र और प्रदेश की सरकार का विकास मॉडल उनसें ही प्रेरित है।

भाजपा नगर अध्यक्ष शत्रोहन मिश्रा, कुम्भी मण्डल अध्यक्ष रविन्द्र कटियार, नगर मंत्री धीरज वाजपेयी, महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता विश्वकर्मा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष विजय झा, ज्ञानू तिवारी आदि मौजूद रहे।

नैनो खाद के प्रयोग पर दिया जोर किसानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

संवाददाता, सिंगाही

अमृत विचार: खैरीगढ़ साधन सहकारी समिति परिसर में सहकारी शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन विनीत मनार रहे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी प्राप्त की।

मुख्य अतिथि विनीत मनार ने कहा कि बदलते समय के साथ कृषि पद्धतियों में सुधार करना आवश्यक है। उन्होंने सभी किसानों से अपील की कि वे अपना किसान रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराएं, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं और सहकारी संस्थाओं की सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए नैनो खाद के प्रयोग पर विशेष जोर दिया। कहा कि नैनो यूरिया और अन्य उन्नत उर्वरकों के संतुलित उपयोग से लागत में कमी आएगी और पैदावार में वृद्धि होगी।

कार्यक्रम में कृभको के क्षेत्रीय प्रबंधक ज्ञानेंद्र यादव ने किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर चालित एवं पेट्रोल से चलने वाली स्प्रे मशीनें उपलब्ध कराने की घोषणा की। अरविंद यादव ने भी किसानों को सहकारी समितियों से जुड़कर उन्नत बीज, खाद और तकनीकी मार्गदर्शन लेने की सलाह दी। इस अवसर पर सिंगाही सहकारी बैंक के प्रबंधक जगन्नाथ, समिति अध्यक्ष पंकज सिंह, उपाध्यक्ष राकेश जायसवाल, संचालक दिलीप रस्तोगी, मोनू त्रिवेदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिलोकीनाथ देवड़िया, पूर्व प्रधान श्रीराम सिंह, सभासद आशीष भंडारी, शिशिर गुप्ता, अनूप भंडारी, प्रदीप श्रीवास्तव, समिति सचिव रवी शुक्ला आदि किसान उपस्थित रहे।

सम्मेलन में बोलते जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन मुख्य अतिथि विनीत मनार।

● साधन सहकारी समिति पर आयोजित हुआ सम्मेलन

डॉ. योगेंद्र को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार

लखीमपुर खीरी, अमृत विचार: जिले के लिए गौरव की बात है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज (यूपी बोर्ड) के प्रधानाचार्य डॉ. योगेंद्र प्रताप सिंह का चयन मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए किया है। जिले से पुरस्कार के लिए पहली बार किसी शिक्षक का चयन हुआ है, जिससे शिक्षा जगत में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए हाल ही में आवेदन आमंत्रित किए थे। जनपद से कुल तीन शिक्षकों में से डॉ. योगेंद्र प्रताप सिंह को राज्य स्तरीय चयन समिति ने साक्षात्कार एवं प्रस्तुतीकरण के आधार पर चयनित किया है। प्रदेश भर से पांच शिक्षकों का चयन किया गया, जिसमें डॉ. योगेंद्र प्रताप सिंह का नाम शामिल है। डॉ. सिंह को आगामी पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, साथी घायल

कार्यालय संवाददाता, लखीमपुर खीरी

● मनीष अपने साथी नन्नू के साथ काम से खीरी जा रहे थे

● गंभीर घायल को जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया

अमृत विचार: थाना खीरी क्षेत्र में कस्बे के बाहर कार ने मंगलवार की शाम एक बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया है। सदर कोतवाली के सलेमपुर निवासी मनीष कश्यप (25) अपने साथी नन्नू के साथ किसी काम से खीरी कस्बा जा रहे थे।

कस्बे के बाहर पेट्रोल पंप के पास अज्ञात कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा, जहां से डॉक्टर ने मनीष कश्यप को मृत घोषित कर दिया, जबकि हालत गंभीर होने पर नन्नू को लखनऊ रेफर कर दिया है। परिवार वालों के मुताबिक नन्नू की 11 फरवरी यानी बुधवार को सगाई थी। सगाई की तैयारियां घर पर जोरों से चल रहीं थीं। हादसे में मृतक मनीष कश्यप अविवाहित थे और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में बॉडी रिपेयरिंग का काम करते थे। युवक की मौत से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

मनीष कश्यप।

बच्चों ने स्कूल के वार्षिकोत्सव में मचाई धूम

संवाददाता, मूड़ा सवारान

अमृत विचार: क्षेत्र के अंबे इंटर कॉलेज शिवपुरी में स्कूल का वार्षिकोत्सव बुधवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया, साथ ही कक्षा 10 व 12 के विद्यार्थियों का भावनात्मक विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि गोला विधायक अमन गिरि ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। बच्चों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद अलग-अलग गानों पर बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं। साथ ही नाट्य मंचन कर बच्चों ने खूब तालियां बटोरीं। विद्यालय प्रबंधक विनोद सोनी ने कहा कि बच्चों का चौमुखी विकास करना ही शिक्षकों का दायित्व होता है। विद्यालय में बेहतर शिक्षा मिले यह हमारी प्राथमिकता है।

मुख्य अतिथि विधायक अमन गिरि ने कहा कि विदाई का यह क्षण खुशी और विषाद दोनों भावनाओं का संगम होता है। एक ओर विद्यालय से बिछड़ने का भाव होता है तो दूसरी ओर जीवन में नए सपनों और नए आयाम की ओर कदम बढ़ाने की खुशी।कार्यक्रम समापन पर बच्चों को पुरस्कृत किया गया। संचालन रियाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया। इस मौके पर बिजुआ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि वीरेंद्र भूषण, अभिषेक कुमार, कालेज प्रधानाचार्य विवेक वर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कश्मीर सिंह, बिजुआ प्रधान संघ अध्यक्ष ओंमकार सिंह, पंकज बाजपेई, सुशील शर्मा, विजयकांत श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

अंबे इंटर कॉलेज में पुरस्कृत बच्चों संग अतिथि। ● अमृत विचार

● मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ विदाई समारोह संपन्न

मछुआरे के जाल में फंसा नवजात का शव

मितौली, अमृत विचार: थाना क्षेत्र मितौली की पुलिस चौकी मढ़िया बाजार क्षेत्र के दतेली खुर्द गांव के बाहर उस समय सनसनी फैल गई, जब मछली पकड़ने के लिए मछुआरे के डाले गए जाल में नवजात का शव आ गया। इससे हड़कंप मच गया। गांव दतेली खुर्द में धोबहैय्या तालाब में बुधवार को मछली पकड़ने के लिए मछुआरे ने तालाब में जाल डाला तो उसमें एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ। यह देख मछुआरे जाल छोड़कर भाग गए। शव पड़ा होने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मढ़िया बाजार चौकी प्रभारी लल्लन सिंह भी पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि आखिर नवजात के शव को तालाब में किसने और किन परिस्थितियों में फेंका है।

मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कलश यात्रा से शुरू

संवाददाता, सिंगाही

अमृत विचार: कस्बे के मेन सर्राफा बाजार स्थित जीर्णोद्धार कर बनाए गए नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आरंभ बुधवार को कलशयात्रा के साथ हुआ। कार्यक्रम में भारी संख्या में में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

महारानी सुरथ कुमारी मेन रोड सर्राफा बाजार में प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कस्बे के स्वर्णकार समाज की पहल पर कराया है। मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद बुधवार से 16 फरवरी तक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का पांच दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया जा रहा है।

बुधवार को कार्यक्रम का आरंभ हुआ। मंदिर परिसर में पंडित सोनेलाल मिश्र की आचार्य मंडली ने मुख्य यजमान राहुल सोनी से मंत्रोच्चार के साथ पूजन कराया। इसके बाद महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली।

कलश यात्रा मेन बाजार से होते हुए मेला मैदान पहुंची। वहां से श्रद्धालु वाहनों के माध्यम से मसुरहा घाट के पास सरयू नदी तट पर पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पवित्र जल भरा गया। जल लेकर श्रद्धालु पुनः मंदिर पहुंचे और सभी कलशों को विधिपूर्वक मंदिर परिसर में स्थापित किया गया।

पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं की भीड़ और भक्ति गीतों से वातावरण शिवमय हो गया। आयोजन में पूर्व चेयरमैन प्रदीप कुमार पुरवार, दुर्गा मंदिर अध्यक्ष उत्तम सोनी, पुरुषोत्तम सोनी, प्रेम सोनी, आलोक सोनी, दीपू सोनी, आनंद सोनी, धर्मू मौर्य, अनुराग पुरवार सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। 16 फरवरी को पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन होगा।

कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु। ● अमृत विचार

टिन शेड समेत दीवार गिरी, दंपती की मौत, दो बच्चियां घायल

पिलर टूटने से हुआ हादसा, टिन शेड के नीचे पोतियों के साथ सोये थे दंपती

संवाददाता, धौरहरा

अमृत विचारः शारदा नगर थाना क्षेत्र के गांव लौखनिया में बुधवार तड़के दर्दनाक हादसा हो गया। टीनशेड का लकड़ी का पिलर टूटने से टीन सहित पक्की दीवार भरभराकर ढह गई। मलबे के नीचे दबने से चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग दंपति और उनकी दो पोतियां घायल हो गईं। घायलों को सीएचसी रमियाबेहड़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने वृद्धा को मृत घोषित कर दिया। जबकि उसके पति ने लखनऊ जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।

गांव लौखनिया निवासी छोटन्न यादव (65) पुत्र गोकुल यादव अपनी पत्नी कृष्णावती (58) और पोतियां पिंकी (11) व बबली (9) पुत्री दिनेश यादव के साथ घर के टिन शेड में सो रहे थे। परिवार के अन्य सदस्य दिनेश यादव, कौशल और पैरू घर के अलग-

कृष्णावती।

छोटन्न यादव।

अलग हिस्सों में थे। ग्रामीणों के अनुसार सुबह करीब 6:15 बजे टिन शेड का लकड़ी का पिलर अचानक टूट गया, जिससे टिन और उससे सटी पक्की दीवार तेज धमाके साथ गिर गई।

अचानक हादसे से घर में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर पड़ोसी और ग्राम प्रधान अखिलेश वर्मा मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला। शारदा नगर पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी रमियाबेहड़ भेजा। वहां चिकित्सकों ने कृष्णावती को मृत घोषित कर दिया, जबकि

घटना स्थल पर जांच करती पुलिस। • अमृत विचार

अन्य घायलों का उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालत में सुधार न होने पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने छोटन्न यादव को लखनऊ रेफर कर दिया। उन्हें परिजन एम्बुलेंस से लखनऊ ले जा रहे थे।

रास्ते में सीतापुर के पास बुजुर्ग ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। हादसे की सूचना पर एसडीएम शशिकांत मणि और तहसीलदार आदित्य विशाल मौके पर पहुंचे। राजस्व लेखपाल से रिपोर्ट तलब की। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। प्रभारी निरीक्षक शारदा नगर मनोज कुमार सिंह ने बताया बुजुर्ग दंपती की मौत हो गई है, घायल दोनों बच्चियों का इलाज चल रहा है।

हाथियों ने रौंदी किसानों की फसल

मझगई, अमृत विचारः मझगईं वन रेंज के तहत बौधिया कलां में मंगलवार रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। झुंड ने 24 से अधिक किसानों की खड़ी फसल रौंद डाली, जिससे कई एकड़ में लगी सरसों, गन्ना और केले की फसल पूरी तरह तबाह हो गई। बुधवार सुबह जब किसान खेतों पर पहुंचे तो फसल जमीन पर बिछी मिली। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, वनकर्मी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। हाथियों द्वारा रौंदी गई फसलों में अशोक कुमार की दो बीघा गन्ना, राजू की दो बीघा, मोहन जायसवाल की दो बीघा, हरद्वारी की दो बीघा, सोबरन की दो बीघा, दीनबंधु की तीन बीघा, रामसिंह की चार बीघा, हेमेंद्र की तीन बीघा, नरेंद्र की चार बीघा, मन्नू सिंह की एक बीघा, दयाराम की चार बीघा, कपिल सिंह की तीन बीघा और हरपाल यादव की एक बीघा फसल शामिल है। इसके अलावा अन्य किसानों की भी फसलें नुकसान की जद में हैं।

डीआरएम के नाम स्टेशन अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन

संवाददाता, गोला गोकर्णनाथ

अमृत विचारः नगर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आकर गोवंशों की लगातार हो रही मौतों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ा रुख अपनाया है। मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) लखनऊ को संबोधित ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक को सौंपा है।

भारतीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष अनूप गुप्ता के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा है कि नौ फरवरी को गाड़ी 15009 इज्जत नगर एक्सप्रेस के सुबह 10.15 बजे स्टेशन पर आगमन के दौरान प्लेटफार्म और ट्रैक की जांच न होने के कारण दो गोवंशों की मृत्यु हो गई तथा एक गंभीर घायल हो गया। आरोप है कि स्टेशन मास्टर और रेलवे प्रशासन की लापरवाही के चलते इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने मांग की है कि ट्रेन आने से पहले अनिवार्य रूप से प्लेटफार्म और ट्रैक की जांच कराई जाए तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। स्थानीय लोगों ने रेलवे से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और गोवंशों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। यहां जिला अध्यक्ष अनूप गुप्ता के साथ संदीप गुप्ता, हर्षित, रचित, नितिश, विपिन कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, सम्पूर्णानगर, जिला-खीरी

ई-निविदा सूचना

मिल समिति में वर्ष 2025-26 में Supply of PM Analyzer Sensor Etc. से सम्बन्धित ई-बिड निविदायें दिनांक 11.02.2026 से दिनांक 18.02.2026 को सायंकाल 6:55 बजे तक आमंत्रित की गयी है। उक्त निविदायें **www.etender.up.nic.in** एवं **www.upsugarfed.org** पर देखी जा सकती है। **प्रधान प्रबन्धक**

महिला से मांगी रंगदारी वीडियो वायरल की धमकी

शाहजहांपुर, अमृत विचार : सदर बाजार थाना क्षेत्र की महिला ने थाने में दी तहरीर में बताया कि एक साल से गाजी खान निवासी एमनजई जलालनगर थाना सदर से रिलेशनशिप में थी। आरोपी अंटा चौराहे पर एक कैफे में उसे ले गया। आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान आरोपी ने मोबाइल से वीडियो बना ली। अब उसका ब्रेकअप हो गया है। आरोपी उसकी फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी के नाम पर दो लाख रुपये मांग रहा है। प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज की है

हिरासत में लेकर संदिग्धों से पूछताछ

संवाददाता, बेहजम

- **12 से अधिक हिरासत में संदिग्ध फिर भी नतीजा सिफर**
- **दौदापुर में 50 लाख रुपये की चोरी का मामला**

> चार टीमें सर्विलांस और क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर लगातार कार्य कर रही हैं। शीघ्र ही घटना का खुलासा कर घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। **-प्रवीर कुमार गौतम**, एसओ नीमगांव

अमृत विचारः नीमगांव थाना क्षेत्र के दौदापुर गांव में डेढ़ लाख की नगदी और 50 लाख के जेवर चोरी मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। स्थानीय पुलिस के साथ ही घटना में लगी स्वाट टीम ने 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक की जांच में पुलिस के हाथ ऐसे कोई सबूत नहीं लगे हैं, जिससे पुलिस घटना में शामिल लोगों की अभी तक पहचान भी नहीं कर सकी है।

7 फरवरी को अभिजीत प्रताप सिंह के घर चोरी हुई थी। शुरुआती दौर पर चोरी को संदिग्ध बताकर रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी कर रही पुलिस ने फजीहत कराने के बाद तीसरे दिन रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस पीड़ित परिवार पर तहरीर से जेवरों की कीमत और संख्या हटाने का दबाव बना रही थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। एसपी ने घटना के खुलासे में क्राइम ब्रांच की स्वॉट टीम, सर्विलांस टीम को भी लगाया है। टीमें लगातार क्षेत्र में संदिग्धों के घरों पर दबिश दे रही है। अब तक करीब 12 संदिग्ध पुलिस की हिरासत में हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए संदिग्ध थाना क्षेत्र के अलावा सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर के भी शामिल हैं। मंगलवार देर शाम बीटीएस पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। पुलिस सर्विलांस की मदद से संदिग्धों की कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी पहलुओं से जांच कर रही है। साथ ही पीड़ित परिवार के बैंक खातों की भी पड़ताल की जा रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी बिंदुओं की गहराई से जांच हो सके।

बेहजम में सत्यापन अभियान तेज

बेहजम। नीमगांव थाना क्षेत्र में चोरी और लूट की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बेहजम पुलिस चौकी प्रभारी सिद्धांत पवार के नेतृत्व में पूर्व में इन अपराधों में संलिप्त रहे आरोपियों का सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। पुराने, हिस्ट्रीशीटर और संदिग्ध प्रवृत्ति के व्यक्तियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। पुलिस टीमें उनके वर्तमान निवास स्थान, आजीविका के स्रोत, गतिविधियों और आपराधिक संपर्कों की जानकारी जुटा रही हैं। जिन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है, उन्हें विशेष निगरानी सूची में शामिल किया गया है। चौकी प्रभारी ने चिन्हित व्यक्तियों को प्रत्येक सप्ताह थाना या चौकी पर आकर हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। बाजार, बैंक, ज्वैलरी दुकानों और संवेदनशील स्थानों पर भी गश्त बढ़ा दी गई है।

गरीब मजदूर किसान पार्टी के दुर्गेश बने नगर अध्यक्ष

गोला में मनोनीत पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र सौंपते राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरनलाल।

संवाददाता, गोला गोकर्णनाथ

अमृत विचारः गरीब मजदूर किसान पार्टी की बैठक अलीगंज रोड स्थित दुर्गेश सोनी के प्रॉपर्टीज कार्यालय पर हुई। बैठक में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन लाल, राष्ट्रीय सचिव कृष्ण कुमार यादव, चमन लाल यादव, जिलाध्यक्ष जसकरन लाल वर्मा ने दुर्गेश सोनी को पार्टी का नगर अध्यक्ष, आशीष गुप्ता नगर कोषाध्यक्ष, अमित त्रिपाठी नगर महामंत्री, सौरभ पुरवार को नगर संगठन मंत्री का दायित्व सौंपा है। इस मौके पर मनोज वर्मा, सुशील वर्मा, अनिरुद्ध गुप्ता, फुरकान खान, आमिर खान सईदी, अचल अवस्थी मोनू, विक्रांत गिरि आदि व्यापारी व किसान मौजूद रहे।.

सड़क हादसे में घायल छात्र की मौत, चालक पर रिपोर्ट

तिलहर, अमृत विचार : जैतीपुर थाना क्षेत्र के बंथरी गांव निवासी संजेश के पुत्र सुधांशु की सड़क हादसे में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। संजेश के अनुसार 4 फरवरी की सुबह सुधांशु बरखेड़ा मार्ग स्थित पिथनापुर के स्कूल जा रहा था। आरोप है कि पिथनापुर गांव के ट्रैक्टर चालक कर्मवीर उर्फ कटीले ने उसे टक्कर मार दी। सुधांशु ट्रैक्टर में फंस गया और कई मीटर तक घसीटा गया। घायल छात्र को शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 10 फरवरी को डॉ. ने उसे बरेली रेफर किया, लेकिन उसी रात रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिता ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

विद्युत चोरी में फर्जी नो-ड्यूज जारी कर लाखों रुपये की ठगी

संवाददाता, लखीमपुर खीरी

> अधिशासी अभियंता रवींद्र कुमार सिंह यादव ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों के खिलाफ थाना ईसानगर पुलिस को तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शिवशंकर शुक्ला, आलोक मिश्रा एवं ललित मिश्रा के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। **-निर्मल तिवारी**, थाना प्रभारी।

अमृत विचारः विद्युत चोरी के मामलों में शमन शुल्क और राजस्व निर्धारण के नाम पर उपभोक्ताओं से लाखों रुपये की ठगी कर फर्जी नो-ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। विद्युत वितरण खंड निघासन के अधिशासी अभियंता की तहरीर पर थाना ईसानगर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

निघासन विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता रवींद्र कुमार सिंह यादव ने बताया कि थाना एंटी पावर थेफ्ट लखीमपुर की जांच में कहा है कि दिनेश लाल गुप्ता, शत्रोहन लाल गुप्ता निवासी खमरिया, कमलाकांत गिरि व रमाकांत गिरि निवासी मटरिया थाना खमरिया, संजय श्रीवास्तव निवासी अदलीसपुर व जगदीश प्रसाद व बसंत निवासी सिरसी थाना ईसानगर के विरुद्ध पूर्व में विद्युत चोरी के मामले दर्ज हुए थे। इन प्रकरणों में खंड कार्यालय द्वारा शमन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण किया गया था। आरोप है कि उक्त राजस्व निर्धारण एवं शमन शुल्क जमा कराने के नाम पर आलोक मिश्रा निवासी ईसानगर ने दिनेश लाल गुप्ता, शत्रोहन लाल गुप्ता, कमलाकांत गिरि व रमाकांत गिरि से कुल 1,60,000 रुपये लिए। इसी प्रकार ललित मिश्रा निवासी नौरंगपुर थाना ईसानगर ने संजय श्रीवास्तव, जगदीश प्रसाद व बसंत से 80,000 रुपये वसूले। तहरीर में आरोप है कि आलोक मिश्रा और ललित मिश्रा ने उक्त धनराशि शिवशंकर शुक्ला निवासी ढखनिया कोतवाली धौरहरा को देने की बात कही। आरोप है कि शिवशंकर शुक्ला ने संबंधित उपभोक्ताओं के नाम से फोटो एडिटिंग के माध्यम से कूट रचित फर्जी नो-ड्यूज प्रमाण पत्र तैयार किए, जिन पर फर्जी रसीद संख्या अंकित कर अधोहस्ताक्षरी अधिकारी के जाली हस्ताक्षर एवं मुहर स्कैन कर चिपकाई। ये फर्जी दस्तावेज उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए गए। जब विभागीय अभिलेखों का मिलान किया तो संबंधित धनराशि जमा न होने और दस्तावेजों के फर्जी होने का खुलासा हुआ।

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना : ओटी-18-2025

उप मुख्य विद्युत इंजीनियर / निर्माण, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्यो के लिये ''खुली'' निविदा आमंत्रित की जाती है। **निविदा सं०:**- ओटी-18-2025, **कार्य का विवरणः**- कुसुम्ही-गोरखपुर- डोमिनगढ़ तीसरी लाइन और गोरखपुर- नकहा दोहरीकरण परियोजना के अन्तर्गत गोरखपुर में 25 केवी, 50 हट्र्ज, सिंगल फेज, एसी नए स्विचिंग पोस्ट (एसएसपी) का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग का कार्य। **अनुमानित लागतः**- रु. 1,48,35,483.35, **बयाना राशिः**- रु. 2,24,200.00, **निविदा प्रपत्र का मूल्य** - रु निल, **कार्य पूर्ण करने की अवधि** - 06 माह, **निविदा बन्द होने की अंतिम तिथि व समयः** 05.03.2026 को 15.00 बजे।, **नोटः** • इस निविदा के विरुद्ध कोई मैनुअल आफर स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे प्राप्त मैनुअल आफर को उपेक्षित कर दिया जायेगा। विस्तृत विवरण व निविदा जमा करने हेतु कृपया भारतीय रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** को देखें।, • निविदा सूचना में यदि हिन्दी या अंग्रेजी के आलेखों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के ही आलेख मान्य होगें।

उप मुख्य विद्युत इंजीनियर/निर्माण, गोरखपुर
मुजाधि/विद्युत-277

ट्रेनों में बीड़ी/सिगरेट न पियें

कार्यालय ग्राम पंचायत ढकनी रजपुरी वि.खं. भुता बरेली

पत्रांक: 108/लेखा/निविदा/वर्ष 2025-26 दिनांक: 08.01.2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ढकनी रजपुरी में मनरेगा योजना के अन्तर्गत मुकेश पन्डित के घर से हरप्रसाद के घर तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण कार्य होना है। जिसकी लागत 2.50 लाख है। इच्छुक फर्म सीमेन्ट, बजरफुट, बजरी, रेता, प्रथम ईट, रोड़ा आदि आपूर्ति हेतु दिनांक 17.02.2026 तक निविदा आमंत्रित की जाती है। जिन्हें कार्यालय ग्राम पंचायत में दिनांक 18.02.2026 तक जमा कर सकते हैं। जिन्हें उसी दिन शाम 4 बजे खोला जायेगा। जिस फर्म का टेन्डर सबसे कम दर का होगा उसे स्वीकार किया जायेगा।

नरेन्द्र कुमार प्रधान — **अजेय यादव** सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत सिठौरा वि.खं. भदपुरा (बरेली)

निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक : 12.02.2026

समस्त अधिकृत फर्मो व विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सिठौरा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत निम्न निर्माण हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु पंजीकृत फर्मो से निविदा आमंत्रित की जाती है। सामग्री विवरण निम्नवत् है। ईट, बजरफुट, सरिया, सीमेंट, रेज, बजरी व अन्य सामग्री जो प्राक्कलन में लिखित है। निविदा पंचायत कार्यालय पर दिनांक 12.02.2026 से 14.02.2026 तक किसी समय खोली जा सकती है। कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति आदि की सूचना किसी कार्यालय दिवस में देखी जा सकती है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	माप	अनु. लागत
1.	पूरनलाल की बैठक से नहर तक सी.सी. रोड व पक्की नाली निर्माण	95x4 मीटर	2,86,500.00

अभिषेक सिंह-सचिव — **वीरवती-ग्राम प्रधान**

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
193-ए, सिविल लाइन्स, बरेली मण्डल, बरेली

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कृष्ण पाल सिंह द्वारा अध्यक्ष की हैसियत से करन सिंह मैमोरियल पब्लिक शिक्षा समिति, ग्राम महताबपुर पो. खास तह. दातागंज जिला बदायूं का नाम परिवर्तन कर संस्था का नया नाम करन सिंह मैमोरियल संस्कृत पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, ग्राम महताबपुर पो. खास तह. दातागंज जिला बदायूं करने हेतु प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है। वर्तमान में प्रबन्धकारिणी समिति की सूची में निम्नलिखित पदाधिकारी/सदस्य है-

क्र.सं.	नाम/पिता/पति का नाम	पद
1.	श्री कृष्णपाल सिंह पुत्र श्री करन सिंह	अध्यक्ष
2.	श्री शिवओम पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्री राजकपूर उर्फ अभिषेक पुत्र श्री देवेन्द्र पाल	प्रबन्धक
4.	श्री पप्पू सिंह पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह	कोषाध्यक्ष
5.	श्री रानी पत्नी श्री कृष्णपाल	सदस्य
6.	श्रीमती आरजू पत्नी श्री राजकपूर उर्फ अभिषेक	सदस्य
7.	प्रियंका पुत्री श्री रविकान्त	सदस्य

उपरोक्त संस्था का नाम परिवर्तन किये जाने में यदि सम्मानित पदाधिकारी/सदस्य को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर फोटोयुक्त नोटरीशपथ पत्र के माध्यम से आपत्ति पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त निर्धारित अवधि में किसी की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जायेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तत् उपरान्त आपत्ति के अभाव में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भू.पू./वर्ममान पदाधिकारी/सदस्यों की होगी। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना/नोटिस सोसा. रजि. एक्ट 1860 की धारा-4 के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

सहायक रजिस्ट्रार, बरेली।

पूर्वोत्तर रेलवे ई-ऑक्शन सूचना

सं. सी/54/खानपान/ई ऑक्शन दिनांक 10.02.2026

वरि. मंडल वाणिज्य प्रबन्धक/इज्जतनगर द्वारा आई.आर.ई.पी.एस. (IREPS) पर पंजीकृत संस्थाओं से ई-ऑक्शन के माध्यम से खानपान ठेकों हेतु बोलियाँ आमंत्रित की जा रही हैं। ऑक्शन कैटलाग को आई.आर.ई.पी.एस. (IREPS) की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर प्रकाशित किया जा चुका है। इज्जतनगर मंडल की आगामी ई-ऑक्शन का विवरण निम्नवत है-

श्रेणी	कैटलॉग सं.	ऑक्शन प्रारंभ	ऑक्शन समापन
खानपान	IZN-CAT-26-01	20.02.26/12:00:00	20.02.26/13:50:00

क्रम	स्टेशन	स्टेशन कोड	श्रेणी	ऑक्शन के लिए इकाई	चिन्हित इकाई	प्लेटफार्म सं.
01	गंजडुंडवारा	GWA	डी	जीएमयू/स्टाल	अनारक्षित	01
02	कमालगंज	KLJ	डी	जीएमयू/स्टाल	अनारक्षित/महिला	01
03	सिकंदराराउ	SKA	डी	जीएमयू/स्टाल	अनारक्षित	01
04	रुदायन	RDN	डी	जीएमयू/स्टाल	अनारक्षित	01
05	फतेहगढ़	FGR	डी	जीएमयू/स्टाल	अनारक्षित	01
06	निगोही	NOH	ई	जीएमयू/स्टाल	अनारक्षित	01
07	कम्पिल रोड	KXF	ई	जीएमयू/स्टाल	अनारक्षित/महिला	01
08	उझानी	UJH	डी	एसएमयू/स्टाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	01
09	पीपलसाना	PLS	ई	एसएमयू/स्टाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	01

1. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि ई-ऑक्शन से सम्बन्धित जानकारी के लिए रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** देखें। 2. उक्त ई-ऑक्शन, आई.आर.ई.पी.एस. (IREPS) के ई-ऑक्शन लीजिंग मॉड्यूल के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। 3. ई-ऑक्शन संबंधित समस्त जानकारी जैसे पात्रता, कार्य का दायरा, ठेके की अवधि, नियम एवं शर्तें आदि आई.आर.ई.पी.एस. (IREPS) की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। 4. बोलीदाता उक्त दिये गये दिनांक एवं समय के अनुसार ही ई-ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। 5. सभी संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ई-ऑक्शन से संबंधित किसी भी शुद्धिपत्र हेतु नियमित रूप से रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** का अवलोकन करते रहें।

मुजाधि/वाणिज्य-257 — **सहायक वाणिज्य प्रबन्धक/इज्जतनगर**

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बदायूँ।
ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रण सूचना

No. : 166 / Nivida(E-T.)/ 2025-26 Date : 05-02-2026

1. महामहिम राज्यपाल, उ0 प्र0 की ओर से अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोनिवि बदायूँ के अन्तर्गत निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार ऑनलाइन ई-निविदा दि0 13.02.2026 से दि0 19.02.2026 की दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की गयी हैं:-

2.

Sr. No.	District	Name of work	Estimated cost (in Rs. Lacs)	Bid Security (in Rs.lac)	Cost of Bid Document (Rs.)	Time of completion	Address of Executive Engineer Executing the work	Address of Superintending Engineer	Address of Chief Engineer	Eligible category of Contractor
1	2	3	0	5	6	7	8	9	10	11
1	Budaun	वर्ष 2024-25 में विधानसभा क्षेत्र बिसौली के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण मार्गो पर गडढा मुक्ति एवं पैच मरम्मत का कार्य।	32.10	3.21	Tender Cost+ Stationery Charges+ GST Rs.944.00	Four Month	C.D. P.W.D., Budaun	Budaun-Pilibhit Circle, P.W.D. Bareilly	Bareilly Zone P.W.D., Bareilly	A,B,C,D
2	Budaun	वर्ष 2024-25 में विधानसभा क्षेत्र बिसौली के अन्तर्गत पड़ने वाले राज्य मार्ग/अजिमा पर गडढा मुक्ति एवं पैच मरम्मत का कार्य।	30.40	3.04	Tender Cost+ Stationery Charges+ GST Rs.944.00	Four Month	C.D. P.W.D., Budaun	Budaun-Pilibhit Circle, P.W.D. Bareilly	Bareilly Zone P.W.D., Bareilly	A,B,C,D
3	Budaun	वर्ष 2024-25 में विधानसभा क्षेत्र सहसवान के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण मार्गो पर गडढा मुक्ति एवं पैच मरम्मत का कार्य।	28.70	2.87	Tender Cost+ Stationery Charges+ GST Rs.944.00	Four Month	C.D. P.W.D., Budaun	Budaun-Pilibhit Circle, P.W.D. Bareilly	Bareilly Zone P.W.D., Bareilly	A,B,C,D
4	Budaun	वर्ष 2024-25 में विधानसभा क्षेत्र सहसवान के अन्तर्गत पड़ने वाले राज्य मार्ग मार्गो पर गडढा मुक्ति एवं पैच मरम्मत का कार्य।	32.60	3.26	Tender Cost+ Stationery Charges+ GST Rs.944.00	Four Month	C.D. P.W.D., Budaun	Budaun-Pilibhit Circle, P.W.D. Bareilly	Bareilly Zone P.W.D., Bareilly	A,B,C,D
5	Budaun	वर्ष 2024-25 में राज्य मार्ग/अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गो पर गडढा मुक्ति एवं पैच मरम्मत हेतु बिसौली स्थित विभागीय हॉट मिक्स प्लाण्ट पर ग्रिट आपूर्ति का कार्य।	28.70	2.87	Tender Cost+ Stationery Charges+ GST Rs.944.00	Four Month	C.D. P.W.D., Budaun	Budaun-Pilibhit Circle, P.W.D. Bareilly	Bareilly Zone P.W.D., Bareilly	A,B,C,D

3- बिड डाक्यूमेन्ट वेबसाइट http://etender.up.nic.in. पर दिनांक 13.02.2026 से 19.02.2026 तक उपलब्ध है, निविदाये दिनांक 19.02.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक अपलोड की जा सकती हैं। इसकी तकनीकी बिड दिनांक 19.02.2026 को दोपहर 12.30 बजे खोली जायेगी।

निविदा से सम्बन्धित अधिक जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

UP - 245765 दिनांक: 10/02/2026
विज्ञापन वेबसाइट www.up.gov.in पर उपलब्ध है।

(देवपाल सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., बदायूँ।

कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, बरेली सम्भाग, बरेली

पत्रांक : 2972/स्वी.अनु./गे.ख./परि.-ई-निविदा/2026-27/बरेली दिनांक : 10.02.2026

अल्पकालीन ई-टेण्डर नोटिस

कार्यालय आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ.प्र. जवाहर भवन, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 5471/अ.आ.वि./रा.वि.व.-01/2026-27 दिनांक 29.12.2025 के साथ संलग्न शासनादेश सं.- 380/29-5-2025 (ई.2000859) दिनांक 24.12.2025 के द्वारा रबी विपणन वर्ष 2026-27 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय व्यवस्था संबंधी समय सारिणी में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं. 591/29-4-2023/4013(99)/7/2022 दिनांक 16.05.2023, शासनादेश सं. 1215/29-4013(99)7/2022 दिनांक 15.09.2022, शासनादेश सं.-571/29-4-2023/4013(99)/ 7/2022 दिनांक 03.05.2023, शासन के पत्र संख्या 831/29-4-2023-385/19 दिनांक 25.07.2023 एवं अपर आयुक्त (विपणन), खाद्य तथा रसद विभाग, उ.प्र. जवाहर भवन लखनऊ के पत्रांक 3773/अ.वि.श./है.परि./परि.दर/359/2022 दिनांक 25.07.2023 के साथ संलग्न राज्य स्तरीय कमेटी (एस.एल.सी.) की दिनांक 10.07.2023 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 2893/स्वी.अनु./गे.ख./परि./ई-निविदा/2026-27/बरेली दिनांक 02.02.2026 के द्वारा प्रथम बार बरेली सम्भाग के जनपद बरेली, बदायूं, पीलीभीत एवं शाहजहांपुर में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नामित समस्त क्रय एजेन्सियों से सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा स्वीकृत गेहूँ क्रय केन्द्रों से निर्धारित/सम्बद्ध भारतीय खाद्य निगम डिपो तक गेहूँ के परिवहन कार्य हेतु (एस.एल.सी. द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में) शेड्यूल दर के सापेक्ष ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ई-निविदायें आमंत्रित की गयी थी।

उक्त ई-टेण्डर के उपरांत मण्डल में विज्ञापित केन्द्रों पर परिवहन कार्य हेतु विचारणीय निविदा न प्राप्त होने वाले अवशेष केन्द्रों एवं जिलाधिकारी बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर द्वारा स्वीकृत नवीन गेहूँ क्रय केन्द्रों पर संलग्न सूची (सूची सं. 01) के अनुसार समस्त क्रय संस्थाओं के गेहूँ परिवहन कार्य हेतु जनपद बरेली के 6, जनपद बदायूं के 23 जनपद पीलीभीत के 07 एवं जनपद शाहजहांपुर के 18 कुल 54 गेहूँ क्रय केन्द्रों पर पुनः ई-टेण्डर आमंत्रित किये जाते है।

शासनादेश सं. 380/29-5-2025 (ई.2000859) दिनांक 24.12.2025 में निर्धारित व्यवस्थान्तर्गत क्रय केन्द्रों का चयन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत/प्रस्तावित क्रय केन्द्रों में से किसी क्रय केन्द्र का चयन नहीं किया जाता है अथवा चयन के उपरान्त निरस्त किया जाता है तो क्रय केन्द्र हेतु डाली गयी समस्त परिवहन कार्य की निविदायें निरस्त समझी जायेगी। संलग्न सूची के अनुसार रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत गेहूँ परिवहन कार्य हेतु ई-निविदायें जनपदवार, केन्द्रवार प्राप्त की जायेगी। निविदादाता द्वारा प्रत्येक केन्द्र के लिए पृथक-पृथक निविदा संलग्न किये जायेंगे तथा निविदा शुल्क (प्रत्येक केन्द्र हेतु) एवं धरोहर धनराशि के रिसीट/यू.टी.आर. की ''स्कैन्ड कापी'' ऑनलाइन निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता द्वारा अपलोड की जायेगी। परिवहन कार्य हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र मूल्य, धरोहर धनराशि निविदा विशिष्टीकरण निविदा खुलने की तिथि एवं अन्य सम्बन्धित जानकारी http://etender.up.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। परिवहन कार्य हेतु निविदा प्रपत्र शुलक 500+90(जी.एस.टी.)=590/- तथा प्रत्येक निविदा के साथ परिवहन कार्य के लिये धरोहर धनराशि रू. 15,000/- सम्भागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (खाद्य), बरेली के पदनाम से खाता संख्या 0232104000190848 आई.एफ.एस.सी. कोड IBKL0000232 आई.डी.बी.आई. बैंक सिविल लाइन्स बरेली में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. से जमा किया जायेगा। प्रत्येक निविदा के साथ निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि के रिसीट/यू.टी.आर. की ''स्कैन्ड कापी'' ऑनलाइन निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता द्वारा अपलोड की जायेगी।

निविदा प्रपत्र ऑनलाइन वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर दिनांक 17.02.2026 को अपरान्ह 02:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है। टेक्निकल बिड दिनांक 17.02.2026 को अपरान्ह 03:00 बजे तदर्थ गठित ई-निविदा समिति के द्वारा ऑनलाइन खोली जायेगी। टेक्निकल बिड के प्रपत्रों की जांचोपरान्त इसमें अहर्य निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। तदोपरांत वित्तीय, निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, बरेली के पास सुरक्षित होगा।

निविदा की शर्त में परिवर्तन तथा शुद्धि पत्र आदि की सूचना केवल ई-टेण्डर वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध होंगे।

(डा. मनिकन्डन ए.)
आई.ए.एस.
सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक,
बरेली सम्भाग, बरेली।

अमृत विचार

गुरुवार, 12 फरवरी 2026

डीपफेक पर शिकंजा

एआई के दौर में डीपफेक लोकतंत्र, निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। आईटी नियमों में हालिया संशोधन, डीपफेक और एआई-जनित सामग्री की नई परिभाषाएं, निर्दिष्ट सामग्री को शीघ्रता से हटाने का अनिवार्य प्रावधान नियामकीय ढांचे को ताकत देंगे। ये इस चुनौती से निबटने का सराहनीय प्रयास है। संशोधित नियमों में 'एआई-जनित या सिंथेटिक मीडिया', 'डीपफेक', 'मॉर्फ्ड या मैनिपुलेटेड कंटेंट' और 'भ्रामक लेबलिंग' जैसी स्पष्ट परिभाषाएं शामिल करने के बाद प्लेटफॉर्म का यह तर्क कि सामग्री 'यूजर-जनरेटेड' है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी सीमित है, कुतर्क में बदल गया है। अब यदि कोई ऑडियो-वीडियो एआई जनित है और उसे वास्तविक बताकर प्रसारित किया गया, तो साफ बताना होगा। गंभीर मामलों में शिकायत होने के तीन घंटे के भीतर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को इसे हटाना या निष्क्रिय करना होगा। यह प्रावधान महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, मैसेजिंग सेवाओं, वीडियो-शेयरिंग साइट्स और होस्टिंग प्रदाताओं सभी पर लागू होगा।

आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत प्लेटफॉर्म को 'सेफ हार्बर' सुरक्षा मिलती है, यानी यूजर की पोस्ट के लिए वे स्वतः दोषी नहीं माने जाते। अब नए नियमों के तहत यदि प्लेटफॉर्म समयबद्ध तरीके से डीपफेक हटाने, लेबलिंग और शिकायत-निवारण अपनाएंगी, तभी उनकी सेफ हार्बर सुरक्षा बचेगी। इसका अर्थ है कि अब उनकी जिम्मेदारी अधिक है और बचाव की गुंजाइश थोड़ी कम, हालांकि इन संशोधनों के बाद भी यह चुनौती बाकी है कि नियम मुख्यतः शिकायत-आधारित हैं, कंटेंट हटाने की प्रक्रिया तब सक्रिय होती है, जब कोई यूजर शिकायत करे और सरकार उस संबंधित सामग्री को फ्लैग करे। डीपफेक का शिकार स्थानीय पुलिस के साइबर सेल में एफआईआर दर्ज करा सकता है, साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकता है अथवा ग्रिवेंस ऑफिसर को ईमेल के जरिये औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकता है। पर सवाल यह है कि हर यूजर दिन रात इसकी बात पर निगरानी नहीं रख सकता कि वह कब कहां और किस प्लेटफॉर्म पर डीपफेक का शिकार हो चुका है। इस मामले में आम उपयोगकर्ता विकल्पहीन नजर आता है, इसलिए भले ही एआई टूल्स सुलभ हैं और 'क्राइम-एज़-ए-सर्विस' मॉडल ने इसे संगठित अपराध का रूप दे दिया हो, नये नियमों के सख्त लेबलिंग, त्वरित टेकडाउन और ट्रेसबिलिटी से नुकसान को किंचित कम किया जा सके, लेकिन अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्लेटफॉर्म को प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, एआई-आधारित डिटेक्शन और जोखिम-आधारित फ्लैगिंग अपनानी ही होगी। सर्विस प्रोवाइडर समय सीमा में कार्रवाई नहीं करता, तो सेफ हार्बर तत्काल समाप्त होने, भारी जुर्माने के साथ उसके विरुद्ध आपराधिक मामला बनना चाहिए, लेकिन यहां स्पष्ट आर्थिक दंड और पीड़ित के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र का अभाव है, जो नियमों को कमजोर बनाएगा। जब तक अनुपालन न करने पर ठोस दंड, जैसे- राजस्व-आधारित जुर्माना, अस्थायी निलंबन या लाइसेंस शर्तें स्पष्ट न हों, तब तक नियमों की प्रभावशीलता सीमित रहेगी।

प्रसंगवश

स्वराष्ट्र, स्वभाषा के पक्षधर थे महर्षि दयानंद सरस्वती

महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे युग पुरुष थे, जिन्होंने सामाजिक कुरीति उन्मूलन, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, सामाजिक समरसता के लिए काम कर समाज सुधार की नई क्रान्ति का सूत्रपात किया। उन्होंने देश में स्वराज्य तथा आजादी की भावना को सुदृढ़ किया। महर्षि दयानंद और उनका आदर्श था- 'कृण्वंतो विश्वमार्यम्' ॥ अर्थात, हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, हम पूरे विश्व में श्रेष्ठ विचारों का, मानवीय आदर्शों का संचार करें, इसलिए, 21वीं सदी में आज जब विश्व अनेक विवादों में फंसा है, हिंसा और अस्थिरता में घिरा हुआ है, तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी का दिखाया मार्ग करोड़ों लोगों में आशा का संचार करता है।

उनका जन्म 12 फरवरी, 1824 को गुजरात के टंकारा में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम मूल शंकर तिवारी था। उनके माता-पिता यशोदाबाई और लालजी तिवारी

सुधांशु टाक
लेखक

समर्पित हिंदू थे। छोटी उम्र में ही उनमें आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति गहरी रुचि विकसित हो गई और उन्होंने मूर्ति पूजा, अनुष्ठानों और अंधविश्वासों पर प्रश्न उठाए।

19 वर्ष की उम्र में सांसारिक जीवन त्यागकर, वे सत्य की खोज में लगभग 15 वर्षों तक एक तपस्वी के रूप में भ्रमण करते रहे। उन्होंने मथुरा में स्वामी विरजानंद से शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म से भ्रष्ट प्रथाओं को समाप्त करने तथा वेदों के सच्चे अर्थ को पुनर्स्थापित करने के लिए काम करने का आग्रह किया। जब महर्षि दयानंद जी का जन्म हुआ, तब देश सदियों की गुलामी से कमजोर पड़कर अपनी आभा, अपना तेज, अपना आत्मविश्वास, सब कुछ खोता चला जा रहा था। प्रतिपल हमारे संस्कारों को, हमारे आदर्शों को, हमारे मूल्योंर को चूर-चूर करने की लाखों कोशिशें होती रहती थीं। जब किसी समाज में गुलामी की हीन भावना घर कर जाती है, तो आध्यात्म और आस्था की जगह आडंबर आना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में महर्षि दयानंद जी ने आगे आकर वेदों के बोध को समाज जीवन में पुनर्जीवित किया। उन्होंने समाज को दिशा दी, अपने तर्कों से ये सिद्ध किया और उन्होंने ये बार-बार बताया कि खामी भारत के धर्म और परंपराओं में नहीं है। खामी है कि हम उनके वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और विकृतियों से भर गए हैं।

स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्वभूषा, स्वसंस्कृति और स्वतंत्रता के प्रबलतम पक्षधर महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे दिव्य राष्ट्र पुरुष थे, जिनका संपूर्ण चिंतन और कार्य जहां आध्यात्मिकता से ओतप्रोत था, वहीं राष्ट्र उनके लिए प्रथम था। महर्षि दयानंद मानते थे कि व्यक्ति की सर्वांगीण उन्नति 'स्व' से ही प्रारंभ होती है। किसी भी क्षेत्र की पराधीनता व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए अधोगति का कारण बनती है। पराधीन व्यक्ति चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है।

भारतवर्ष की स्वाधीनता के लिए एकदम साफ और बुलंद शब्दों में आवाज उठाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति महर्षि दयानंद ही थे और इसके लिए कष्ट और अमानवीयता की सीमा तक यातनाएं सहने वाले अधिकांशतः व्यक्ति देव दयानंद के अनुयाई और पथानुगामी ही थे। उसे समय के प्रायः सभी युगपुरुष और महापुरुष जहां कुछ एक क्षेत्र में कार्य करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ रहे थे वहां मात्र महर्षि दयानंद ने संपूर्ण क्रांति के लिए कार्य किया। अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना से भी पहले सन् 1874 में ऋषि दयानंद सरस्वती ने 'आर्याभिविनय' की रचना की थी। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था- 'अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी शासन न करें। हम कभी पराधीन न हों।'

हम खेलना बंद नहीं करते, क्योंकि हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं।

–जार्ज बर्नाड शॉ, आइरिश लेखक

उत्तराखंड के लिए संजीवनी बनेगी होमस्टे की नीति

अमित शर्मा
हल्द्वानी

पर्वतीय और पर्यटन राज्य की बेशुमार खूबियां समेटे उत्तराखंड के लिए होमस्टे की नयी नीति को किसी संजीवनी से कम नहीं आंका जा सकता है। होमस्टे के कॉन्सेप्ट ने न केवल यहां रोजगार के द्वार खोले हैं, बल्कि अकल्पनीय पर्यटन का विस्तार भी किया है। प्रदेश के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे अलग से पहाड़ की लोक संस्कृति, परंपरा, संस्कार और स्थानीय उत्पादों की पहचान देश-विदेश में करवा रहा है। मात्र 10 वर्षों में होमस्टे का प्रचलन राज्य के कोने-कोने में पैर जमाने में सफल हुआ है।

अलग राज्य बनने के बाद प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की थी जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं को मजबूरन पलायन करना पड़ रहा था और पलायन रोकना ही प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी चुनौती रहती आई है। रोजगार के अभाव में प्रदेश में गांव के गांव वीरान होने लगे थे। इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए कोई युक्ति नहीं थी, लेकिन करीब दस वर्ष पहले होमस्टे का कॉन्सेप्ट वापसी की लौ बनकर सामने आया। यह देखने में बेहद मामूली नजर आ रहा था, लेकिन रोजगार के साथ पर्यटन के विस्तार का बड़ा मार्ग था। कुछ वर्ष यूं ही बीत गए और करीब छह बरस पहले इसके महत्व को समझते हुए प्रदेश सरकार ने होमस्टे को आगे ले जाने के लिए युवाओं को इससे जोड़ने व प्रेरित करने का अभियान शुरू कर दिया।

दरअसल, यह पर्यटन की ऐसी अवधारणा थी, जिसमें खर्च न के बराबर और आकर्षण अनूठा था। अधिक कुछ न कर पुराने घरों को संवारना था और पर्यटक के रूप में आने वाले मेहमानों को घर जैसे प्यार के साथ आवभगत करना था। कुमाऊं और गढ़वाल की संस्कृति सैकड़ों वर्ष पुरानी है, जो देश और दुनिया में अलग पहचान रखती है, लेकिन इसका विस्तार तभी संभव था, जब महानगरों से लोग आएं और यहां की संस्कृति, सौहार्द, खान-पान और रहन-सहन की अनुभूति को अनुभव कर सकें।

उत्तराखंड के लिए होमस्टे की नई नीति को किसी संजीवनी से कम नहीं आंका जा सकता। होमस्टे के कॉन्सेप्ट ने न केवल यहां रोजगार के द्वार खोले हैं, बल्कि पर्यटन का विस्तार भी किया है।

प्रदेश के पारंपरिक कुमाऊंनी, गढ़वाली घर मिट्टी-पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। पर्यावरण संरक्षण की झलक और उदाहरण देते प्रतीत होते हैं। पर्यटकों के लिए यह ऐसा आकर्षण और अनुभव है, जो कल्पना से परे होता है। मगर इस अहसास को जगाने के लिए सैलानियों की मौजूदगी बेहद जरूरी थी। इस बीच कोविड महामारी शुरू हो गई। यह महामारी अभिशाप जरूर थी, लेकिन राज्य के होमस्टे का सुहाना सफर यहीं से शुरू हुआ। पलायन कर चुके युवाओं का रिवर्स पलायन शुरू हो गया और उनके लिए उन्हें जब होमस्टे के बारे में पता लगा तो उन्हें अपने सपनों का संसार घर में बसाने का सुनहरा अवसर मिल गया।

एक खास बात यह भी है कि उत्तराखंड की एक विशेष पहचान कुकिंग को लेकर भी रही है। गांव छोड़ महानगरों की शरण लेने वाले लोगों में एक तबका बड़े-नामी होटलों में खाना बनाने में माहिर माने जाते हैं। यह ऐसा हुनर है, जो होमस्टे की सफलता की बुनियाद है। यही वजह है कि वर्तमान में प्रदेशभर में 6545 होमस्टे सफलता के साथ संचालित हो रहे है और 20 हजार से अधिक लोग इन होमस्टे में आजीविका कमाने के साथ अपनी जड़ों से वापस जुड़ रहे हैं।

इसमें जरा भी संदेह नहीं कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता दुनिया में अलग और बेपनाह खूबसूरत है। इधर, होमस्टे ने जहां रोजगार की दिशा में बड़ा कदम उठाया, वहीं प्रदेश की तमाम खूबियों के चलते देश-विदेश के लोगों के प्रति आकर्षण पैदा किया है। देवभूमि की बड़ी विशेषता यहां का भोजन है, जो औषधि का काम करता है। गहत और भट्ट की दाल और राजमा का कोई सानी नहीं। इसके अलावा बिच्छू समेत पहाड़ी सब्जियों का भंडार ग्रामीण अंचलों में उपलब्ध है, जो शहरों की हाईब्रिड सब्जियों से कहीं अधिक उत्तम व ऑर्गेनिक है। भाग दौड़ भरी जिंदगी से पहाड़ों का सुकून व शांति का वातावरण पर्यटकों को बेहद भाने लगा है। आदर सत्कार, स्नेह, प्रेम और संस्कार, जो होटलों में संभव नहीं, वह होमस्टे में मिलता है। कम खर्च और ढेर सारी मौज-मस्ती का आनंद होमस्टे में मिल जाता है। यही वजह है कि वर्तमान में होटलों की जगह होमस्टे की मांग बढ़ने लगी है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने बीते माह होमस्टे योजना को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए अहम बदलाव किए। इसके अनुसार, अब केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही होमस्टे योजना का लाभ उठा सकते हैं, हालांकि अन्य राज्यों के होम स्टे संचालक बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में शामिल होंगे, जिन्हें जीएसटी और व्यावसायिक दरों पर बिजली-पानी मिलेगा। नई 'उत्तराखंड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली-2026' का स्पष्ट उद्देश्य स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा करना है।

इस योजना के बड़े फायदों में, स्थानीय निवासियों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और रिवर्स पलायन में यह योजना संजीवनी का काम करेगी। पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम आएगी। स्थानीय होने के चलते वे स्वयं पहाड़ व अपने आसपास की संस्कृति, विशेषताओं से मेहमान पर्यटकों को बता सकेंगे। स्थानीय होम स्टे संचालकों को बिजली और पानी की सुविधा घरेलू दरों पर मिलने से उनकी लागत भी कम होगी।

पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी कहते हैं कि होमस्टे दूरदराज के ग्रामीण अंचल के लिए किसी वरदान से कम नहीं। प्रदेश की बड़ी आबादी दूर गांवों में रहती है, जहां रोजगार के रूप में होमस्टे लोगों का जीवन स्तर बदल रहा है। होमस्टे खोलने को लेकर सरकार 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है, तो बैंक से मिलने वाले ऋण में बैंक ब्याज में 50 फीसद छूट दे रहा है। होमस्टे ने रिवर्स पलायन में बड़ी भूमिका निभाई है। ग्रामीण विकास और पलायन आयोग की रिपोर्ट 2025 के अनुसार 6000 से अधिक प्रवासी अपने गांवों में लौटकर अधिकांश होमस्टे का स्वरोजगार कर रहे हैं।

आमने

आपने भारत बेच दिया है। क्या आपको भारत बेचने में शर्म नहीं आती? आपने हमारी मां, भारत माता को बेच दिया है। आपको पता है उन्होंने भारत क्यों बेचा? क्योंकि वे उनका गला घोंट रहे हैं। उन्होंने उनकी गर्दन पकड़ रखी है। हम प्रधानमंत्री की आंखों में डर देख सकते हैं।

–राहुल गांधी
नेता प्रतिपक्ष

आपने कहा कि इन्होंने देश बेच दिया, पर मैं कहना चाहता हूं कि आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, जो देश को बेच सके और न कोई है जो हमारे देश को खरीद सके। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश के अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।

–किरेन रिजिजू
संसदीय कार्यमंत्री

सामने

बजट: चुनावी रेवड़ियों की जगह मजबूत रोडमैप

मनोज त्रिपाठी
कानपुर

उत्तर प्रदेश में 2027 के पूर्वार्द्ध में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट उम्मीदों के विपरीत चुनावी घोषणाओं, लोक लुभावन योजनाओं और मुफ्त की रेवड़ियों से परहेज करता हुआ जनता के उस विश्वास का दस्तावेज जैसा लगता है, जिसे सरकार ने नौ सालों में पूरी शिद्दत के साथ अर्जित किया है। इसी कारण वित्तीय वर्ष 2026-27 का सरकार का बजट जो कि 9,12,696 करोड़ रुपये के साथ आकार में अब तक का सबसे बड़ा है, वित्तीय लेखा-जोखा से ज्यादा, सरकार की आर्थिक सोच, राजनीतिक प्राथमिकताओं और प्रशासनिक क्षमताओं का बखान करने के साथ स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षी और रणनीतिक रहते हुए विकसित यूपी का रोडमैप प्रस्तुत करता है।

यदि समग्र आकार और संरचना पर नजर डालें, तो यह बजट पिछले वर्षों की तुलना में अधिक विस्तारवादी है। कुल परिव्यय पिछले साल की तुलना में करीब 12.2 फीसदी ज्यादा है। इसके साथ ही वित्तीय अनुशासन और पूंजीगत खर्च बढ़ाने पर खास फोकस है। पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) में वृद्धि के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि प्रदेश केवल कल्याणकारी योजनाओं पर ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे पर भी निवेश कर रहा है। एक्सप्रेस-वे, मेट्रो विस्तार, डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक पार्क, एग्री-एक्सपोर्ट हब, नए मेडिकल कॉलेज, एआई मिशन, प्लेसमेंट सेंटर्स आदि, ये सब मिलकर उस नए उत्तम प्रदेश की तस्वीर पेश करते हैं, जिसे सरकार निवेश-हितैषी और आधुनिक बनाना चाहती है, हालांकि पूंजीगत व्यय के साथ राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना आसान नहीं होता। यदि राज्य का कर्ज अनुपात बढ़ता है, तो भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ बढ़ सकता है। सरकार ने इसे लेकर संतुलन का दावा किया है, लेकिन वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और केंद्र से मिलने वाले अनुदान पर निर्भरता को देखते हुए उसे वित्तीय प्रबंधन की परीक्षा देना अभी बाकी है।

सरकार जब प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय एक लाख 20 हजार होने और छह करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का आंकड़ा पेश करती है, तो यह बताना नहीं भूलती कि अर्थव्यवस्था का हाल पहले क्या था और किस तरह वह राज्य की अर्थव्यवस्था को एक डॉलर ट्रिलियन बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। इसी क्रम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का यह बताना कि उत्तर प्रदेश देश की तीन टॉप अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में प्रदेश की रैंकिंग 2018-19 में 29वें स्थान से सुधरकर 2023-24 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है।

फरवरी 2024 में आयोजित चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में करीब 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए हैं, जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार पैदा होने की संभावना है। अब तक 16 हजार से ज्यादा परियोजनाओं के लिए लगभग 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ चार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी हैं, तो योगी सरकार के इसी दावे पर मुहर लगती है कि उसके पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है, चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश या रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तीकरण हो या युवाओं का कौशल संवर्धन, किसानों की खुशहाली हो या गरीबी उन्मूलन। इन सारी बातों से सरकार यही संदेश हर किसी तक पहुंचाना चाहती है कि अब तक की बदलाव की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इस बार का बजट भी प्रदेश के संतुलित विकास, विशेषकर युवाओं और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है, ताकि राज्य को देश की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाया जा सके।

बजट का सबसे बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित किया गया है। विशेष रूप से सड़कों और फ्लाईओवर के निर्माण पर 34,468 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे प्रदेश में एक्सप्रेसवे, मुख्य राजमार्ग, बाईपास, ग्रामीण सड़कों और पुलों के विस्तार पर तेजी से काम होगा। फिलहाल प्रदेश में सात एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक दौड़ रहा है, तीन एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। अब चार और नए एक्सप्रेसवे बनने की घोषणा से सरकार का इरादा साफ है कि प्रदेश के हर जिले को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, ताकि परिवहन सुविधाएं मजबूत हों और आर्थिक गतिविधियां बढ़ें, क्योंकि यही वह बिंदु है, जिससे लोगों में विकास होने की आम राय बनती है।

निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। बेहतर सड़क नेटवर्क से औद्योगिक क्षेत्रों तक माल की ढुलाई आसान होने से लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है और व्यापार-कारोबार बढ़ता है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में सड़कों के विस्तार से किसानों की बाजार तक पहुंच आसान होने से उनकी आय में सुधार आ सकता है। बजट का दूसरा सबसे प्रमुख हिस्सा टेक्नोलॉजी और एआई मिशन है, जिसमें राज्य को आईटी हब बनाने का संकल्प है।

यूपी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट उम्मीदों के विपरीत चुनावी घोषणाओं से परहेज करता हुआ जनता के विश्वास का दस्तावेज जैसा लगता है।

सोशल फोरम

फिर चित्रा ने नहीं गाया

1975-76 के लगभग जगजीत-चित्राजी का पहला LP रिकार्ड Unforgettables आया, उसके बाद ही हिंदुस्तान में ही नहीं, एक हद तक पाकिस्तान में भी गज़ल गायकी का जैसे ट्रेंड ही बदल गया। उस समय ग़ज़ल गायकी में ग्रेट मेंहदी हसन बहुत बड़ा नाम थे और भारत में तलत महमूद थे और भी बड़े-बड़े शास्त्रीय ग़ज़ल गायक थे

रश्मि त्रिपाठी
ब्लॉगर

उस दौर के, किंतु जगजीत सिंह एक ऐसा नाम उभरा जो जीवन का अंत होने के समय तक निरंतर शोहरत की बुलंदियों पर चढ़ता चला गया। बिना इस बात की परवाह किए कि बाकी गायक कितने बड़े और शोहरतमंद हैं?

अपनी सरल गायकी और मखमली आवाज़ के बल पर जगजीत सिंह न केवल खुद जन-जन के प्रिय होते चले गए, अपितु उन्होंने ग़ज़ल को भी अपार लोकप्रियता दिलाई। ग़ज़ल जो कुछ 'एलीट क्लास' की बैठकों के शौकीनों की शोभा मात्र हुआ करती थीं, अब आम लोगों में गुनगुनाने की चीज़ बन गई। बात यहां तक आ गई कि लोकप्रिय फिल्मी गीतों की तुलना में भी जगजीत जी को अधिक शोहरत मिलने लगी।

कुछ वर्षों के इस सफर के बाद जगजीत सिंह को हिंदी सिनेमा में गाने का मौका भी मिल गया। 'तुम इतना जो मुस्करा रहे हो' या फिर 'होठों से छू लो तुम,मेरा गीत अमर कर दो' जैसे अनेक कालजयी फिल्मी गाने जगजीत सिंह की गायकी और उन्हीं की मौसिक़ी से निकले थे। इससे पहले 1967 में जब जगजीत काम ढूंढ रहे थे, तब उनकी मुलाकात चित्रा दत्ता से हुई। चित्रा उस वक्त शादीशुदा थीं। वो मुंबई में जहां रहती थीं। उनके सामने वाले घर में जगजीत का आना-जाना लगा रहता था और यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई थी।

धीरे धीरे वे एक-दूसरे को पसंद करने लगे थे और अलग सी बात ये थी कि जगजीत ने उनके पति देबू प्रसाद दत्ता से उन्हे मांग लिया था। दिसंबर 1969 में चित्रा ने अपने पति को तलाक देकर जगजीत सिंह से शादी कर ली। कहते हैं कि देबू दत्ता का भी कहीं और अफेयर था, इसलिए उनको भी तलाक में सुविधा हो गई।

चित्रा-जगजीत दोनों एक साथ एक के बाद एक कॉन्सर्ट लगातार करते जा रहे थे। शोहरत-दौलत दिन-दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। साल 1980 तक जगजीत सिंह गजल किंग बन चुके थे। इसी समय उनके एक मात्र पुत्र विवेक की 1990 में एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। दोनों ने गाना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जगजीत सिंह तो रोमांटिक न सही, लेकिन थोड़े बदले मिज़ाज़ के गीत-गजल गाने लगे, लेकिन चित्रा ने फिर नहीं गाया। **–फेसबुक वॉल से**

सामयिकी

ईयू-यूएस से व्यापारिक समझौता सुनहरा मौका

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अब भारतीय निर्यातकों को 50 प्रतिशत शुल्क के स्थान पर सिर्फ 18 प्रतिशत शुल्क ही देना होगा, किंतु यह भी सत्य है कि पहले यह शुल्क मात्र 2.9 प्रतिशत ही था। यह दोनों समझौते भारत को विश्व पटल पर मजबूत स्थिति में खड़ा होने का अवसर प्रदान करते हैं। यदि भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को सभी समझौतों की जननी कहा जा सकता है, तो भारत-अमेरिका व्यापार समझौता सभी समझौतों का जनक माना जा सकता है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया जाने वाला शुल्क अब 18 प्रतिशत रह जाएगा, हालांकि भारतीय यूरोपीय संघ समझौता अपने आप में महत्वपूर्ण है, किन्तु भारत द्वारा अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार अमेरिका से निर्यात को विविधतापूर्ण बनाना भी एक कठिन प्रयास था, जिसमें भारत को अंततः सफलता प्राप्त हुई। यह समझौता

प्रो. रिपुदमन सिंह
शिक्षाविद्

न केवल भारत की व्यापार स्थिति को बहाल करेगा, बल्कि दशकों पुराने भारत-अमेरिका राजनयिक संबंधों को भी मजबूत करेगा, जिनमें हाल ही में तनाव के संकेत दिखाई दिए थे।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते ने भारतीय उद्योगों को राहत की सांस लेने का मौका प्रदान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह दावा कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा भी चुनौतीपूर्ण है, भारत को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि रूसी तेल पूरी तरह बंद करने पर भारत को अपने एक तिहाई तेल की आपूर्ति के लिए विकल्प तलाशना होगा तथा रूस के साथ भारत के संबंध पर भी असर पड़ेगा। रूस भारत का लंबे समय से मित्र और रक्षा उपकरणों का महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है। यह कदम भारत के लिए संबंधों को पुनर्गठन करने जैसा होगा। इसी तरह वेनेजुएला से अधिक कच्चा तेल खरीदना शोधन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न करेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि भारत ने अमेरिका को टैरिफ रियायतों निवेशों और खरीद आदेशों के संदर्भ में क्या प्रतिबद्धतायें निर्धारित की हैं, क्योंकि ट्रंप और उनकी टीम, संवेदनशील कृषि उत्पादों और डेयरी उत्पादों के आदान-प्रदान किए जाने का दावा कर रहे हैं। भारतीय वाणिज्य मंत्री ने ट्रंप के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है, लेकिन अमेरिकी व्यापार समझौते ने एक उम्मीद की किरण तो दी है, क्योंकि इससे शेयर बाजारों में तेजी आई है, रुपये को मजबूती मिली है और कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते और इंजीनियरिंग सामान जैसे श्रम प्रधान उद्योगों में उत्साह का माहौल है।

व्यापार के मोर्चे पर भारत के वस्त्र और चमड़ा निर्यातकों को त्वरित लाभ मिलने की संभावना है। वर्तमान में खेल सामग्री, रत्न और आभूषणों के निर्यातकों को उच्च टैरिफ के चलते कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और यह निर्यातक 10-20 प्रतिशत तक नुकान उठा रहे थे। यह डैडम् क्षेत्र में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत वस्त्र और परिधान का 28 प्रतिशत निर्यात अमेरिका को करता है, जो भारतीय चमड़े और खेल सामग्री का भी बहुत बड़ा बाजार है। भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता भारत के इतने बड़े निर्यात को इतनी जल्दी समायोजित करने की स्थिति में संभवतः नहीं था, किंतु एक वैकल्पिक व्यवस्था बनने की स्थिति में जरूर आगे आ सकता है। अमेरिकी रणनीतिकार संभवतः इसी संभावना को भांपने में सफल रहे हैं और भारत-अमेरिका समझौते को अति शीघ्र लागू करने के लिए तत्पर हो गए हैं। भारत-अमेरिका व्यापार समझौता का एक व्यापक रणनीतिक उद्देश्य भी है, यह द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने में भी मदद करेगा, जो नागरिक परमाणु समझौते के बाद से लगातार मजबूत होते गए हैं।

स्वामी-रुहेलखंड इंटरप्राइजेज के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक हरि ओम गुप्ता द्वारा अमृत विचार प्रकाशन, नवादा जोगियान, चक रोड, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के सामने, बरेली (उ.प्र.), पिन कोड-243006 से मुद्रित एवं 932 कटरा चांद खां, भारत पेट्रोल पंप के सामने पीलीभीत बाईपास रोड बरेली (उ.प्र.) पिन कोड-243005 से प्रकाशित। **संपादक- राजेश श्रीनेत, स्थानीय संपादक- नवीन गुप्ता*** 0581-4000222 (कार्यालय), ईमेल- editorschoice@amritvichar.com, आर.एन.आई नं0-UPHIN/2019/78502, *इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी। (नोट-सभी विवादों का न्यायक्षेत्र बरेली होगा)।

कैम्पस

75% कॉलेज छात्रों को नहीं दे पा रहे जॉब वाली स्किल्स

राजेश जैन
लेखक

भारत में हर साल लाखों युवा बड़े सपनों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। परिवार उम्मीद करता है कि चार साल की पढ़ाई के बाद बच्चा अच्छी नौकरी पाएगा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा और समाज में सम्मान पाएगा, लेकिन आज की सच्चाई यह है कि डिग्री मिलने के बाद भी नौकरी मिलना किसी जुए से कम नहीं रह गया है। टीमलीज एडटेक की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत के करीब 75 प्रतिशत कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने छात्रों को जॉब-रेडी स्किल्स देने में नाकाम हो रहे हैं। यानी डिग्री तो मिल रही है, लेकिन नौकरी के लायक नहीं है। यह सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

डिग्री की फैक्ट्रियां बनते जा रहे हैं कॉलेज

आज बड़ी संख्या में संस्थान सिर्फ डिग्री बांटने वाली फैक्ट्रियों में बदल चुके हैं। क्लासरूम में थ्योरी पढ़ाई जाती है, पुराने सिलेबस रटाए जाते हैं, लेकिन असली दुनिया की जरूरतों से छात्रों का कोई संपर्क नहीं होता। नतीजा यह होता है कि छात्र पास होकर निकलते हैं, लेकिन उन्हें यह तक नहीं पता होता कि इंडस्ट्री उनसे क्या चाहती है। आज कंपनियों को ऐसे युवा चाहिए जो टेक्नोलॉजी समझते हों, कम्युनिकेशन में मजबूत हों, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हों, लेकिन ज्यादातर कॉलेज इन स्किल्स पर काम ही नहीं करते।

प्लेसमेंट का कड़वा सच

कागजों में कई संस्थान 100 प्रतिशत प्लेसमेंट का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ 16.67 प्रतिशत संस्थान ही ऐसे हैं, जो अपने 76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत छात्रों को छह महीने के भीतर नौकरी दिला पाते हैं। बाकी छात्रों को या तो बहुत कम सैलरी वाली नौकरी मिलती है या फिर वे बेरोजगार घूमते रहते हैं या किसी दूसरे कोर्स की तैयारी करने लगते हैं। यह स्थिति उन माता-पिता के लिए भी चिंता का विषय है, जो भारी फीस भरकर बच्चों को प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाते हैं। इंडस्ट्री और पढ़ाई के बीच गहरी खाई आज की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यही है कि पाठ्यक्रम और उद्योग की जरूरतों में तालमेल नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 8.6 प्रतिशत संस्थानों के कोर्स पूरी तरह इंडस्ट्री-फ्रेंडली हैं, 51 प्रतिशत से ज्यादा संस्थानों का उद्योग से कोई तालमेल ही नहीं। मतलब आधे से ज्यादा कॉलेज ऐसे हैं, जहां पढ़ाया कुछ और जाता है और नौकरी में चाहिए कुछ और।

क्लासरूम में इंडस्ट्री का अनुभव नदारद

अगर कॉलेजों में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पढ़ाएं, तो छात्रों को असली दुनिया की समझ मिले, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 7.56 प्रतिशत संस्थानों में ही 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' जैसे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को शामिल किया गया है। बाकी जगह वही पुराने प्रोफेसर, वही पुराने नोट्स, वही पुरानी थ्योरी। छात्रों को यह नहीं बताया जाता कि आज जॉब मार्केट कैसे बदल रहा है, नई भूमिकाएं क्या हैं, कंपनियां किस तरह की स्किल्स ढूंढ रही हैं।

सर्टिफिकेट्स से दूरी

आज कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं देखतीं, वे मान्यता प्राप्त इंडस्ट्री सर्टिफिकेट्स को भी महत्व देती हैं। जैसे-एआई और डेटा साइंस सर्टिफिकेट, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, 60 प्रतिशत से ज्यादा संस्थानों ने इन सर्टिफिकेट्स को अपने कोर्स में शामिल करने पर कभी सोचा ही नहीं। नतीजा ये हुआ छात्र ऐसे स्किल्स के बिना ग्रेजुएट होते हैं, जिन्हें कंपनियां तुरंत पहचान सकें।

इंटर्नशिप: नाम की, काम की नहीं

नौकरी से पहले इंटर्नशिप सबसे जरूरी कदम होती है। यहीं से छात्र सीखते हैं-ऑफिस कल्चर, टीमवर्क, असली प्रोजेक्ट पर काम, लेकिन भारत में सिर्फ 9.4 प्रतिशत संस्थानों में सभी कोर्स के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप होती है और 37.8 प्रतिशत संस्थानों में इंटर्नशिप की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यानी लाखों छात्र बिना किसी प्रैक्टिकल अनुभव के सीधे जॉब मार्केट में उतर जाते हैं। फिर कंपनियां कहती हैं-आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है।

लाइव प्रोजेक्ट्स भी गायब

लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स छात्रों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं, लेकिन सिर्फ 9.68 प्रतिशत संस्थानों में ही ऐसे प्रोजेक्ट कराए जाते हैं। बाकी जगह थ्योरी पढ़ाओ, एग्जाम लो, डिग्री दो और मामला खत्म।

एलुमनाई नेटवर्क की कमजोरी

पूर्व छात्र किसी भी संस्थान की ताकत होते हैं। वे मेंटरशिप दे सकते हैं, रेफरल दिला सकते हैं, जॉब के मौके खोल सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 5.44 प्रतिशत संस्थानों के पास सक्रिय एलुमनाई नेटवर्क है। यानी कॉलेज अपने ही पुराने छात्रों की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे।

इसका असर सिर्फ छात्रों पर नहीं, देश पर भी-जब युवा बेरोजगार रहते हैं, तो इसका असर सिर्फ परिवार पर नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उत्पादकता घटती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, स्किल गैप बढ़ता है, माइग्रेशन बढ़ता है, डिग्रीधारी बेरोजगारी, देश के लिए सबसे खतरनाक संकेतों में से एक है।

यह है समाधान

रिपोर्ट साफ कहती है कि अब बदलाव विकल्प नहीं, मजबूरी है। इसके लिए इंडस्ट्री-अनुकूल सिलेबस, अनिवार्य इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की भागीदारी, सर्टिफिकेट कोर्स, मजबूत एलुमनाई नेटवर्क, कॉलेजों को सिर्फ पढ़ाने की नहीं, रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी लेनी होगी।

सरकार की भूमिका भी अहम

नई शिक्षा नीति सही दिशा में कदम है, लेकिन जमीन पर उसका असर अभी सीमित है। सरकार को चाहिए कि कॉलेजों की जवाबदेही तय करे, प्लेसमेंट डेटा पब्लिक करे, स्किल-बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दे, इंडस्ट्री पार्टनरशिप अनिवार्य बनाए, छात्रों को भी जागरूक होना होगा। आज का छात्र सिर्फ डिग्री पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे खुद भी ऑनलाइन स्किल्स सीखनी होंगी, इंटर्नशिप ढूंढनी होगी, नेटवर्क बनाना होगा, इंडस्ट्री ट्रेंड समझना होगा। अगर भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम आज नहीं सुधरा तो आने वाले सालों में डिग्रियों की भीड़ होगी, लेकिन नौकरियों की कमी। यह संकट सिर्फ शिक्षा का नहीं, राष्ट्र निर्माण का संकट है। अब वक्त है डिग्री फैक्ट्रियों को रोजगार केंद्रों में बदलने का।

वर्ड स्मिथ

कैसे बना शैंपू शब्द

आज शैंपू हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक सामान्य शब्द बन चुका है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका जन्म भारत में हुआ और यह शब्द हिंदी-उर्दू नहीं, बल्कि संस्कृत मूल से होकर अंग्रेजी तक पहुंचा। 'शैंपू' शब्द की कहानी औपनिवेशिक भारत, आयुर्वेद और पश्चिमी संस्कृति के आपसी संपर्क से जुड़ी है। 'शैंपू' शब्द की जड़ संस्कृत के शब्द 'चम्पू' (Champu) में मिलती है। 'चम्पू' का अर्थ होता है-दबाना, मलना या मालिश करना। प्राचीन भारत में सिर और शरीर की तेल मालिश को 'चम्पू' कहा जाता था। यह केवल सौंदर्य का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का भी महत्वपूर्ण हिस्सा था। आयुर्वेद में सिर की मालिश को तनाव दूर करने, रक्तसंचार बढ़ाने और बालों को स्वस्थ रखने का प्रभावी उपाय माना गया है।

17वीं-18वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश व्यापारी और अधिकारी भारत आए, तो उन्होंने यहां की मालिश और स्नान पद्धतियों को देखा। बंगाल में 'चम्पू' एक प्रचलित प्रक्रिया थी, जिसमें जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक तत्वों से सिर की सफाई और मालिश की जाती थी। अंग्रेजों ने इस शब्द को अपने उच्चारण के अनुसार 'Shampoo' कहना शुरू कर दिया। सन 1762 में यह शब्द पहली बार अंग्रेजी शब्दकोश में दर्ज हुआ। शुरुआत में 'शैंपू' का अर्थ केवल सिर की मालिश या शरीर को मलने की क्रिया था, न कि किसी तरल पदार्थ का नाम। बाद में, 19 वीं शताब्दी में जब तरल साबुन और बाल धोने वाले उत्पाद विकसित हुए, तब इस प्रक्रिया से जुड़े उत्पाद को ही 'शैंपू' कहा जाने लगा। इस प्रकार, 'शैंपू' केवल एक कॉस्मेटिक उत्पाद नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की देन है, जो संस्कृत से चलकर औपनिवेशिक रास्तों से होती हुई पूरी दुनिया की भाषाओं में शामिल हो गई। यह शब्द हमें याद दिलाता है कि भारतीय परंपराओं का वैश्विक प्रभाव कितना गहरा और स्थायी रहा है।

नोटिस बोर्ड

- बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उन्हें रोजगार पाने के लिए बहुत जल्द सुनहरा अवसर मिलेगा। जिला सेवा योजन विभाग, अमेठी की ओर से 26 फरवरी को आरआरपीजी कॉलेज में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 50 से अधिक नामी कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। मेले के माध्यम से 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। मेले में कक्षा आठवीं पास से लेकर स्नातक, परास्नातक, बीटेक, आइटीआइ और पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि मौके पर ही साक्षात्कार लेकर चयन प्रक्रिया पूरी करेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा साथ ले जाएं।

- बरेली कॉलेज के ललितकला विभाग ने बीए प्रथम सेमेस्टर चित्रकला विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। विभागीय सूचना के अनुसार बैक और रेगुलर दोनों श्रेणी के विद्यार्थियों की परीक्षा 14 फरवरी को सुबह 10 बजे से आयोजित की जाएगी। परीक्षा ललितकला विभाग में ही संपन्न होगी। विभाग के प्रभारी प्रो. एबीएल. लखटकिया ने छात्रों को निर्देश दिए हैं कि वे परीक्षा के दिन निर्धारित समय से कम से कम आधा घंटा पहले विभाग में उपस्थित रहें, ताकि सभी आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें और परीक्षा प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो।

कैंपस में पहला दिन

जीवन को सोचने व समझने की यात्रा

कृष्णा चौहान
बीएससी छात्रा, एसएस कॉलेज, शाहजहांपुर

आज भी स्मृतियों में किसी ताजी सुबह की तरह कॉलेज का पहला दिन चमकता है। स्कूल की सुरक्षित और जानी-पहचानी दुनिया से निकलकर बीएससी की छात्रा के रूप में कॉलेज की देहरी पर कदम रखना मेरे लिए उत्साह और संकोच दोनों का मिला-जुला अनुभव था। हाथ में नई फाइल, कंधे पर बैग और मन में अनगिनत सवाल, क्या मैं यहां अपने सपनों के करीब पहुंच पाऊंगी?

कॉलेज का विशाल परिसर देखते ही मन आश्चर्य से भर उठा। ऊंची इमारतें, हरे-भरे पेड़, भागते हुए छात्र, कहीं हंसी की आवाजें तो कहीं गंभीर चेहरों पर किताबों का बोझ, सब कुछ नया था। विभाग की ओर बढ़ते कदमों के साथ दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। बीएससी की छात्रा होने का गर्व तो था, लेकिन साथ ही यह डर भी कि विज्ञान जैसे गंभीर विषय को संभाल पाऊंगी या नहीं। पहली कक्षा का अनुभव कभी नहीं भूल सकती। प्रयोगशाला में रखे चमकते उपकरण, रसायनों की हल्की गंध और दीवारों पर टंगे वैज्ञानिकों के चित्र मुझे एक अलग ही दुनिया में ले गए। जब पहली बार अध्यापक ने अपना परिचय दिया और विषय की महत्ता समझाई, तब महसूस हुआ कि यह सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि जीवन के सोचने और समझने की एक नई यात्रा है। सबसे सुकून देने वाला पल तब आया, जब कुछ अनजान चेहरे मुस्कान में बदल गए। पास बैठी छात्रा से हुई छोटी-सी बातचीत दोस्ती की शुरुआत बन गई। लगा जैसे डर धीरे-धीरे आत्मविश्वास में बदल रहा हो। कैंटीन की पहली चाय और हल्की-फुल्की बातचीत ने उस दिन को और यादगार बना दिया।

शाम को कॉलेज से लौटते समय मन में थकान नहीं, बल्कि एक अजीब-सी खुशी थी। लगा, जैसे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूं, तो समझ में आता है कि वह पहला दिन सिर्फ कॉलेज का नहीं था, बल्कि मेरे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला कदम था, जो आज भी मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

करेंट अफेयर्स

- हाल ही में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम और कड़े हो गए हैं। संशोधित आईटी नियम 2021 के तहत अब एआई-जनित (AI-generated) सामग्री पर "स्पष्ट और प्रमुख" लेबल लगाना अनिवार्य होगा और अवैध सामग्री हटाने की समय-सीमा 36 घंटे से घटाकर केवल तीन घंटे कर दी गई है। ये बदलाव 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे।
- भारत और सेशेल्स के द्विपक्षीय संबंध एक नए रणनीतिक स्तर पर पहुंचा गए हैं। हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने सततता, आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए सुदृढ़ संपर्कों के माध्यम से संयुक्त दृष्टि (SESEL) की घोषणा की। यह पहल हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और एक करीबी समुद्री साझेदार के रूप में सेशेल्स के महत्व को रेखांकित करती है, जिसमें सुरक्षा, विकास और जन-केंद्रित सहयोग को केंद्र में रखा गया है।
- हाल ही में नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश के लिए एक महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा योजना पेश की है। इस नीति ब्लूप्रिंट का उद्देश्य वर्ष 2035 तक आंध्र प्रदेश को भारत के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हब में बदलना है। घटती बिजली लागत और बड़े क्षमता विस्तार के साथ आंध्र प्रदेश को भविष्य में देश के लिए स्वच्छ ऊर्जा निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
- हाल ही में वैश्विक खेल प्रशासन के लिए एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने ईरान से अपनी पहली महिला सदस्य का चुनाव किया है। ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी सोरया अघाई हाजिआगहा को 4 फरवरी इटली के मिलान में आयोजित 145 वें IOC सत्र के दौरान निर्वाचित किया गया। इस चुनाव के साथ ही वे IOC की वर्तमान सबसे कम उम्र की सदस्य भी बन गई हैं।
- भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। यह उपलब्धि उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में सातवां स्थान हासिल करने के पांच दिन बाद दर्ज की। डबल शूट-ऑफ के बीच मनु ने मानसिक मजबूती दिखाते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। यह 25 मीटर पिस्टल में उनका पहला व्यक्तिगत सिल्वर मेडल है।

जॉब अलर्ट

एम.पी. राज्य सहकारी बैंक

- पद का नाम-कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर (संविदा), सोसायटी मैनेजर, अधिकारी
- पदों की संख्या- (1763 क्लर्क + 313 अधिकारी) 2076 पद
- सैलरी/पे स्केल क्लर्क : लेवल-4 (Rs. 19,500-62,000) 7 वां पे स्केल / लेवल-7 (Rs. 28,700-91,300) / 6 वां पे स्केल (Rs. 5,200-20,200 + 1900 GP)
- शैक्षणिक योग्यता-स्नातक
- आयु सीमा -18 से 35 वर्ष (40 वर्ष छूट के साथ), कंप्यूटर ऑपरेटर (संविदा) : 18 से 55 साल
- आवेदन की अंतिम तिथि- 20 फरवरी 2026
- वेबसाइट-www.apexbankmp.bank.in

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

- पद का नाम- ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती (विभिन्न विभाग / बोर्ड / निगम)
- सीईटी ग्रुप सी पर आधारित- विज्ञापन नंबर 01/2025 क्वॉलिफाइड कैंडिडेट
- पदों कि संख्या -4227
- एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख- 9 फरवरी 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि- 23 फरवरी 2026
- ऑफिशियल वेबसाइट www.hssc.gov.in

सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

- पद का नाम- डिप्टी जनरल मैनेजर (इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स), डिप्टी जनरल मैनेजर (माइक्रोवेव), दूसरे पोस्ट (डिप्टी इंजीनियर, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, वगैरह
- पदों की संख्या- 34
- विज्ञापन नंबर 118/Pers/1/2026
- सैलरी- Rs.17,500 - 2,20,000/- हर महीने
- क्वालिफिकेशन- B.E./B.Tech / MBA / CA/ ICWA / ग्रेजुएट / 10th
- एज लिमिट- पदानुसार
- आवेदन की अंतिम तिथि- 3 फरवरी 2026
- वेबसाइट- https://www.celindia.co.in

बोर्ड परीक्षा से पहले सफलता का स्मार्ट स्टडी प्लान

डॉ. मनोज कुमार तिवारी
बीएचयू

बीते दिनों परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कुशल मनोवैज्ञानिक की भांति विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा की, उन्होंने सीधे परीक्षा तनाव पर चर्चा करने के बजाय छात्रों के जीवन व उनके क्षेत्र से संबंधित विभिन्न आयामों पर चर्चा की, जिससे छात्र उनसे सीधे जुड़ सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर छात्र अद्वितीय हैं, उनकी अपनी क्षमता, विशेषता, जीवनशैली, सोचने-समझने का ढंग अलग-अलग होता है, इसलिए विद्यार्थियों का परीक्षा की तैयारी का तरीका अलग-अलग हो सकता है। उन्होंने छात्रों से कहा कि अपनी परीक्षा की तैयारी अपने ढंग से करनी चाहिए, सभी के सुझाव को सुनना चाहिए, किंतु अपनी तैयारी का पैटर्न अपने अनुभव के अनुसार तय करना चाहिए। यूपी बोर्ड एग्जाम के कुछ दिन ही शेष रह गए हैं।

इन दिनों में परीक्षार्थियों को विशेष ध्यान रखते हुए परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। आइए आज आपको बताते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी सुझाव, जिन्हें अपनाकर आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं।

सिलेबस के अनुसार बनाएं स्टडी प्लान

सबसे पहले एक सरल और व्यावहारिक टाइम टेबल तैयार करें। यह बहुत जटिल नहीं होना चाहिए। दिन के अलग-अलग समय के अनुसार विषय तय करें। सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, इसलिए इस समय कठिन विषयों का अध्ययन करें। दोपहर में हल्के टॉपिक और शाम के समय रिवीजन पर ध्यान दें।

जरूरी टॉपिक पर करें फोकस

जब बोर्ड परीक्षा में कुछ ही दिन शेष हों, तब नया पाठ्यक्रम शुरू करने के बजाय महत्वपूर्ण अध्यायों पर ध्यान देना समझदारी है। सिलेबस में शामिल मुख्य चैप्टर और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का विश्लेषण करें। जिन टॉपिक से बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें अच्छी तरह तैयार करें। अगर कोई अध्याय पूरा नहीं आता है, तो उसे छोड़ने के बजाय उसके आसान हिस्सों को जरूर पढ़ लें।

प्रश्नों की लिखकर करें प्रैक्टिस

पढ़ी हुई सामग्री को बार-बार दोहराना बहुत जरूरी है। रोजाना कम से कम एक बार रिवीजन करें। साथ ही लिखकर अभ्यास करने से उत्तर लेखन की गति बढ़ती है और परीक्षा के समय समय-प्रबंधन में मदद मिलती है। गणित, विज्ञान और अकाउंट्स जैसे विषयों में यह तरीका विशेष रूप से लाभकारी होता है।

मॉक टेस्ट देना न भूलें

पुराने प्रश्नपत्र और फुल मॉक टेस्ट बोर्ड परीक्षा की तैयारी का सबसे बेहतर साधन हैं। छात्रों को सप्ताह में कम से कम दो से तीन फुल-लेंथ मॉक टेस्ट देने चाहिए। इससे परीक्षा के माहौल की आदत बनती है। टेस्ट के बाद अपनी गलतियों को समझें और उन्हें सुधारने पर काम करें।

तनाव से दूर रहें, बनाए रखें आत्मविश्वास

परीक्षा से पहले घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन अत्यधिक तनाव पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। छात्रों को खुद पर भरोसा रखना चाहिए। पूरे साल की गई मेहनत अंतिम समय में जरूर रंग लाएगी।

बाजार	सेंसेक्स ↓	निफ्टी ↑
बंद हुआ	84,233.64	25,953.85
गिरावट/बढ़त	40.28	18.70
प्रतिशत में	0.05	0.07

सोना 1,61,300 प्रति 10 ग्राम

चांदी 2,68,500 प्रति किलो

अमृत विचार

बरेली, गुरुवार, 12 फरवरी 2026

www.amritvichar.com

कारोबार

बरेली मंडी

वनस्पति तेल तिलहन : तुलसी 2610, राज श्री 1940, फॉर्चून कि. 2425, रविन्द्रा 2515, फॉर्चुन 13 किग्रा 2145, जय जवान 2125, सचिन 2120, सूरज 2125, अवसर 1865, उजाला 1920, गृहणी 13 किग्रा 1975, क्लासिक (किग्रा) 2325, मोर 2320, चक्र टिन 2375, ब्लू 2215, आशीर्वाद मस्टर्ड 2420, स्वास्तिक 2565

किराना : हल्दी निजामाबाद 17000, जीरा 24500, लाल मिर्च 18000-23000, धनिया 9400-12000, अजवायान 13500-20000, मेथी 6000-8000 सौंफ 9000-13000, सोंठ 31000, (प्रतिकि.) लौंग 800-1000, बादाम 780-1080, काजू 2 पीस 840, किसमिस पीली 300-400, मखाना 800-1100

चावल (प्रति कु) : डबल चाबी सेला 9700, स्पाइस 6500, शरबती कच्ची 5250, शर्बती स्टीम 5350, मंसूरी 4000, महबूब सेला 4050, गौरी रॉयल 8400, राजभोग 6850, हरी पत्ती (1 किग्रा, 5 किग्रा) 10100, हरी पति नेचुरल 9100, गौरी स्पेशल 8500, गौरी प्रीमियम 10200, सूमो 4000, गौरी रॉयल 8600, मंसूरी पनघट 4200,लाडली 4200

दाल दलहन : मूंग दाल इंदौर 9800, मूंग धोवा 10000, राजमा चित्रा 11200-12000, राजमा भूटान नया 10100, मलका काली 7250-7450 मलका दाल 7350-9200, मलका छाँटी 7250, दाल उड़द बिलासपुर 8800-9800, मसूर दाल छोटी 10000-11600, दाल उड़द दिल्ली 11200, उड़द साबुत दिल्ली 10500, उड़द धोवा इंदौर 12700, उड़द धोवा 9800-11500,चना काला 7150, दाल चना 7250, दाल चना मोटी 7100, मलका विदेशी 7200, रूपकिशोर बेसन 7500, चना अकोला 6600, डबरा 6800-8400, सच्चा हीरा 8700, मोटा हीरा 10000, अरहर गोला मोटा 8800, अरहर पटका मोटा 9500, अरहर कोरा मोटा 9800, अरहर पटका छोटा 11100-11800, अरहर कोरी छोटी 13100

चीनी : पीलीभीत 4460, बहेड़ी 4300

हल्द्वानी मंडी

चावल : शरबती- 4000, मसूरी- 1600, बासमती- 8200-9000, परमल- 2200-3900

दाल दलहन : काला चना- 2600-4000, साबुत चना दाल- 1400, मूंग साबुत- 5000, राजमा- 9000-12200, दाल उड़द- 7500, साबुत मसूर दाल- 4000, मसूर दाल- 1500

उड़द साबुत- 10400, काबुली चना- 7500-10000, अरहर दाल- 10000 -12200, लोबिया/करमानी- 2400-4400

भारत-अमेरिका समझौते में संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरह संरक्षित : वाणिज्य सचिव

दोनों पक्ष संयुक्त बयान को कानूनी समझौते में बदलने पर कर रहे काम

- दोनों देश मार्च के अंत तक समझौते के प्रारूप के अंतिम रूप दिए जाने के बाद हस्ताक्षर की उम्मीद

न्यूर्नबर्ग (जर्मनी), एजेंसी

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत ने व्यापार समझौतों में हमेशा उन क्षेत्रों को लेकर स्पष्ट सोच रखी है जो देश के लिए बेहद संवेदनशील हैं और अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते में ऐसे सभी प्रमुख क्षेत्रों की पूरी तरह रक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष संयुक्त बयान को कानूनी समझौते में बदलने पर काम कर रहे हैं जिसे मार्च के अंत तक अंतिम रूप देकर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।

अग्रवाल ने कहा कि भारत ने हमेशा सभी समझौतों पर स्पष्ट सोच के साथ बातचीत की है। जो भी क्षेत्र भारत के लिए बेहद संवेदनशील हैं, जहां हमें लगता है कि हमारे किसान, मछुआरे, दुग्ध क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, वहां हमने अपने साझेदार देशों को साफ बता दिया है कि भारत ऐसे मामलों में बाजार नहीं खोल सकता या पहुंच नहीं दे सकता।

उन्होंने कहा कि अगर आप पिछले एक साल में किए गए सभी समझौतों को देखें। हमने पांच व्यापार समझौते किए हैं। सभी में संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा की गई है। अमेरिका के साथ भी सभी प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा गया है। जहां थोड़ी संवेदनशीलता थी, वहां हमने शुल्क दर कोटा व्यवस्था का इस्तेमाल किया ताकि बाजार तक पहुंच सीमित रहे और हमारे किसानों पर असर न पड़े। इस महीने की शुरुआत में घोषित अंतरिम व्यापार समझौते के तहत भारत ने मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल (ईंधन), तंबाकू, कुछ सब्जियों और मांस जैसे संवेदनशील कृषि एवं दुग्ध उत्पादों को पूरी तरह संरक्षित रखा है। इन वस्तुओं पर अमेरिका को कोई शुल्क रियायत नहीं दी गई है। ये उत्पाद संवेदनशील हैं क्योंकि इनका संबंध देश के छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका से है। अन्य मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में भी भारत ने संवेदनशील कृषि और दुग्ध उत्पादों पर आयात शुल्क में कोई रियायत नहीं दी है।

देश का निर्यात सकारात्मक रहने की उम्मीद

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के वस्तु एवं सेवा निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है और जनवरी में भी इसके सकारात्मक रहने का अनुमान है। जनवरी के आंकड़े इस महीने आधिकारिक रूप से जारी किए जाएंगे। अग्रवाल ने कहा, कुल मिलाकर निर्यात अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वस्तु निर्यात में हम मजबूती से टिके हुए हैं। सेवाएं हमेशा की तरह बहुत अच्छा कर रही हैं। आप (जनवरी के आंकड़ों) के सकारात्मक रहने की उम्मीद कर सकते हैं। जनवरी के निर्यात आंकड़ों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने यह बात कही। अग्रवाल यहां बायोफैच 2026 प्रदर्शनी में हिस्सा लेने पहुंचे हैं जहां 100 से अधिक भारतीय प्रदर्शक और करीब 20 राज्य अपने जैविक उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं।

कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़

भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए को अंतिम रूप दिया है। कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियां जैसे पशुपालन भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनसे 50 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जहां कृषि अत्यधिक मशीनीकृत और कॉरपोरेट आधारित है, वहीं भारत में यह आजीविका का सवाल है। भारतीय कृषि क्षेत्र को वर्तमान में घरेलू किसानों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए मध्यम से उच्च शुल्क एवं नियामकीय उपायों के जरिये संरक्षण दिया गया है। भारत को 2024 में अमेरिका का कृषि निर्यात 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।

समझौते पर संशोधित दस्तावेज से व्हाइट हाउस ने कुछ दालों का जिक्र हटाया

न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस ने अंतरिम व्यापार समझौते पर जारी संशोधित दस्तावेज में उन अमेरिकी उत्पादों की सूची से दालों का जिक्र हटा दिया है जिन पर भारत के शुल्क समाप्त करने या कम किए जाने की बात कही गई थी। व्हाइट हाउस ने अमेरिका और भारत ने की ऐतिहासिक व्यापार समझौते (अंतरिम समझौता) की घोषणा शीर्षक से एक दस्तावेज (फैक्ट शीट) सोमवार को जारी किया था। भारत और अमेरिका के पारस्परिक एवं लाभकारी व्यापार से संबंधित अंतरिम समझौते के ढांचे की संयुक्त घोषणा के कुछ दिन बाद व्हाइट हाउस ने इसे जारी किया। इसमें समझौते की प्रमुख शर्तों को उल्लेख किया गया है जैसे कि भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं एवं अमेरिकी खाद्य व कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क समाप्त करेगा या घटाएगा। इनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड सोरघम, ट्री नट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट सहित अन्य उत्पाद शामिल हैं। साथ ही यह कहा गया था कि भारत ने अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने तथा ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य क्षेत्रों में 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। व्हाइट हाउस ने हालांकि मंगलवार को जारी संशोधित दस्तावेज (फैक्ट शीट) में दालों का जिक्र हटा दिया और भारत के लिए प्रयुक्त शब्द प्रतिबद्ध को बदलकर इरादा रखता है (इंटेंड्स) कर दिया गया है। संशोधित दस्तावेज में कहा गया है, भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं व अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क समाप्त या कम करेगा जिनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स (डीडीजी), रेड सोरघम, ट्री नट्स, ताजे व प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, वाइन तथा स्पिरिट और अन्य उत्पाद शामिल हैं। भारत अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने और 500 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिकी ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कोयला और अन्य उत्पादों की खरीद का इरादा रखता है।

एसएमई की पूंजी बाजार में पहुंच सीमित

- सेबी प्रमुख पांडये ने कहा- सूचीबद्धता से कंपनियों का संचालन हो सकता बेहतर

मुंबई, एजेंसी

सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने बुधवार को कहा कि पिछले कुछ समय में हुए विकास के बावजूद, पूंजी बाजार के नजरिये से लघु एवं मझोले उद्यम (एसएमई) क्षेत्र की पहुंच अभी भी सीमित बनी हुई है। पांडेय ने इंडिया एसएमई वित्तपोषण और निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि सूचीबद्धता से ऐसी छोटी कंपनियों में संचालन व्यवस्था बेहतर हो सकती है।

उन्होंने कहा कि नियामक संस्था को अतीत में इस मोर्चे पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। भारत की क्षमता के मुकाबले एसएमई पूंजी बाजार अभी भी सीमित बना हुआ है। कंपनियां पूंजी बाजारों से अपरिचित होने और मर्चेंट बैंकरों तक सीमित पहुंच के कारण बाजार में आने से हिचकिचाती हैं। कुछ वर्षों में सूचीबद्धता में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए पांडेय ने कहा कि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से पूंजी जुटाने की लागत भी एक बाधा हो सकती है। ऐसी कंपनियां खुलासा और अनुपालन को बोझिल मानती हैं और दस्तावेज दाखिल करने संबंधी व्यावहारिक मार्गदर्शन अक्सर अस्पष्ट होता है।

सेबी प्रमुख ने बाजार से पूंजी जुटाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा कदम संचालन व्यवस्था को बेहतर बनाता है, जिससे पूंजी की लागत कम हो सकती है क्योंकि बाजार विश्वसनीयता को पुरस्कृत करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले, बाजार से पूंजी प्राप्त करने में एक और बाधा तब उत्पन्न हुई जब कुछ एसएमई ने एसएमई ढांचे के तहत उपलब्ध रियायतों का दुरुपयोग किया। ऐसे मामलों ने एसएमई आईपीओ में निवेशकों के भरोसे को बुरी तरह प्रभावित किया।

1,400 कंपनियां अलग एसएमई एक्सचेंज पर सूचीबद्ध

पांडेय ने कहा कि ऐसे भी मामले सामने आए जहां कुछ एसएमई ने सकारात्मक माहौल बनाने और निवेशकों को अपने शेयर खरीदने के लिए प्रेरित करने को अनुचित व्यापार गतिविधियों का सहारा लिया। सेबी और शेयर बाजार दोनों ने इस पर सुधार किया है। 1,400 कंपनियां अलग से बनाये गये एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं और उनका कुल बाजार पूंजीकरण 4.1 लाख करोड़ रुपये है। इनमें से 350 से अधिक कंपनियां मुख्य शेयर बाजार में स्थानांतरित हो चुकी हैं। पिछले वित्त वर्ष में कंपनियों ने 98 आईपीओ के माध्यम से 9,800 करोड़ रुपये जुटाए। 2025-26 में जनवरी तक 232 सूचीबद्धता के साथ बढ़कर 10,500 करोड़ रुपये हो गया है।

ईसी बिना खदान संचालन पर एनएलसी को कैग ने फटकारा

नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने वैध पर्यावरणीय मंजूरी के बिना अपनी एक खदान का संचालन करने के लिए एनएलसी इंडिया को फटकार लगाई है। कैग ने कहा कि पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) के पुनः सत्यापन को कंपनी के समय पर आवेदन नहीं करने से एनएलसी इंडिया ने माइन-II का संचालन वैध ईसी के बिना किया।

ऑडिट में सामने आया कि अगस्त, 2017 में उच्चतम न्यायालय के आदेश और अप्रैल, 2018 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के बाद ईसी पुनः सत्यापन के लिए आवेदन में देरी से खदान में अनधिकृत संचालन हुआ। एनएलसी इंडिया के परिचालन प्रदर्शन पर 2017-18 से 2022-23 की अवधि को शामिल करने वाली ऑडिट रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में रखी गई।

देश का प्रत्यक्ष कर संग्रह 9.4% बढ़कर 19.44 लाख करोड़

नई दिल्ली, एजेंसी

चालू वित्त वर्ष में 10 फरवरी तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 9.4% बढ़कर 19.44 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह बढ़ोतरी कॉरपोरेट कर की बेहतर वसूली और कर रिफंड की धीमी गति का परिणाम है।

आयकर विभाग से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह 14.51% बढ़कर 8.90 लाख करोड़ पहुंच गया। वहीं गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह, जिसमें व्यक्तिगत आयकर और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) से मिले कर शामिल हैं, 5.91% बढ़कर 10.03 लाख करोड़ रुपये रहा। शेयरों एवं अन्य प्रतिभूतियों के लेनदेन पर लगाया जाने वाला प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) का संग्रह 1 अप्रैल, 2025 से 10 फरवरी, 2026 के दौरान 50,279 करोड़ रहा। कर रिफंड जारी करने में 18.82% की गिरावट आई और यह घटकर 3.34 लाख करोड़ रहा। रिफंड में कमी से कर संग्रह वृद्धि दर को सहारा मिला।

देश का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 4.09% बढ़कर 22.78 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसमें 10.88 लाख करोड़ का सकल कॉरपोरेट कर और 11.39 लाख करोड़ रुपये का सकल गैर-कॉरपोरेट कर शामिल हैं। सरकार ने संशोधित अनुमान (आरई) में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 24.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया है।

- आयकर विभाग के मुताबिक, शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह 14.51% बढ़कर 8.90 लाख करोड़ पहुंचा

राष्ट्रीय

बजट पर चर्चा : लोस में भाजपा-कांग्रेस में ठनी

जिन्हें असत्य बोलने की आदत होती है वे कभी भी टिक नहीं पाते : अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेने के तुरंत बाद राहुल गांधी के सदन से चले जाने को लेकर उनपर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें असत्य बोलने की आदत होती है वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं।

ठाकुर ने 2026-27 के बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा, पहले यह होता था कि हमारे भाषण के बीच में राहुल सदन से चले जाते थे, लेकिन अब तो यह स्थिति है कि वह पहले ही भाग जाते हैं।' क्योंकि जिन्हें असत्य बोलने की आदत होती है वे ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। ना उनके आरोप कभी टिक पाए, न ये नेता कभी टिक पाए हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो भारत के लिए गर्व की और मुस्कुराने की बात है।

उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, मुझे याद नहीं कि राहुल गांधी पिछली बार कब मुस्कुराये थे। वह 31 जुलाई 2025 को चार बजकर 20 मिनट पर मुस्कुराये थे। जब भारत ने किसी देश के आगे झुकने से मना कर दिया था। किसी ने भारत को तल्खी में डेड इकोनॉमी (मृत अर्थव्यव्यवस्था) कहा था। उन्होंने कहा कि भारत डेड इकोनॉमी नहीं, बल्कि डोमिनेटिंग (दबदबा रखने वाली) इकोनॉमी है।

उन्होंने वोट चोरी के आरोपों पर राहुल पर पलटवार करते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि इनकी प्रोग्रामिंग अंकल सैम (अमेरिका सरकार) और अंकल सोरोस (जॉर्ज सोरोस) ने की है। इनमें अंकल सैम का सिम कार्ड और अंकल सोरोस का सिम कार्ड है। उधर से टाइप होता है और इधर से टेलीकास्ट होता है। ठाकुर ने भारत में डेटा सेंटर के लिए बजट प्रस्ताव में 20 साल के लिए कर अवकाश का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे भारत में निवेश आएगा, लेकिन राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं।

सरकार ने अमेरिका के सामने समर्पण किया, भारत माता को बेच दिया : राहुल

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बुधवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पूरी तरह समर्पण कर दिया है और उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया है।

उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का समझौता करने को विवश हुए क्योंकि अमेरिका ने उनकी गर्दन पकड़ रखी है। कांग्रेस नेता ने टोका-टाकी के बीच यह भी कहा कि भारत-अमेरिका समझौते में देश के किसानों के हितों को कुचला गया, जैसा आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया और आगे भी कोई नहीं करेगा। कांग्रेस नेता ने मोदी और सरकार पर निशाना साधते हुए अमेरिका में एक भारतीय उद्योगपति के खिलाफ दर्ज मामले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित प्रकरण का उल्लेख किया, जिस पर पीठासीन सभापति ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि यह रिकॉर्ड में शामिल नहीं होगा।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें उन आरोपों को सत्यापित करना चाहिए, जिस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि वह इसके लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने कहा, मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में क्या हुआ। अगर हम इंडिया गठबंधन (की सरकार में) अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे होते, तो हम साफ़ करते कि इस पूरे समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण पूंजी भारतीय डेटा है। अगर डॉलर को सुरक्षित रखना है, तो उसे यह मानना होगा कि भारतीय डेटा रणनीतिक पूंजी है और किसी भी चर्चा को बराबरी पर होना चाहिए, मालिक और नौकर की तरह नहीं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता और अमेरिका अपने किसानों की रक्षा करेगा, वहीं हम अपने किसानों की रक्षा करेंगे।

केंद्रीय करों के हिस्सेदारी में से किसी राज्य का हिस्सा नहीं घटाया : सीतारमण

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को केंद्र से उनकी कर हिस्सेदारी का हस्तांतरण नहीं होने संबंधी कुछ विपक्षी सांसदों के आरोपों को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि सरकार ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में से किसी राज्य का हिस्सा नहीं घटाया है।

सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने बजट में पांच मेडिकल क्लस्टर, पांच मेगा औद्योगिक पार्क, बुजुर्गों के देखभाल के लिए पेशेवरों को तैयार करने जैसी कई घोषणाएं की हैं जिनसे लाखों रोजगारों का सृजन होगा। हम पर आरोप है कि हम राज्यों की 41% कर हिस्सेदारी का हस्तांतरण नहीं करते। मैं आश्वासन देती हूं कि हमने केंद्रीय करों में राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी में से किसी राज्य का हिस्सा नहीं घटाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने 2018-19 से 2022-23 तक राज्यों की कर हिस्सेदारी का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि केंद्र से राज्यों को मिलने वाला यह धन आयोग की सिफारिश से मेल खाता है और इसमें कोई कमी नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में राज्यों को कुल कर हस्तांतरण 25.44 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 2.07 लाख करोड़ अधिक होगा। संविधान ने केंद्र को उपकर और अधिशेष लगाने का अधिकार दिया है और विभाज्य पूल में वह शामिल नहीं होता है, इसलिए राज्यों की कुल कर हिस्सेदारी की बात करते समय उपकर और अधिशेष संबंधी आरोप अनुचित हैं।

बंगाल में बम चलता है कानून नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि बंगाल में बम चलता है, कानून नहीं। सदन में विपक्षी सदस्यों के शोर-गुल के बीच, उन्होंने राज्य में महिलाओं के साथ हुई हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि तृणमूल सरकार कानून-व्यवस्था को बेहतर करने के बजाय दोष महिलाओं पर मढ़ रही है। वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री एक महिला होते हुए भी बोल रही हैं कि अगर महिला, विशेष रूप से लड़की हो तो रात्रि के समय बाहर नहीं जाओ। आप कानून-व्यवस्था को बेहतर नहीं कर रहे हैं, मगर महिला के उपर दोष डालते जा रहे हैं। उन्होंने दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना का भी जिक्र किया।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक

विचार को 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का किया गया गठन

नई दिल्ली, एजेंसी

- समिति में दोनों सदनों के सदस्य, प्रावधानों की समीक्षा के बाद रिपोर्ट करेगी प्रस्तुत

उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक बनाने का प्रस्ताव करने वाले विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक (वीबीएसए) पर गौर करने के लिए संसद में 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व बीजेपी सांसद डी. पुरंदेश्वरी करेंगी।

लोकसभा सचिवालय द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस समिति में दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं और यह प्रस्तावित कानून के प्रावधानों की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। संसद में वीबीएसए विधेयक को शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया गया था। यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा नियामक ढांचे में व्यापक बदलाव करने का उद्देश्य रखता है। प्रस्तावित कानून का लक्ष्य विभिन्न मौजूदा नियामकों को एक ही व्यापक संस्था से बदलना और मान्यता, वित्त पोषण और मानक निर्धारण की जिम्मेदारियों को अलग करना है। सरकार ने कहा था कि विपक्षी दलों द्वारा संघवाद, संस्थागत स्वायत्तता और शक्तियों के केंद्रीकरण से जुड़ी चिंता जताने के मद्देनजर परामर्श के लिए वह संयुक्त समिति को भेजना चाहती है।

एअर इंडिया विमान दुर्घटना जांच रिपोर्ट दाखिल करे केंद्र

- केंद्र ने कहा- एएआईबी जांच अंतिम चरण में, कुछ जांच विदेश में किए जाने की जरूरत

नई दिल्ली, एजेंसी

उच्चतम न्यायालय ने 12 जून, 2025 को एअर इंडिया विमान दुर्घटना के मामले में बुधवार को केंद्र से अब तक अपनाए गए प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल पर संक्षिप्त रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अदालत ने यह निर्देश तब दिया जब उसे सूचित किया गया कि हादसे की जांच विमान दुर्घटना जांच बोर्ड (एएआईबी) द्वारा अंतिम चरण में है।

लंदन जा रही एअर इंडिया की बोइंग 787-8 उड़ान एआई171 गुजरात के अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 241 यात्री और चालक दल समेत 260 लोग मारे गए। दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई थी। बुधवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि एएआईबी जांच अंतिम चरण में है और कुछ जांच विदेश में किए जाने की जरूरत है। मेहता केंद्र और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की तरफ से अदालत में पेश हुए। शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि मामले पर तीन संबंधित याचिकाओं को व्यापक सुनवाई के लिए तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जा सकता है। पीठ का शुरू में विचार था कि एएआईबी जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में उसके समक्ष प्रस्तुत की जाए।

एसआईटी के समक्ष पेश हों पूर्व टीडीबी सचिव

शबरिमला सोना चोरी का मामला

उच्चतम न्यायालय ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) की पूर्व सचिव को शबरिमला सोना चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया और उनकी अग्रिम जमानत अवधि भी बढ़ा दी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और एससी शर्मा की पीठ ने पूर्व टीडीबी सचिव एस जयश्री को गिरफ्तारी से दी गई राहत को बढ़ाते हुए उनसे मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा। न्यायालय ने कहा, प्रतिवादी केरल राज्य के जवाबी हलफनामे के अनुच्छेद 16 में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ता को निर्देश देते हैं कि वह आगे की पूछताछ के लिए 18 फरवरी, 2026 को दोपहर 12 बजे एक बार फिर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो। पूर्व में दी गई अंतरिम सुरक्षा अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगी। इसने मामले को 20 फरवरी के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने 18 दिसंबर, 2025 को जयश्री की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करते हुए, उन्हें 8-9 जनवरी को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्ति की परतों से सोने की चोरी से संबंधित मामले में चौथी आरोपी जयश्री, 2019 में टीडीबी की सचिव थीं।

यूएपीए पर रिपोर्ट दाखिल करे एनआईए

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को निर्देश दिया है कि वह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा और अशांति से संबंधित मामले में आतंकवाद से जुड़े कठोर प्रावधानों वाले गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के इस्तेमाल का औचित्य स्पष्ट करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करे। पश्चिम बंगाल सरकार की अपील का निस्तारण करते हुए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राज्य सरकार को मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में एनआईए की जांच के खिलाफ अपनी शिकायतों के साथ उच्च न्यायालय में जाने के लिए भी कहा।

हिमंत से जुड़ी याचिका होगी सूचीबद्ध

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को चार लोगों द्वारा दायर एक और याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के खिलाफ राज्य में मुसलमानों को निशाना बनाने वाले कथित नफरती भाषणों के मामले में निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और सीपीआई नेता एनी राजा की एक अलग याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी। इसमें एक वायरल वीडियो को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। वीडियो में हिमंत को मुस्लिमों पर राइफल से गोली चलाते हुए दिखाया गया था।

वर्ल्ड ब्रीफ

फिलीपींस में जहाज डूबने से मरने वालों की संख्या 52 हुई

फिलीपींस। फिलीपींस के बेसिलन प्रांत के पास यात्री-मालवाहक जहाज 'त्रिशा कर्स्टन 3' के डूबने से 52 लोगों की मौत हो गई है। फिलीपीन कोस्ट गार्ड (पीसीजी) ने तकनीकी गोताखोर टीमों के चल रहे प्रयासों का हवाला देते हुए बताया कि गोताखोरों ने मंगलवार तड़के बालुक-बालुक द्वीप के पास खोज और बचाव अभियान के दौरान एक और शव बरामद किया। कुल मिलाकर 316 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि बचाव दल अभी भी शेष पीड़ितों की तलाश में जुटे हैं। यह जहाज 26 जनवरी की रात बेसिलन से लगभग एक समुद्री मील की दूरी पर डूब गया था, जिसमें 332 यात्री और चालक दल के 27 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने कहा कि डूबने का संभावित कारण तकनीकी खामी थी।

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने में सिंगापुर में भारतीय को सजा

सिंगापुर। सिंगापुर की एक अदालत ने बुधवार को भारतीय मूल के एक व्यक्ति को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और एक सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने के आरोप में 14 सप्ताह की जेल की सजा सुनाई। चैनल न्यूज एशिया (सीएनए) की रिपोर्ट के अनुसार 36 वर्षीय विकनेस्वरन वी मोगनावल ने धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के अधिनियम के तहत एक आरोप और एक लोक सेवक के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने के दूसरे आरोप में दोषी होने की बात स्वीकार कर ली है। वह इसलिए नाराज था क्योंकि उसके पड़ोसी के बच्चे अक्सर उसके अपार्टमेंट के पास वाले साझा गलियारे में खेलते थे। उसकी पड़ोसी अपने पति, तीन बच्चों, सास, बहन और एक नौकरानी के साथ वहीं रहती थी।

तनाव कम करने के लिए यूनान और तुर्किए के नेता करेंगे वार्ता

अंकारा। यूनान के प्रधानमंत्री क्यारियाकोस मित्सोताकिस बुधवार को तुर्किए की यात्रा के लिए रवाना हुए, जहां दोनों देशों के बीच वार्ता होने की उम्मीद है। यह यात्रा ऐसे समय में संवाद बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा है जब दोनों प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। वरिष्ठ मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आने वाले मित्सोताकिस तुर्किए के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात करेंगे। यह वार्ता उच्च स्तरीय सहयोग परिषद के तहत एक पहल है जिसे नाटो के दोनों सहयोगियों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। यूनान और तुर्किये के बीच समुद्री सीमाओं, साइप्रस और पूर्वी भूमध्य सागर में 'ड्रिलिंग' अधिकारों सहित कई मुद्दों पर मतभेद बना हुआ है।

श्रीलंकाई सांसद की हत्या के मामले में 12 को मौत की सजा

कोलंबो, एजेंसी

● बेगमपुर इलाके में हुआ हादसा पुलिस ने दर्ज किया मामला

श्रीलंका की गम्पाहा हाईकोर्ट ने बुधवार को वर्ष 2022 में तत्कालीन सांसद अमरकीर्ति अथुकोराला और उनके सुरक्षा अधिकारी की हत्या के मामले में 12 व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। यह फैसला एक लंबी सुनवाई के बाद आया है, जिसमें इन हत्याओं के संबंध में कुल 42 लोगों को आरोपित किया गया था।

मौत की सजा के अलावा, अदालत ने चार अन्य व्यक्तियों को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। अन्य 23 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार, मई 2022 में देशव्यापी अशांति के दौरान सांसद और उनके सुरक्षा अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों की एक आक्रोशित भीड़ पर उस समय गोलियां चला दी थीं, जब वे उनके वाहन को रोक रहे थे। इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसी दिन बाद में सांसद और उनके सुरक्षाकर्मी पास की एक इमारत के अंदर मृत पाए गए थे।

साइबर ठगों को सिस्टम का साथ

डिजिटल 'डकैती'

डिजिटल अरेस्ट के जरिए 54,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की ठगी को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डकैती करार दिया है। यह निराशाजनक ही है कि साइबर ठगी यह तरीका कई वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन देश का गृह विभाग इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। रिकॉर्ड के अनुसार देश में डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं का इतिहास करीब पांच साल पुराना हो चुका है। साल दर साल इन घटनाओं में बेहद तेज वृद्धि हुई है। इस बीच सबसे ज्यादा चिंताजनक यह है कि ठगी के कुछ मामलों में बैंक और टेलीकॉम अफसरों की साठगांठ भी सामने आई है। डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं में अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस की कामयाबी की दर भी बेहद मामूली है। इसके साथ यह भी सवाल उठने लगे हैं कि देश में डिजिटल क्रांति पर जोर देने के साथ लोगों को ठगी से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं।

डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत

- लोगों को वीडियो कॉल कर डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी के मामले 2021 में आने शुरू हुए और बाद में तेजी से इनकी संख्या बढ़ी।
- डिजिटल अरेस्ट में मनोवैज्ञानिक दबाव और वीडियो विजुअल्स की मदद ली गई जो जामतारा जैसे ठगी के केंद्रों से विकसित हुआ।
- भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 40,000 केस दर्ज किए गए थे जो 2024 तक बढ़कर 1.23 लाख से अधिक हो गए।
- नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार 2024 में तीन गुना वृद्धि हुई, शुरू के 4 महीनों में ही 120.30 करोड़ की ठगी हुई।

अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और तकनीक

- जांच में पाया गया कि ठग गिरोहों के तार दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों जैसे कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से जुड़े हैं।
- हाल के वर्षों में अपराधियों ने एआई का उपयोग करके पुलिस अधिकारियों की आवाज और चेहरे की नकल करनी शुरू की है।

बैंक अधिकारियों की साठगांठ

- दिल्ली में येस बैंक के दो अफसर गिरफ्तार किए गए, जिन्होंने फर्जी खाते खोले ताकि पैसे को लाउंडर किया जा सके।
- कमीशन लेकर फर्जी खाते खोलने पर हैदराबाद और बेंगलुरु में एयू स्मॉल फाइनेंस, बंधन बैंक शाखा प्रबंधक पकड़े गए।
- तेलंगाना में ऑपरेशन इनसाइडर के तहत कई बैंक अफसर पकड़े गए जो खाते खोलकर अपराधियों की मदद कर रहे थे।
- वोडाफोन के एरिया सेल्स मैनेजर ने साइबर ठगों को 21,000 सिम मुहैया कराए, जिसे दिल्ली में सीबीआई ने गिरफ्तार किया।

हैरतअंगेज मामले

- चेन्नई में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्व केंद्रीय सचिव पद्म भूषण सम्मानित टी. रामासामी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने 57 लाख की ठगी की।
- अगस्त 2024 में ठगों ने पद्म भूषण से सम्मानित वर्धमान ग्रुप के एसपी ओसवाल को सीबीआई अफसर बनकर डिजिटल अरेस्ट किया और 7 करोड़ ठग लिए।
- चंडीगढ़ में रिटायर्ड कर्नल और उनकी पत्नी से 3.4 करोड़ रुपये की ठगी हुई।

डिजिटल क्रांति में सुरक्षा की कमी

- भारत का पहला व्यापक डिजिटल कानून डिजिटल क्रांति के कई वर्षों बाद आया। इसके नियम अभी भी पूरी तरह लागू होने की प्रक्रिया में हैं। इस देरी ने ठगों को बड़ा अवसर मुहैया कराया।
- टेलीकॉम और बैंकिंग कर्मचारी ही सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार कर रहे हैं, जो सिस्टम की बड़ी कमजोरी है। रिजर्व बैंक ने भी स्वीकार किया है कि म्यूल खाते खोलने के पीछे साठगांठ है।
- ठग अत्याधुनिक एआई और डीपफेक उपयोग कर रहे हैं जबकि देश के कई राज्यों में साइबर पुलिस के पास पुराना बुनियादी ढांचा है और वह विशेषज्ञों की भारी कमी से जूझ रही है।

आपसी मतभेदों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखे भारत

दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता के बाद चीन ने दिया जोर

बीजिंग, एजेंसी

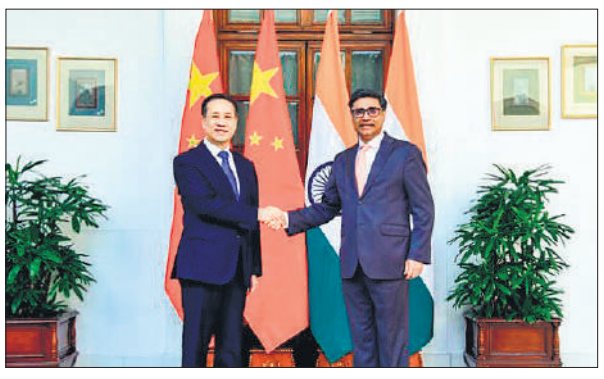

भारत ने संवेदनशील मुद्दों पर चिंता जताई

इस वार्ता पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति की समीक्षा की और लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाकर तथा संवेदनशील मुद्दों पर चिंताओं को दूर करके संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। जायसवाल ने संवेदनशील मुद्दों के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन समझा जाता है कि भारतीय पक्ष दुर्लभ पृथ्वी खनिजों से संबंधित चीन के निर्यात नियंत्रण उपायों को लेकर चिंतित है। मिसरी और झाओक्सू की वार्ता पर भारतीय पक्ष की ओर से जारी बयान में कहा गया कि चर्चा मुख्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और पुनर्निर्माण में हालिया प्रगति तथा आगे संपर्क बढ़ाने के उपायों पर केंद्रित रही। दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों की समग्र प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

चीन के विदेश मंत्रालय ने नR दिल्ली में भारत के साथ मंगलवार को हुई रणनीतिक वार्ता पर मंगलवार को कहा कि दोनों देशों को अपने संबंधों को रणनीतिक एवं दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, साथ ही मतभेदों को उचित तरीके से सुलझाना चाहिए और सहयोग बढ़ाना चाहिए। विदेश सचिव विक्रम मिसरी और उनके चीनी समकक्ष मा झाओक्सू ने भारत-चीन रणनीतिक वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई।मा झाओक्सू भारत में 'ब्रिक्स' शेरपा बैठक में भाग लेने आए हैं।

चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से मिसरी और झाओक्सू के बीच बातचीत पर कहा गया कि दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिति, दोनों देशों की आंतरिक एवं बाहरी नीतियों, साझा हितों से जुड़े क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों तथा चीन-भारत संबंधों पर मित्रतापूर्ण, स्पष्ट और गहन संवाद किया। दोनों पक्षों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति में जटिल और गहरे बदलावों को देखते हुए भारत और चीन को मिलकर काम करना चाहिए तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बनी महत्वपूर्ण समझ को गंभीरता से लागू करना चाहिए। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं के बीच बनी समझ के अनुसार, दोनों देशों को यह रणनीतिक धारणा बनाए रखनी चाहिए कि भारत और चीन प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि सहयोगी साझेदार हैं और दोनों एक-दूसरे के लिए विकास का अवसर हैं, खतरा नहीं।

चीन ने कहा कि दोनों देशों को आपसी विश्वास को मजबूत करना चाहिए, सहयोग बढ़ाना चाहिए, मतभेदों को सही तरीके से सुलझाना चाहिए और संबंधों को स्थिर एवं सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। दोनों पक्षों ने 2026 और 2027 में ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान एक-दूसरे के कार्यों का समर्थन करने पर सहमति जताई। इसके अलावा दोनों पक्षों ने बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका, 'ग्लोबल साउथ' में एकता एवं सहयोग को मजबूत करने, अंतरराष्ट्रीय न्याय एवं निष्पक्षता की रक्षा करने, बहुध्रुवीय विश्व के लिए मिलकर काम करने तथा एशिया और विश्व में शांति एवं विकास में योगदान देने पर सहमति जताई।

बीजिंग में भारत और अमेरिका के राजदूतों की मुलाकात

बीजिंग। चीन में भारत के राजदूत प्रदीप रावत और उनके अमेरिकी समकक्ष डेविड पर्ड्यू ने बीजिंग में मुलाकात की और अमेरिका-भारत संबंधों एवं साझा हितों पर चर्चा की। पर्ड्यू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों पर घनिष्ठ सहयोग और क्वाड की भागीदारी के माध्यम से अमेरिका-भारत संबंध वास्तविक परिणाम देते हैं। उन्होंने कहा, अपने मित्र राजदूत रावत से मिलकर हमारी साझा रुचियों पर चर्चा करना हमेशा ही बहुत अच्छा अनुभव रहता है। दिसंबर के बाद से यह उनकी दूसरी बैठक है। रावत, पर्ड्यू और चीन में जापानी राजदूत केंजी कानासुगी ने पिछले साल दिसंबर में अमेरिकी दूतावास में मुलाकात की थी।

बांग्लादेश में आम चुनाव आज, 50% से ज्यादा मतदान केंद्र संवेदनशील

● सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, बॉडी कैमरे से लैस पुलिसकर्मी तैनात

ढाका, एजेंसी

बांग्लादेश में बृहस्पतिवार को होने जा रहे आम चुनाव के लिए आधे से अधिक मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से 90 प्रतिशत मतदान केंद्र सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगे। राजधानी ढाका में बॉडी कैमरों से लैस पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग की सुरक्षा प्रणाली जोखिम मूल्यांकन पर आधारित है। निर्वाचन आयुक्त अबुल फजल मोहम्मद सनाउल्लाह ने मंगलवार देर रात संवाददाता सम्मेलन में कहा, स्थानीय स्तर पर संवेदनशीलता के आकलन के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कहा कि इन चुनाव में देश के चुनावी इतिहास में कानून प्रवर्तन कर्मियों की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती और प्रौद्योगिकी का सबसे व्यापक उपयोग देखने को मिलेगा। सनाउल्लाह ने कहा कि निर्वाचन आयोग को उम्मीद है कि कानून प्रवर्तन एजेंसी मतदान के दौरान और चुनाव के बाद मतदाताओं के लिए शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करेंगी।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति से काफी हद तक संतुष्ट है और पहले की तुलना में हम अब बेहतर स्थिति में हैं। उनकी यह टिप्पणी पुलिस महानिरीक्षक बहारुल आलम के उस बयान के कुछ देर बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश भर में लगभग 43,000 मतदान केंद्रों में से 24,000 मतदान केंद्र उच्च या मध्यम जोखिम वाले मतदान केंद्र पाए गए हैं।

आम चुनाव की पूर्व संध्या पर ढाका में मतपेटियां तैयार करता एक कर्मचारी।

मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात के बीच

बांग्लादेश में एक जटिल 84 सूत्री सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह के साथ आम चुनाव हो रहे हैं। मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के बीच है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को पिछले साल भंग कर दिया था और पार्टी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। बांग्लादेश में बृहस्पतिवार को संसदीय चुनाव होंगे।

भारत-पाकिस्तान के बीच मार गिराए गए थे 10 विमान : ट्रंप

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा दोहराया कि उन्होंने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को टैरिफ की धमकी देकर रोक दिया था जो परमाणु युद्ध में बदल सकता था। उन्होंने कहा, इस संघर्ष में उनके हस्तक्षेप करने तक 10 विमान मार गिराए गए थे।

ट्रंप ने मंगलवार को एक साक्षात्कार में कहा, मैंने आठ युद्ध रुकवाए। इनमें से छह टैरिफ के कारण सुलझे। जैसे भारत और पाकिस्तान। मैंने कहा कि अगर आप यह युद्ध नहीं रोकते हैं तो मैं आप पर टैरिफ लगा दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मारे जाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, उन्होंने पूछा कि युद्ध का टैरिफ से क्या लेना-देना। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था, ट्रंप ने हमें लड़ाई रोकने के लिए राजी करके कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई।

पेजेश्कियान ने प्रदर्शनों पर खूनी कार्रवाई के पीड़ितों से माफी मांगी

दुबई, एजेंसी

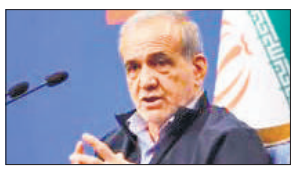

● देशव्यापी प्रदर्शनों पर पश्चिमी देशों के दुष्प्रचार की निंदा की

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देशव्यापी प्रदर्शनों और उसके बाद हुई खूनी कार्रवाई से पीड़ित सभी लोगों से बुधवार को माफी मांगी। हालांकि, राष्ट्रपति ने प्रदर्शनों को लेकर फैलाए कथित पश्चिमी दुष्प्रचार की भी निंदा की।

पेजेश्कियान ने कहा कि वह प्रदर्शनों और उनके खिलाफ कार्रवाई के दौरान हुए लोगों के गहरे दुख को समझते हैं लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर यह स्वीकार नहीं किया कि इस रक्तपात में ईरानी सुरक्षा बलों की भूमिका थी। उन्होंने कहा, हम जनता के सामने शर्मिंदा हैं और इन घटनाओं में जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। हम जनता से टकराव नहीं चाहते। पेजेश्कियान ने यह भी जोर देकर कहा कि उनका देश परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा और वह किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं।

उनकी यह टिप्पणी ईरान की 1979 की इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में आई। ईरान इस समय अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत के दौर में है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि कोई परमाणु समझौता हो पाएगा या नहीं। ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए एक और विमानवाहक पोत भेजने की धमकी दी है। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कई महीनों से ईरान के परमाणु भंडार का निरीक्षण और सत्यापन करने में असमर्थ रही है।

ट्रंप के अलावा किसी ने नहीं कहा रूस से तेल खरीदना बंद करेगा भारत

● लावरोव ने कहा- रूस भारत के साथ संबंधों को लेकर हरसंभव प्रयास करने को तैयार

मास्को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी ने भी यह नहीं कहा है कि भारत, रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को देश की संसद में यह बात कही। रूस ने अमेरिका पर भारत और अन्य देशों को उससे तेल खरीदने से रोकने का प्रयास करने का आरोप लगाया था, जिसके दो दिन बाद लावरोव की यह टिप्पणी आई है।

रूस का कहना है कि वाशिंगटन टैरिफ, प्रतिबंध और सीधे रोक सहित कई तरह के दबावपूर्ण कदम उठा रहा है। लावरोव ने बुधवार को स्टेट ड्यूमा (निचले सदन) में एक सांसद के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, आपने उल्लेख किया कि ट्रंप ने भारत की रूस से तेल न खरीदने की सहमति की घोषणा की है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी अन्य भारतीय नेता से ऐसा कोई बयान नहीं सुना है। लावरोव ने उल्लेख किया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में शेरपाओं की पहली बैठक में कहा था कि ऊर्जा सुरक्षा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में से एक होगी, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शामिल होने की उम्मीद है। भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा।

लावरोव ने कहा कि दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा ने मॉस्को और नई दिल्ली के बीच संबंधों को समृद्ध किया है।

गलत बाल काटने पर मुआवजा राशि दो करोड़ से घटाकर 25 लाख की

● सुप्रीम कोर्ट ने पलटा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल के सैलून में गलत बाल काटने पर एक महिला को दी जाने वाली मुआवजा राशि को दो करोड़ रुपये से घटाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, बेशक सेवा में खामी सिद्ध हुई है, फिर भी उपभोक्ता विवादों में मुआवजा सिर्फ शिकायतकर्ता की मांग या हठ पर तय नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति बिंदल ने फैसले में कहा, दावा जब करोड़ों रुपये का हो तो मुआवजा देने के लिए कुछ ठोस सबूत पेश करना जरूरी है। मुआवजे का दावा करोड़ों रुपये का था, जिसके लिए यह साबित करना आवश्यक था कि सेवा में कमी के कारण प्रतिवादी को कुछ आर्थिक नुकसान हुआ। इसे केवल दस्तावेजों की फोटोकॉपी पेश करके साबित नहीं किया जा सकता।

यह था मामला

अप्रैल 2018 में प्रबंधन पेशेवर अशना रॉय दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल के सैलून गई थीं। रॉय ने आरोप लगाया कि हेयर स्टाइलिस्ट ने उनके कहने के विपरीत बाल छोटे काट दिए, जिससे उन्हें मानसिक आघात लगा और करियर के अवसरों से हाथ धोना पड़ा। एनसीडीआरसी ने शुरू में उन्हें दो करोड़ रुपये दिए जाने का फैसला सुनाया था।

आज का भविष्यफल

-पं. मनोज कुमार द्विवेदी

आज की ग्रह स्थिति : 12 फरवरी, गुरुवार 2026 संवत-2082, शक संवत 1947 मास-फाल्गुन, पक्ष-कृष्ण पक्ष, दशमी 12.22 तक तत्पश्चात एकादशी।

आज का पंचांग

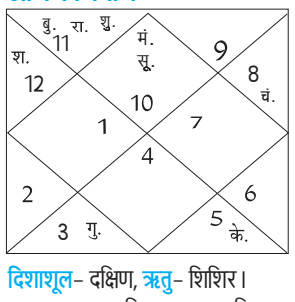

दिशाशूल- दक्षिण, **ऋतु**- शिशिर।
चन्द्रबल- वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ।
ताराबल- अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद, रेवती।
नक्षत्र-ज्येष्ठा 13.42 तक तत्पश्चात मूल।

मेष — आज महिलाओं को अपना व्यवहार संयमित रखना चाहिए। मन में अनेक प्रकार के विचार एक साथ आएंगे। गूढ़ विषयों के अध्ययन के लिये प्रेरित हो सकते हैं। लोगों से अधिक सलाह न लें वरना अनावश्यक भ्रमित हो जाएंगे।

वृष — आज आपके रुके हुए कार्य गतिशील होने की संभावना है। नई तकनीक के प्रति जिज्ञासु रहेंगे। परिश्रम का बेहतरीन परिणाम प्राप्त होगा। आंखों में परेशानी और सिरदर्द की समस्या हो सकती है। जीवनसाथी की भावनाओं को समझें।

मिथुन — आज आपकी सलाह से लोगों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। अचल संपत्ति की खरीदी का विचार मन में आएगा। कार्यक्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। सरकारी जॉब कर रहे लोगों को पदोन्नति मिल सकती है।

कर्क — आज दोपहर के बाद का समय आपके लिए अत्यंत सुखद रहने वाला है। आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। अटके हुए धन का लाभ आपको मिलेगा। आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में आपको सुधार करना पड़ेगा।

सिंह — आज मन में साहसिक कार्य करने की इच्छाशक्ति जागृत होगी। अपनी कमियों को लेकर थोड़े कुंठित हो सकते हैं। अहंकारी व्यवहार के कारण स्वजन आपसे नाराज हो सकते हैं। अधिकारी वर्ग से अपना व्यवहार अच्छा रखें।

कन्या — आज अधीनस्थ कर्मचारी आपसे अत्यधिक प्रसन्न रहने वाले हैं। दूर के स्थानों की यात्रा करने के योग बन रहे हैं। नए कारोबार में आप निवेश कर सकते हैं। मीडिया और प्रकाशन समूह से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

तुला — आज विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपको कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। लोगों के लिए आप प्रेरणा का केन्द्र बनेंगे। घर का वातावरण बहुत ही सुखमय रहेगा। कड़वी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है।

वृश्चिक — आज रचनात्मक कार्यों में आप रुचि लेंगे। परिवार में सभी आपसे अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। किसी मांगलिक कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की प्रशंसा होगी।

धनु — आज पहले की गई गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आर्थिक मामलों को लेकर आप थोड़े परेशान रहेंगे। अपना मन सदैव शान्त रखें। घरेलू खर्च को लेकर आपका बजट गड़बड़ा सकता है। स्वार्थी लोग आपके संपर्क में रहेंगे।

मकर — आज दिन की शुरुआत किसी शुभ खबर से होगी। आपके कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। प्रेमीजन के साथ मतभेद दूर होंगे। गलत बातों में अपना समय बर्बाद न करें। व्यवसाय में आपको अपेक्षा से अधिक धन लाभ होगा। प्रेम संबंधों को पर्याप्त समय देंगे।

कुंभ — आज सरकारी नौकरी कर रहे लोगों का मन काम में नहीं लगेगा। कारोबार में आपको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने के कारण मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। अपने काम के प्रति निष्ठावान रहें। मन में संतुष्टि का भाव रहेगा।

मीन — आज अनर्गल कार्यों में अधिक ध्यान न लगाएं। सहकर्मी आपकी अत्यधिक सहायता करेंगे। व्यवसाय में आकस्मिक धन हानि झेलनी पड़ सकती है। धार्मिक कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा। पिता के किसी निर्णय से आप नाराज हो सकते हैं।

सुडोकू-59

सुडोकू एक तरह का तर्क वाला खेल है, जो एक वर्ग पहेली की तरह होता है। जब आप इस खेल को खेलना सीख जाते हैं तो यह बहुत ही सरलता से खेला जा सकता है। सुडोकू खेल में बॉक्स में 1 नंबर से 9 नंबर तक आने वाले अंक दिए हैं। इसमें कुछ बॉक्स खाली हैं, जिन्हें आपको भरना है। कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। एक सीधी लाइन और एक खड़ी लाइन तथा बॉक्स में नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए।

		1			4		7	
				3				5
2					9			
6	5			7			8	
			1		8			
	1			6			9	2
			7					8
9				4		3		
	8		3			1		

सुडोकू - 58 का हल

6	1	9	2	5	4	7	3	8
7	2	4	3	8	6	1	9	5
3	5	8	1	9	7	6	2	4
1	6	7	5	3	9	4	8	2
2	4	3	6	7	8	9	5	1
8	9	5	4	2	1	3	6	7
4	3	6	8	1	2	5	7	9
9	8	1	7	6	5	2	4	3
5	7	2	9	4	3	8	1	6

भारतीय टीम 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए उत्साहित हैं। हम खेलने के लिए तैयार हैं। हम सभी टीमों पर नजर रखे हैं। हम गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को देख रहे हैं।
–तिलक वर्मा

स्टेडियम

बरेली, गुरुवार, 12 फरवरी 2026

अमृत विचार

www.amritvichar.com

अभिषेक की तबीयत खराब होने से मेजबान टीम चिंतित

नई दिल्ली, एजेंसी

मौजूदा चैंपियन भारत को गुरुवार को यहां होने वाले टी20 विश्व कप मैच में नामीबिया से किसी तरह का खतरा नहीं है लेकिन सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पेट के संक्रमण के कारण मुख्य कोच गौतम गंभीर सहित टीम प्रबंधन चिंतित होगा क्योंकि इससे उसकी योजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में वानखेड़े की चिपचिपी पिच पर बल्लेबाज अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। अब उन्हें फिरोज शाह कोटला की पिच पर आक्रामक खेल दिखाना चाहेगा, जिसे बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन पिच कहा जा सकता है। नामीबिया के खिलाफ भारत का पलड़ा बहुत भारी है जिसकी टीम इसी मैदान पर नीदरलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस तरह से देखा जाए तो भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले महत्वपूर्ण मैच से पहले यह मैच अभ्यास मैच की तरह है। भारत अगर टॉस जीतता है तो वह पहले बल्लेबाजी करना चाहेगा ताकि उसके बल्लेबाजों को पर्याप्त अवसर मिल सके। नामीबिया का

टीम

भारत : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह।

नामीबिया : गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जान बाल्ट, ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), मालन क्रूगर, डायलन लीचर, लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिनक, जान निकोल लोफ्टी-ईटन, विलियम मायबर्ग, जे जे स्मिट, जैक ब्रासेल, मैक्स हेंगो, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, बेन शिकोंगो, रूबेन ट्रम्पेलमैन।

दो दिन बाद अस्पताल से मिली छुट्टी, नामीबिया से खेलने पर संदेह

नई दिल्ली। भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पेट में संक्रमण के कारण दो दिन अस्पताल रहने के बाद छुट्टी मिल गई है, लेकिन नामीबिया के खिलाफ बृहस्पतिवार को यहां होने वाले टी20 विश्व कप क्रिकेट मैच में उनका खेलना संदिग्ध है। मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा ने कहा कि अभिषेक के कल खेलने को लेकर अभी फैसला नहीं लिया गया है। तिलक ने पत्रकारों से कहा जब हम दिल्ली पहुंचे तो वह चेकअप के लिए अस्पताल गया था। उसे आज छुट्टी मिल गई है और वह ठीक है। मैच में अभी भी एक दिन का समय है। उम्मीद है कि कल इस पर फैसला लेंगे।

- संजू सैमसन के लिए लय में लौटने का एक सुनहरा मौका

गेंदबाजी आक्रमण खास नहीं है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रही कोई भी टीम उसको छठी का दूध याद दिला सकती है। नामीबिया के खिलाफ मैच खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन के लिए लय में लौटने का एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार असफलताओं के चलते उन्हें अपनी जगह ईशान किशन के हाथों गंवानी पड़ी, जो इस समय शानदार फॉर्म में हैं। सहायक कोच रयान टेन डोएशे ने कहा संजू अच्छा महसूस कर रहे हैं और चोटिल खिलाड़ी के स्थान पर टीम में अपनी भूमिका को समझ रहे हैं।

अभ्यास सत्र के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव। एजेंसी

आज के मैच

टीम	समय
श्रीलंका-ओमान	पूर्वाह्न 11 बजे
इटली-नेपाल	दोपहर 3 बजे
भारत-नामीबिया	शाम 7 बजे

हाईलाइट

बांगड़ ने कहा- बेखौफ होकर खेलना जारी रखे भारत

नई दिल्ली। पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ ने कहा कि भारत को टी20 विश्व कप के अपने पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ बल्लेबाजों की नाकामी का ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है और उसे अपना बेखौफ रवैया जारी रखना चाहिए जिसके कारण उसने काफी सफलता हासिल की हैं। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए अपने पहले मैच में भारत 13वें ओवर में 77 रन पर छह विकेट खो बैठा था, लेकिन फिर भी उसने अमेरिका पर 29 रन से जीत हासिल की। बांगड़ ने जिओ हॉटस्टार के एक कार्यक्रम में कहा मुझे नहीं लगता कि भारतीय बल्लेबाजों को वानखेड़े में अमेरिका के खिलाफ जो हुआ उसका बहुत अधिक विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि टी20 क्रिकेट में आजकल जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज खेल रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर जोखिम भरा हुआ है।

अनीश ने रैपिड फायर पिस्टल में कांस्य जीता

नई दिल्ली। विश्व चैम्पियनशिप रजत पदक विजेता अनीश भानवाला ने एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता जबकि आठवें दिन कजाखस्तान का दबदबा रहा। अनीश का एशियाई चैम्पियनशिप में यह तीसरा पदक है। एड्रियन कर्माकर ने 50 मीटर राइफल प्रोन जूनियर पुरूष वर्ग में और जूनियर पुरुष 25 मीटर आरएफपी में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के अब 41 स्वर्ण, 19 रजत और 15 कांस्य पदक हो गए हैं जबकि स्पर्धा के दो दिन बाकी हैं। अनीश और आदर्श सिंह क्वालीफाइंग दौर में सातवें और आठवें स्थान पर रहे थे। कजाखस्तान के पूर्व चैम्पियन निकिता चिरयुकिन क्वालीफायर में शीर्ष रहे। फाइनल में आदर्श चौथी सीरिज के बाद बाहर हो गए जबकि अनीश, निकिता व जापान के योशिओका संयुक्त बढ़त पर थे।

दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका की अफगानिस्तान पर रोमांचक जीत

टी-20 विश्व कप : पहले 187 और 17 रनों पर टाई हो गया था मुकाबला

अहमदाबाद, एजेंसी

सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज के साहसिक खेल के बावजूद अफगानिस्तान को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार को यहां रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचे मैच में दूसरे सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा जिससे उसकी सुपर आठ में पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका लगा।

दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद छह विकेट पर 187 रन बनाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 19.4 ओवर में 187 रन पर आउट हो गई। फिर पहला सुपर ओवर भी टाई रहा। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लुंगी एनगिडी ने सुपर ओवर किया जिसमें अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। इसमें अजमतुल्लाह उमरजई का एक छक्का और दो चौके शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका ने फजलहक फारुकी के ओवर में एक विकेट पर 17 रन बनाए। ट्रिस्टन स्टब्स ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर स्कोर बराबर किया। उमरजई दूसरा सुपर ओवर करने के लिए आए जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने डेविड मिलर के दो छक्कों की मदद से 23 रन बनाए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने पहली दो गेंद पर कोई रन नहीं दिया और मोहम्मद नबी को आउट किया। गुरबाज ने इसके बाद लगातार तीन छक्के लगाए लेकिन आखिरी गेंद पर वह आउट हो गए।

इस जीत से दक्षिण अफ्रीका के दो मैच में चार अंक हो गए हैं जबकि अफगानिस्तान की यह लगातार दूसरी हार है। उसे अगले चरण में जाने के लिए न सिर्फ अपने बाकी बचे दोनों मैच जीतने होंगे बल्कि अन्य मैच के परिणाम भी अनुकूल रहने के लिए दुआ करनी होगी। अफगानिस्तान इससे पहला लक्ष्य हासिल करने की स्थिति में था लेकिन लगातार विकेट गंवाने के कारण उसे नुकसान हुआ। उसकी तरफ से गुरबाज ने 42 गेंद पर 84 रन बनाए जिसमें चार चौके और सात छक्के शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए एनगिडी ने 26 रन देकर तीन विकेट लिए। इससे पहले रयान रिकेल्टन ने 28 गेंद पर 61 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें पांच चौके और चार छक्के शामिल हैं। क्विंटन डीकॉक ने 41 गेंद पर पांच चौकों और तीन छक्कों की मदद से 59 रन बनाए। कप्तान एडन मार्करम (05) के जल्दी आउट होने के बाद 114 रन की साझेदारी की।

सुपर ओवर में अफगानिस्तान पर जीत दर्ज करने के बाद जश्न मनाते दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी। एजेंसी

संक्षिप्त स्कोर

दक्षिण अफ्रीका 187/6 (20 ओवर)
- मार्क रयान रिकलेटन 61
- क्विंटन डी कॉक 59

गेंदबाजी : अजमतुल्लाह उमरजई 3-41, राशिद खान 2-28

अफगानिस्तान 187/10 (19.4 ओवर)
- रहमानुल्लाह गुरबाज़ 84
- अज़मतुल्लाह उमरज़ई 22

गेंदबाजी : लुंगी एनगिडी 3-26, केशव महाराज 1-27

पहला सुपर ओवर : टाई

अफगानिस्तान - 6 बॉल में 17/0

दक्षिण अफ्रीका - 6 बॉल में 17/1

दूसरा सुपर ओवर: द. अफ्रीका 4 रन से जीता

दक्षिण अफ्रीका - 6 बॉल में 23/0

अफ़गानिस्तान - 6 बॉल में 19/2

खिलाड़ियों से कहा था कि आखिर तक लड़ना होगा

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टीम के साथी खिलाड़ियों से कहा था कि उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ 'चुनौती' के लिए तैयार रहना होगा और बुधवार को यहां खेला गया यह मैच टी20 विश्व कप के इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक साबित हुआ। इसे शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है। जीत और अंक मिलने के लिए शुक्रगुजार हूं। मार्करम ने कहा आखिरकार सुपर ओवर में आप अपने बेहतर, सबसे आत्मविश्वास से भरे खिलाड़ी को चुनते हैं। पहले ओवर में लुंगी से ज्यादा गलती नहीं हुई, लेकिन फिर उन्होंने अच्छा स्कोर बना लिया। केशव के साथ भी यही कहानी रही। स्पिनर के लिए यह मुश्किल होता है, फिर भी हमने उन पर भरोसा किया। उन्होंने कहा मैंने लड़कों से कहा था कि लक्ष्य ठीक है, लेकिन हमें चुनौती का सामना करना होगा।

वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 30 रनों से परास्त किया

मुंबई, एजेंसी

- शेरफेन रदरफोर्ड की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद गुडाकेश मोती ने की घातक गेंदबाजी

शेरफेन रदरफोर्ड (नाबाद 76) के 42 गेंदों में दो चौकों और सात छक्कों की मदद से सजे आतिशी अर्धशतक और लेफ्ट आर्म स्पिनर गुडाकेश मोती (33 रन पर तीन विकेट) की घातक गेंदबाजी से वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को टी 20 विश्व कप मुकाबले में बुधवार को 30 रन से हराकर अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। वेस्ट इंडीज ने छह विकेट पर 196 रन का मजबूत स्कोर बनाने के बाद इंग्लैंड को 19 ओवर में 166 रन पर निपटा दिया।

इंग्लैंड ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत की और सातवें ओवर तक एक विकेट खोकर 74 रन बना लिए थे लेकिन इसके बाद मोती के सामने उसकी पारी लड़खड़ा गयी और विकेट गंवाती चली गयी। वेस्ट इंडीज के स्पिनरों ने 12 ओवर में 94 रन देकर छह विकेट झटक लिए। फिलिप साल्ट ने 30, जोस बटलर ने 21 और जैकब बेथल ने 33 रन और कप्तान हैरी ब्रूक ने 17 बनाये। सैम करन ने एकतरफा संघर्ष करते हुए नाबाद 43 रन बनाये लेकिन इंग्लैंड की हार को नहीं रोक सके। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की शुरुआत खराब रही और उसने आठ रन तक अपने दोनों ओपनर गंवा दिए। लेकिन शिमरॉन हेटमायर ने 23 और रोस्टन चेज ने 34 रन बनाकर वेस्ट इंडीज को संभाला। दोनों ने 28 गेंदों पर 47 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी के बाद दोनों कुछ रनों के अंतराल में आउट हुए।

रदरफोर्ड ने फिर रोवमन पॉवेल के साथ टीम के स्कोर को 128 रन तक पहुंचाया। पॉवेल 14 रन बनाकर आउट हुए। रदरफोर्ड को इसके बाद जैसन होल्डर के रूप में अच्छा जोड़ीदार मिला। दोनों ने जबरदस्त छक्के लगाते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। होल्डर 17 गेंदों में एक चौके और चार छक्कों की मदद से 33 रन बनाने के बाद आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर आउट हुए। रदरफोर्ड और होल्डर ने पांचवें विकेट की साझेदारी में 32 गेंदों पर 61 रन जोड़े। रदरफोर्ड ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर विंडीज को 196 रन तक पहुंचाया।

टीम के साथ जश्न मनाते वेस्टइंडीज के गुडाकेश मोती। एजेंसी

इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है : अफगानिस्तान के कोच ट्रॉट

अहमदाबाद। अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट ने टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका से दूसरे सुपर ओवर में मिली हार के बाद कहा कि इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका ने क्षेत्ररक्षण में उनकी टीम को कमजोर साबित किया। टी20 विश्व कप के इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक में दक्षिण अफ्रीका ने दो सुपर ओवर के बाद अफगानिस्तान को हराया। ट्रॉट ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा इससे साबित होता है कि हमारे पास कितनी शानदार टीम है। हमारे पास कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ दिन पहले मिली हार के बाद दक्षिण अफ्रीका से करीबी मुकाबला हारना दिल तोड़ने वाला है। हमें कठिन ग्रुप भी मिला है। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ट्रॉट ने कहा कि इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है। उन्होंने कहा टीम को अपने प्रदर्शन पर गर्व होना चाहिये लेकिन कई बार इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है। अब अहम यह है कि हम इसके सकारात्मक पहलुओं को देखें और यह भी प्रयास करें कि जहां गलतियां हुई हैं, उनमें सुधार हो। ट्रॉट ने कहा दक्षिण अफ्रीका की फील्डिंग बहुत अच्छी थी। रन आउट, सीमा पर कैच और रन बचाने के प्रयास। जबर्दस्त फील्डिंग और शायद यही फर्क था। ट्रॉट के कोच रहते अफगानिस्तान पिछले टी20 विश्व कप सेमीफाइनल और 2023 वनडे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। इस विश्व कप के बाद वह टीम से विदा ले रहे हैं लेकिन अभी इस बारे में उन्होंने कुछ कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा टूर्नामेंट खत्म होने के बाद इस पर बात करेंगे। अभी दो अहम मैच खेलने हैं। अभी कुछ और बात करने का समय नहीं है। मैं अभी भी कोच हूं और मुझे यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में यूएई के खिलाफ हम अच्छा खेलें।

एलिस-जम्पा की मारक गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को हराया

कोलंबो, एजेंसी

ऑस्ट्रेलिया ने तेज गेंदबाज नाथन एलिस (12 रन देकर चार विकेट) और लेग स्पिनर एडम जम्पा (23 रन देकर चार विकेट) के शानदार प्रदर्शन से बुधवार को यहां ग्रुप बी मैच में आयरलैंड पर 67 रन की जीत के साथ आईसीसी टी20 विश्व कप में अपना अभियान शुरू किया। एलिस ने अपने शुरूआती स्पैल में तीन विकेट झटककर जीत की लय तय की। उन्होंने शीर्ष क्रम को पवेलियन भेजा तो वहीं जम्पा ने मध्य और निचले क्रम पर कहर बरपाया जिससे आयरलैंड की पारी 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 16.5 ओवर में नौ विकेट 115 रन पर खत्म हुई।

आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग एक गेंद खेलने के बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए और फिर बल्लेबाजी करने नहीं उतरे।

ऑस्ट्रेलिया ने तेज गेंदबाज नाथन एलिस।

आयरलैंड के लिए जॉर्ज डॉकरेल ने सर्वाधिक 41 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने धीमी पिच पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए हरफनमौला मार्कस स्टोइनिस (45 रन) और मैथ्यू रेनशॉ (37 रन) के बीच पांचवें विकेट के लिए 61 रन की अहम साझेदारी की मदद से छह विकेट पर 182 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। आयरलैंड की टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए पावरप्ले में चार विकेट गंवा दिए थे। मिचेल मार्श ग्रोइन चोट के कारण टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गए हैं। पैट कमिंस और जोश हेजलवुड भी चोट के कारण बाहर हैं जबकि मिचेल स्टार्क संन्यास ले चुके हैं तो एलिस ने मुख्य तेज गेंदबाज के तौर पर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। एलिस ने इस तरह तीन ओवर के शुरूआती स्पैल में नौ रन देकर तीन विकेट लिए। उन्होंने रोस एडेयर (12), कर्टिस कैम्फर (04), बेन कालिट्ज (02) को आउट किया। फिर जम्पा ने गेरेथ डेलानी (11), लोरकान टकर (24), डॉकरेल और मार्क एडेयर (12) के विकेट झटके। आयरलैंड हालांकि 100 रन का स्कोर पार करने में कामयाब रहा। आखिर में एलिस अपना अंतिम ओवर करने के लिए आए और बैरी मैकार्थी (02) को आउट करके मैच खत्म किया।

ग्रीनपार्क या इकाना में होगा रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल

देहरादून। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पिच क्यूरेटर ने उत्तराखंड में देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का दौरा करने के बाद मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में यहां के मैदान की हालत को बेहद निराशाजनक बताया है। इससे यहां रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल की मेजबानी को लेकर झटका लगा है।

क्यूरेटर राकेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि स्टेडियम की पिच और आउटफील्ड का स्तर इतना खराब है कि यहां सेमीफाइनल जैसा महत्वपूर्ण मुकाबला आयोजित नहीं किया जा सकता। निरीक्षण टीम के अनुसार, ग्राउंड का रखरखाव मानकों के अनुरूप नहीं है। सूत्रों की मानें तो बीसीसीआई अब इस सेमीफाइनल को कानपुर के ग्रीनपार्क या लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित करने पर विचार कर रहा है।

तैयारी पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने कहा- मुकाबले के प्रति टीम बेहद गंभीर

भारत के खिलाफ अलग मानसिकता के साथ खेलेंगे

कोलंबो, एजेंसी

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले टी20 विश्व कप मैच को एक आम मैच करार दिया। लेकिन इसके साथ ही कहा कि इस बार उनकी टीम इस मुकाबले में अलग मानसिकता के साथ उतरेगी। पाकिस्तान की टीम नीदरलैंड और अमेरिका को हराने के बाद ग्रुप ए में शीर्ष पर काबिज हो गई है। नीदरलैंड को हराने में उसे संघर्ष करना पड़ा था लेकिन अमेरिका को उसने आसानी से 32 रन से हराया जिसमें फरहान ने एक 41 गेंद में 73 रन की शानदार पारी खेली।

मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में फरहान से भारत के खिलाफ होने वाले मैच के बारे में पूछा गया जो पाकिस्तान सरकार द्वारा बहिष्कार की अपील वापस लेने के बाद अपने

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी को खेला जाएगा।

फरहान ने कहा लगातार दो मैच जीतने और तालिका में शीर्ष पर काबिज होने से आत्मविश्वास मिलता है। अगला मैच भी एक आम मैच जैसा ही होगा। यह पहला अवसर नहीं है जबकि हम उनके खिलाफ खेलेंगे। उन्होंने कहा हम पहले भी उनके खिलाफ खेल चुके हैं लेकिन इस बार हमारी मानसिकता अलग होगी। आपने देखा ही होगा कि शादाब (खान) रन बना रहे हैं, (मोहम्मद) नवाज़ रन बना रहे हैं। उम्मीद है कि आपको उनके खिलाफ हमारा खेल पसंद आएगा। फरहान ने कहा यह एक सामान्य मैच होगा और हम इसे एक अन्य मैच की तरह ही लेंगे। हम यह नहीं सोचेंगे कि यह भारत और पाकिस्तान का मैच है। हम इसे एक सामान्य मैच की तरह ही खेलेंगे।

भारत का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है। उसने हाल में एशिया कप में पाकिस्तान को सभी मैच में हराया था। तब भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि हाल के वर्षों में उनकी टीम के दबदबे को देखते हुए वह अब पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिद्वंद्विता को बराबरी का नहीं मानते हैं। फरहान हालांकि इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं मानता।

मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया

फरहान से जब पूछा गया कि क्या उनके पास भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का सामना करने के लिए कोई विशेष योजना है, तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि जब आप रन बनाते हैं तो आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं। मैं भी बहुत आत्मविश्वास से भरा हूं और जिस तरह से मैंने पिछली दो पारियां खेली हैं, उससे मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं मानता। एशिया कप में हमने जिस तरह से प्रदर्शन किया उसे देखते हुए मुकाबले एकतरफा नहीं थे। हमने आखिर तक डटकर मुकाबला किया था। उम्मीद है कि इस बार भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पाकिस्तान के लगातार दो मैच जीतने से फरहान काफी उत्साहित हैं।